(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] पंचम विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का चौथा दिवस [संख्या 4

बृहस्पतिवार,

11 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक म.पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(राजस्व, वित्त, सिंचाई, कृषि, सहकारिता, खनिज, भेड़ व ऊन, विद्युत, पंचायत, जन स्वास्थ्य एवं पशुपालन-विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न 1

श्री बनवारी लाल।

भेड़ पालन योजना के तहत ऊन की खरीद

11. श्री बनवारीलाल (धौलपुर) व श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भेड़ पालन योजना के तहत किस किस साल में कितनी कितनी ऊन कितनी कितनी धनराशि की किन किन अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा खरीदी गई है ?

(2) क्या यह सच है कि उपरोक्त खरीद में एडवांस दिया हुआ रुपया दबाया है ? यदि हां, तो किस किस पर कितना कितना ? सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा भी नाम है, दोनों का साथ है।

एक माननीय सदस्य : सब जानते हैं कि दोनों साथ हैं।

श्री शंकरलाल : आपको छोड़ेंगे थोड़े ही।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : छंगाणी साहब छोडकर चले गये, कोई तो साथ चाहिये ही साहब।

राज्य मन्त्री, भेड व ऊन (श्री मुंशीलाल महावर) : (1) भेड़ पालन योजना के तहत जो ऊन खरीदी गई, सूची संलग्न है।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : दुबारा से पढ़ दीजिये साहब। सुना नहीं।

श्री मुन्शी लाल महावर : (1) भेड पालन योजना के तहत जो ऊन खरीदी गई, सूची संलग्न है।

(2) जी हां, बकाया मामलों की सूचियां संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्रीराम गोटेवाला : सूची तो संलग्न है लेकिन जिन जिन में बकाया रहा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री मुन्शीलाल महावर : अध्यक्ष महोदय, बकाया राशि एक लाख 70 हजार 570 रुपये है जिनमें से 10123 वसूल हो गये और बाकी के पी.डी.आर. में केसेज चल रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वसूली की कार्यवाही तो जारी है। मुझे जो लिस्ट दी गई है उसमें कई अधिकारियों के नाम हैं जिनकी वजह से बकाया रही है। तो जिनकी गलती की वजह से बकाया रही है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों के नाम दिये गये हैं उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्य को सूची दी है, सारी जो कार्यवाही की गई है, उसमें लिख दी गई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे से पढ़ी नहीं जाती है। कापी जो मुझे दी गई है वह ऐसी दी गई है कि आंखे बचें न आप से और सूखे बचें न बाप से।

श्री मुन्शी लाल महावर : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है उनमें से कई पुलिस में मामले दर्ज हैं, कइयों में विभागीय जांच चल रही है और कई मामले एन्टीकरप्शन में दे रखे हैं और कुछ मामले विभागीय जांच आयुक्त के भी विचाराधीन हैं। सब पर अन्तिम निर्णय होने पर, इन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कब से केसेज पेन्डिंग हैं ?

श्री शंकरसिंह रावत : क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि...

(अश्रव्य)

श्री मुन्शी लाल महावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी माननीय मंत्री महोदय या कोई भी विधान सभा का सदस्य जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, कोई मंशा नहीं रखते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है, साहब।

श्री अध्यक्ष : आ गया, सन्तोष हो गया आपको अब तो।

नेक्स्ट। श्रीमती उषा प्रकाश।

बाण गंगा की बाढ़ से बन्धों की रक्षा

34. श्रीमती उषाप्रकाश (बैर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले में सन् 1975 में बाण गंगा की बाढ़ से कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ था ?

(श्रीमती उषा प्रकाश)

(2) उपरोक्त बाढ से उपरोक्त नदी का तटबन्ध कहां कहां पर टूटा ? अन्य कौन कौन से बान्धों को हानि पहुंची ?

(3) इस तटबन्ध तथा बन्धों की मरम्मत पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है और अब किन किन स्थानों पर मरम्मत का कितना कार्य होना शेष है ?

(4) शेष कार्यों पर अब कब तक कार्य शुरू किया जायेगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) बाण गंगा की बाढ़ से सन् 1975 में प्राय: 17665 हैक्टेयर भूमि प्रभावित हुई थी ।

(2) उपरोक्त बाढ से निम्न स्थानों पर नदी के तट बन्ध टूटे थे–

बाईं ओर	दाईं ओर
झालाटाला	ललता मूंड़िया
गंगारोली	
खरबेरा	
रमासपुर	

इन तट बन्धों के अलावा 12 बांध एवं 3 नहरें टूटीं एवं 24 बान्ध एवं 6 नहरें क्षतिग्रस्त हुई जिनकी सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है ।

(4) वांछित धनराशि की उपलब्धि पर प्रारम्भ किये जा सकेंगे ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्रीमती उषा प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मै इसमें दो जानकारी चाहूंगी वैसे मंत्री महोदय ने जो लेफ्ट एन्ड राइट की बात कही है, उस चक्कर में तो नहीं पड़ती कि कौन राइट है और कौन लेफ्ट है, किन्तु मेरा सवाल तो यह है कि गंगारोली बान्ध टूटा है उसके लिये कब तक फन्ड्स उपलब्ध हो जायेंगे और कब तक रिपेयर करवा देंगे ? अब जो वर्षा आने वाली है ये बान्ध गंगारोली खरबेरा और रमासपुर से वापिस जन जीवन को परेशानी हो जायगी इस लिए मै आपसे पूछना चाहती हूं कब तक तटबन्धन हो जायेंगे और जो बड़े बड़े बान्ध टूटे हैं उनकी रिपेयर कब तक हाथ में लेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, काम तो हाथ में लिये जा चुके हैं और कई जगह काम चल भी रहे हैं। दो दिन पहले भी प्रश्न आया था इन बांधों पर 7–8 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। माननीय सदस्या को मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस आने वाली वर्षा के पहले पहले जितने आवश्यक काम हैं जिनमें पानी नुकसान करता हो, उनको पूरा कर देंगे चाहे वह खरबेरा का बान्ध हो और चाहे गंगारोली का बान्ध हो । जून से पहले पहले हम पूरा कर देंगे ।

श्रीमती उषा प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इन तट बन्धों पर कई जगह उसके कमजोर होने के विषय में गांव वालों ने और हमने रिपोर्ट की है उसके बावजूद टूटने से बचाने के लिए स्थानीय अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया ? हमने लिखित में भी शिकायत की थी, अगर यह सही है तो उस पर आपने क्या एक्शन लिया ?

Page No 4

(5)

श्री हीरा लाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जांच की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। जो आपने लिखित शिकायत की है, उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी मेरे पास आ गई है। लेकिन वह जानकारी पूरी नहीं है इस लिये उसमें और जानकारी चाही है। अगर निश्चित रूप से शिकायत सही है तो एक्शन लिया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार भरतीय (बूंदी) : बाढ़ आये काफी अर्सा हो गया और उसके पहले इन्तजाम करने की कर रहे हैं – क्या कदम उठाया है ऐसे इमर्जेन्ट मामलों के खिलाफ आपने ? हजारों लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। उन अधिकारियों के खिलाफ क्या सख्त कदम उठाया है ? क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे ?

श्री हीरा लाल देवपुरा : माननीय सदस्य को पता है उस क्षेत्र में बाढ़ आई थी और तत्काल काम किया जाने वाला था, वह किया गया और अब तो यह है कि जो काम बचे हैं जिनसे भविष्य में खतरा हो सकता है, जिनकी मुकम्मिल तैयारी नहीं की जा सकी है उनको पूरा करना है।

श्रीमती उषा प्रकाश : (अश्रव्य) पहले कुछ अधिकारियों के लिये हमने कहा है . .

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मैंने स्पष्ट बताया है कि आपने लिखित में शिकायत की है और जिसके खिलाफ शिकायत लिखी है, जांच करवाई जा रही है। प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी से मुझे सन्तोष नहीं था इसलिये पूरी रिपोर्ट मांगी है और उसकी जानकारी की जा रही है। जिस स्तर पर कमी हुई है उस स्तर पर मुझे एक्शन लेने में कोई एतराज नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मेरी सप्लीमेन्टरी का जवाब नहीं आया, अध्यक्ष महोदय, कब प्रिलिमिनरी जांच आई और कब आपने द्वारा जांच करवाई . . .

(व्यवधान)

(जवाब नहीं आने पर)

अध्यक्ष महोदय क्या आपने यह फरमाया है कि मेरे सप्लीमेन्टरी का जवाब नहीं दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : मेरी इजाजत से पूछेंगे तो जवाब दिया जायगा और मेरे क्लोज करने के बाद पूछेंगे तो जवाब नहीं दिया जायगा।

नेक्स्ट। श्री महेन्द्र कुमार।

मछली पकड़ने का ठेका

35. **श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा) :** क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर में इस प्रकार के कितने तालाब हैं जिनमें मत्स्य पालन किया जाता है ?

(2) उक्त तीनों जिलों में ऐसे कितने तालाब हैं जिनमें मछली पकड़ने का कार्य ठेके पर दिया जाता है ? गत पांच वर्षों से अब तक जिलेवार वर्ष के अनुसार तुलनात्मक दृष्टि से सूची बनाकर सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

मंत्री, पशु पालन (श्री शिवचरण माथुर): (1) जिला डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर में कुल 99 विभिन्न श्रेणी के तालाब हैं, जिनमें मत्स्य पालन किया जाता है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त तीनों जिलों में हर वर्ष औसतन 35 जलाशयों का मछली पकड़ने का ठेका दिया जाता है। तुलनात्मक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री महेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करूंगा कि क्या यह बात सही है कि जिन तालाबों का ठेका नहीं दिया गया है, उनकी भी मछली ठेकेदार निकाल कर ले जाते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : यह अलग से प्रश्न है। आपके पास जानकारी हो तो दे दीजिये, जांच करवा लेंगे।

श्री महेन्द्र कुमार : सूची मेरे पास नहीं आई है, साहब।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सूची भिजवा दीजिये, साहब।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दीपंकर

लाडनूं में पत्थरों की खानों में पानी का भराव

36. **श्री दीपंकर (लाडनूं)** : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं शहर जिला नागौर में पत्थर की सैकड़ों खानें हैं जिनको सरकार ने लीज पर दे रखा है और जिनमें मजदूर काम करते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस साल वर्षा ज्यादा होने से ये खानें पानी से भर गयीं और पानी भरे रहने से मजदूर बेकार हो गये है और लीज होल्डर्स खानों का पानी बाहर निकालने की क्षमता नहीं रखते हैं ? अगर हां, तो क्या इन खानों का पानी निकालने के लिए माइनिंग विभाग कोई योजना बना रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि खानें पानी से भरी होने पर भी लीज चालू है और खान के किरायेदार से रकम ली जा रही है ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

राज्य मंत्री, खनिज विभाग (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां। 95 खानें आर. सी. आर. एल. पर दी हुई हैं।

(2) यह सही है कि अधिक वर्षा के कारण लाडनूं तहसील क्षेत्र में कुछ खानों में पानी भर गया है परन्तु पानी भरे भाग को छोड़ कर बाकी भाग में खनन् कार्य चालू है। जहां पानी भरने के कारण कार्य बन्द है वहां कार्यरत मजदूर अन्य जगह कार्य पर चले गये हैं। लीज होल्डर्स खानों का पानी निकालने की क्षमता रखते हैं या नहीं इसकी जानकारी विभाग को नहीं है। विभाग द्वारा पानी निकालने की कोई कार्यवाही नहीं की जाती अलबत्ता विभाग द्वारा मशीनें किराये पर दी जाती हैं जिनके उपयोग से खान मालिक पानी निकालने का कार्य कर सकते हैं।

(श्री जुझार सिंह)

(3) जी हां, सभी खानें रेन्ट-कम-रोयल्टी लीज पर हैं। नियमानुसार इनका किराया अग्रिम लिया जाता है।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, जब खानों में पानी भरना मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं और खानें चालू नहीं हैं तो उनको लीज पर दिया जाना क्या सरकार की निगाह में जायज है ? नम्बर 1। नम्बर 2, आप यह मानते हैं कि कुछ खानों में पानी भरा· · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : चसलाना खान तो नहीं बनने वाली है ?

श्री दीपंकर : जब कि सम्पूर्ण खानें भरी हुई हैं पानी से। मजदूर बाहर बैठे हैं। और लीज होल्डर्स और मजदूरों के बीच में झगड़ा है। उनको काम नहीं मिल रहा है। लीज होल्डर मांगें या न मांगें, अधिकारी को आप भेजते हैं तो क्यों नहीं वहां पर आप मशीनें भिजवाते हैं जिससे पानी निकाला जा सके और मजदूरों को काम मिल सके और वे काम करने लग सकें ?

श्री जुझारसिंह : ये खानें ऐसी हैं कि जो आर.सी.आर.एल. हैं और उस दृष्टि से उनको लीज पर दी हुई हैं जिनका वार्षिक डेड रेन्ट 36 रुपया है और तीन रुपये महीने के हिसाब से है। जितना माल खानों से निकालते हैं तो उसके हिसाब से रोयल्टी चार्ज होती है खानें काम नहीं कर रही हैं तो रोयल्टी पेमेन्ट करने का सवाल ही नहीं है। लीज होल्डर को नुकसान हो रहा है, ऐसी बात नहीं। आपने कहा कि सारी खानों में पानी भरा है तीस खानों में पानी भरा है और वे वर्केबल हैं पर पार्शियल काम होता है। सारे लीज एरिया में साथ साथ काम चलता हो ऐसी बात नहीं। जिनमें पानी भरा हुआ है, उनमें ऐसी भी जगह हैं जहां कि लोग काम कर रहे हैं। डिपार्टमेन्ट की ओर से पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है। कुछ पंप्स हमारे पास उपलब्ध हैं। जो भी उनको किराये पर लेना चाहते हैं उनकी हमारे पास कोई दरख्वास्त नहीं आयी है। उनको पंप्स अवेलेबल कर सकते हैं जिनका किराया उनसे वसूल किया जावेगा।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : हम सबको समझाया जाय कि किस प्रकार से लीज पर दिया जाता है इन खानों को। 95 खानें स्वयं ने देखी हैं ? पानी भी भरा है और काम करने की जगह भी है ? क्या इतने श्योर हैं इस मामले में ? तीसरा प्रश्न, खनन् पट्टे दिये हुए हैं। हाथ से काम करने वाले लोग हैं। सरकार पानी खानों से निकलवाये ताकि मजदूर काम कर सकें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बहुत बड़ा पर्सेन्टेज खानों का है जिनमें पानी भरा हुआ है और फिर भी निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि वर्केबल हैं। यह संभव नहीं है। 30 खानों में पानी भरा हो और वर्केबल हों। क्या आपको रोयल्टी का लास नहीं हो रहा है ? राष्ट्रीय लास नहीं हो रहा है ? 30 खानें वर्केबल नहीं हैं तो 30 पर्सेन्ट तो काम रुका हुआ है। काफी गम्भीर प्रश्न है।

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां भी खानों में काम होता है, जहां भी खनन् होता है खानों में तो ऐसी कोई खान नहीं होती है कि वहां पर खनन् होने पर पानी न आता हो और उस पानी को निकालने की

(श्री जुझार सिंह)
व्यवस्था लीज होल्डर करता है। लीज होल्डर को ही पानी वहां से निकालना होता है। हजारों खानें ऐसी हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनकी भी मंशा यही है कि वहां से पानी निकाला जाय।

श्री जुझार सिंह : सब जगह पर पानी को लीज होल्डर द्वारा अपने आप निकालने की व्यवस्था है। यहां पर ज्यादा पानी खानों में भर गया है। हमारे यहां से किराये पर पम्प अवेलेबल हैं। लीज होल्डर ने किसी ने भी, इसके लिये एप्लाई नहीं किया है। एप्लाई करेंगे तो किराये पर अवेलेबल करवा दिये जावेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नार्मल कन्डीशन्स में खानों में पानी आता है तो उसको निकालने की व्यवस्था की जाती है। लाडनूं में एबनार्मल रेन्स हुई। उन खानों में पानी भर गया, गहराई तक पानी भर गया इसलिये पानी को निकालने की व्यवस्था डिपार्टमेंट से करनी चाहिये।

श्री जुझारसिंह : हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लीज होल्डर यदि इन खानों पर काम नहीं करना चाहता है तो सरेन्डर कर दे। जितना माल निकालेगा उस पर ही तो रोयल्टी देगा। माल नहीं निकालेगा तो सरेन्डर कर सकता है कि काम नहीं हो सकता है।

श्री मोहनराज (बाली) : मंत्री महोदय के उत्तर से एक बात स्पष्ट हुई है वह यह है कि वहां पर पानी भरे हुए होने के कारण माल नहीं निकाल सकते हैं जिससे रोयल्टी नहीं मिलती है। दूसरा, यह भी स्पष्ट हुआ है कि मजदूर बेकार बैठे हैं और खनन नहीं कर रहे हैं। मजदूर वर्ग को मजदूरी नहीं मिलने से लास है और सरकार को रोयल्टी का लोभ है। नियमों के तहत उनको वर्केबल क्यों नहीं बनाते हैं? छोड़ने की बात नहीं है।

श्री जुझारसिंह : उनको मना कौन करता है? सरेन्डर कर दें यदि काम नहीं करते हैं तो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 20 सूत्री कार्यक्रम का सूत्र नं. 1 कि प्रोडक्शन को लोस नहीं पहुंचना चाहिये। आपका दृष्टिकोण यह नजर नहीं आता है। वे तो सरेन्डर कर देंगे।

श्री शंकरलाल (पाली) : लीज एग्रीमेन्ट में कोई शर्त है क्या?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आपने इतनी बात कह दी कि माल नहीं निकालें। देश को कितना बड़ा नुकसान है? मजदूर बेकार बैठे हैं। 20 सूत्री योजना बनायी इसीलिये कि रोजगार मिले और प्रोडक्शन बढ़े। नहीं होता है काम तो नयी योजना बना कर काम करावें जिससे प्रोडक्शन का नुकसान न हो और मजदूर बेकार न बैठे रहें।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : मजदूर बेकार बैठे हैं तो क्या कान्ट्रेक्टर को सरकार बाध्य नहीं कर सकती है? 20 सूत्री कार्यक्रम का क्या पालन है फिर? मजदूर बेकार बैठा रहे और सरकार देखती रहे और कोई ठेकेदार पर इफेक्ट न हो इसलिये पूछ रहे हैं कि यह कौनसा सूत्र है?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष । बहुत देर हो गयी है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एक सवाल। क्या मंत्री महोदय, यह बताने की स्थिति में हैं कि ये खानें जो बन्द हैं उनसे राज्य सरकार को कितना नुकसान हो रहा है और हो रहा है तो उसको रोकने की क्या तदबीर की है ?

श्री दीपंकर : और स्पष्ट कर देता हूं। माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि वह यह फरमा रहे हैं कि जिन खानों में पानी भर गया है, काम करने वाले मजदूर उन्हीं खानों में काम करने लगे हैं, सलेक्टेड एरिया है ये खाने भर गयीं हैं पानी से तो क्या नयी खानें खोदने का पट्टा अलाट किया है ? खानों में कुल कितने मजदूर काम कर रहे हैं और कितने नये मजदूरों को खानों पर लगाया है और कितने बेकार बैठे हैं ? मैं समझता हूं कि आपके पास गलत इन्फार्मेशन है। सैंकड़ों की तादाद में, कम से कम 200/400 मजदूर बेकार बैठे हैं। इसके सिवाय कोई काम नहीं, कोई जरिया नहीं। और सरकार सुनती नहीं। न लीज होल्डर ही सुनता है। उनके पास बाबू आता है तो वे उसको चाय पिला देते हैं। कम से कम आप अपने आदमियों से उन खानों से पानी निकलवाइये। लीज होल्डर से कहें कि उनको काम पर लगायें। आपने मजदूरों की संख्या भी नहीं बतायी, 30 में पानी भरा है और बाकी में क्या काम चल रहा है ? कहां चल रहा है ? इतना पानी भरा हुआ है कि बिलकुल भी जगह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री दीपंकर : मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे इस प्रश्न का।

श्री अध्यक्ष : देना चाहते हैं ?

श्री जुझार सिंह : दे दूं। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं पूरा जवाब दे चुका हूं· · ·

श्री अध्यक्ष : अगर आप चाहते हैं तो दे दीजिए।

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत से मेम्बर्स को वहां की स्थिति का पता ही नहीं है। आर.सी.आर. लीज से मजदूरों का नुकसान नहीं होता है क्योंकि जितने आदमी जो काम करते हैं और जितना माल निकालते हैं उस पर डिपार्टमेन्ट चार्ज करता है। लीज होल्डर्स को नुकसान नहीं है· · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (अश्रव्य)

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को पता तो कुछ है नहीं वहां की स्थिति का· · · ·

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको कितना नुकसान हो रहा है ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : It is a question of privilege. We know more than him about the mines. I have worked with the labour of the mines. माननीय सदस्यों को

Page No 9

(9)

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)
पता नहीं है ! कैसे पता नहीं है। यह सरकास्टिग रिमार्क्स पास कर रहे हैं। आर. सी. आर. बताने के लिए तैयार नहीं है। आप बता दीजिए कि आर. सी. आर. लीज क्या है ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे से ज्यादा जानते हैं और फिर भी आर.सी.आर. लीज के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या होती है। तो इस बात का तो यही नमूना है कि माननीय सदस्य वहां कि स्थिति को नहीं जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दीपंकर : मजदूरों की संख्या बताइये और उनका इलाज बताइये कि उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : Next question.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

गंगानगर जिले में आर.ई.सी. योजना

37. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या आर.ई.सी. द्वारा गंगानगर जिले में कोई योजना बनाई गई ? यदि हां, तो कब और किस किस गांव के लिये किस किस कार्य के लिये ? इनमें कौन कौन सा कार्य पूरा हो गया है ? कृपया मय कार्य दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गंगानगर के ग्राम बीजवायला, गोलू वाला और घमूड़वाली की आबादी क्या है ? क्या यह सही है कि बीजवायला और गोलूवाला में मण्डियां भी हैं, जहां जिनिग और प्रेसिंग के एवं अन्य काफी कारखाने भी हैं ? यदि हां, तो क्या विद्युत् विभाग या आर.ई.सी. द्वारा आज तक उपरोक्त तीनों ग्रामों में और दोनों मंडियों को बिजली देने की कोई योजना बनाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

विद्युत् मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां, एक योजना सन् 1971–72 में हनुमानगढ़ तहसील क्षेत्र के 34 गांवों के विद्युतीकरण के लिए बनाई गई है। योजना के संक्षिप्त विवरण की सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) श्री गंगानगर के ग्राम बीजवायला व घुमड़वाली की आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार क्रमश: 3979 व 2103 है। गोलूवाला ग्राम तहसील सूरतगढ़ की जनसंख्या वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार 2454 है। बीजवायला व गोलूवाला में मण्डियां, जिनिग एवं प्रेसिंग के कारखाने भी हैं। पदमपुरा क्षेत्र की आर. ई. सी. योजना बनाई जा रही है। उस योजना में यह ग्राम बीजवायला व घुमड़वाली सम्मिलित हैं। सूरतगढ़ क्षेत्र की योजना अभी तक नहीं बनी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न तो यह है कि आपने 1971-72 में काम शुरू किया और 1976 के अन्दर काम कम्पलीट हुआ और उसमें भी जो मुख्य काम है वह 55 प्रतिशत, 58 प्रतिशत और 67 प्रतिशत ही है। जैसा कि 33 के.वी. लाइन

Page No 10

(10)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
बहुत इम्पार्टेन्ट है और फरदर डिस्ट्रिब्यूशन करती है लेकिन आपका एचीवमेन्ट 1971 की योजना में 5 साल के बाद केवल 55 प्रतिशत ही है। क्या यह सन्तोषजनक है ?

दूसरे कुओं को कनेक्शन देना है क्योंकि सारा घग्घर बेड है और पानी बहुत है। इसलिए यह जरूरी है कि कनेक्शन दिये जायें। वह भी 57 प्रतिशत ही कुओं को दे पाये हैं। इसके अतिरिक्त जो टोटल कनेक्शन हाउसेस में दिये हैं वह भी कोई सन्तोषजनक नहीं हैं। क्या इस संबंध में कुछ आप कहेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि 33 के. वी. लाइन आपके हिसाब से 47 किलोमीटर होनी चाहिए और 26 किलोमीटर ही हुई है। 33 के. वी. लाइन इस योजना को पूरा करने के लिए जितनी हमें आवश्यकता थी उतनी हमने पूरी कर ली है। 33 के. वी. लाइन इस योजना में सम्मिलित नहीं होती जो भारत सरकार से मन्जूर होकर आई है। यह बोर्ड को ही पूरी करनी पड़ती है और यह लाइन 47 किलोमीटर आंकी गई थी उसको सेपरेट नहीं लेकर बीच में से ही टैप किया है। इसलिए 47 किलोमीटर नहीं होकर 26 किलोमीटर ही हुई है और इसलिए ही आपने उसको 55 प्रतिशत कहा है। 26 किलोमीटर की जो योजना मन्जूर की गई है हनुमानगढ़ के लिए पर्याप्त थी इसलिए उसको आगे करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए 47 किलोमीटर आंकी तो इसको 26 किलोमीटर ही करनी पड़ी। इसलिए 55 प्रतिशत ही आपने पर्सेन्टेज देखा।

दूसरे एल. टी. लाइन के लिए और कुओं के लिए और हाउस कनेक्शन के लिए कहा। जब आर. ई. सी. योजना बनाते हैं तो हमें पर्टीकुलर कनेक्शन की संख्या देनी पड़ती है और इकानामिकली कैसे फिजीबल होगी उस दृष्टि से उस समय जो मेक्सीमम कनेक्शन उपलब्ध हो सकते थे वह टार्गेट दिया हुआ है। योजना बनाने के बाद कुओं पर कनेक्शन लेना वहां के एग्रीकल्चरिस्ट्स के ऊपर डिपेण्ड करता है। कुओं पर कनेक्शन देने की मेरे पास कोई एप्लीकेशन पैंडिग नहीं हैं। डोमेस्टिक के लिए एप्लीकेशन्स आईं और कनेक्शन भी दे दिये गये हैं। कुओं का टार्गेट जितना सेट था उतने लोगों ने कनेक्शन नहीं लिये इसलिए एल. टी. लाइन भी अनुपात में कम हुई। अगर कुओं पर और हाउस कनेक्शन ले लिये जाते तो एल. टी. लाइन पूरी हो जाती।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पाइंट इस प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि 33 के. वी. लाइन की शार्टकट ले ली इसलिए 47 किलोमीटर के बजाय 26 किलोमीटर ही करनी पड़ी। इसलिए अगर यह लाइन पूरी लेते तो गोलूवाला मण्डी है वह कवर हो जाती। पिछले सत्र में भी कहा था कि इस मण्डी को आप शीघ्रातिशीघ्र बिजली देंगे लेकिन केवल इस शार्टकट की वजह से उसको बिजली नहीं मिल पाई।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इस शार्ट कट का जैसा निवेदन किया था कि 33 के. वी. लाइन को खींचने का सारा फण्ड का भार बोर्ड पर पड़ा था और उस समय इतने फन्ड्स नहीं थे और आर. ई. सी.

(श्री हीरालाल देवपुरा)
योजना के लिए पहले दिल्ली से मिलता था और उसको पूरा करना था इसलिए उस समय इस योजना को पूरा करने के लिए जितनी जरूरत थी उतना कर दिया। बीजवायला और गोलूवाला के लिए निवेदन किया कि पदमपुर की आर. ई. सी. योजना बन रही है और उसमें यह सम्मिलित किये गये हैं। गोलूवाला गांव सूरतगढ में है इसकी योजना बनी नहीं है लेकिन मैं दो तारीख को पीलीबंगा गया था तो वहां भी यह प्रश्न आया था और वहां की कृषि उपज मण्डी ने कहा था कि वह मण्डी बोर्ड को लोन के रूप में देने के लिए तैयार है। हमने उनको एस्टीमेट दिया कि 8–10 लाख का खर्चा होगा। उन्होंने एग्री कर लिया है कि हम यह लोन दे देंगे। मैंने उनसे कहा है कि आप यह लोन दे दीजिये तो हम यह काम इसी वर्ष में पूरा करा देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसी वर्ष ?

श्री हीरालाल देवपुरा : हां, याने 1976–77 में।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जीवनदेसर (पदमपुर) में नहरी भूमि का आवंटन

38. श्री गुरदयाल सिंह संघु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री कुरडाराम को जीवनदेसर बरानी तहसील पदमपुर में 89 बीघा 6 बिस्वा बारानी जमीन व 31 आर. बी. आर्य में 5 बीघा नहरी भूमि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि श्री कुरडाराम पंजाब का रहने वाला है और वह पहले भारतीय सेना में 1950 तक सैनिक तथा 1954 तक पंजाब पुलिस में सिपाही था और 1957 में राजस्थान में आया ? यदि हां, तो जब वह तहसील पदमपुर का रहने वाला नहीं है तो उसे किस आधार पर भूमि का आवंटन किया गया ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त मामले में निष्पक्ष जांच करायेगी और इस नाजायज आवंटन को खारिज करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी नहीं। श्री कुरडाराम को 44 बीघा 5 बिस्वा बारानी भूमि भूतपूर्व सैनिक होने के कारण आवंटित की गई है।

(2) जी नहीं। श्री कुरडाराम पंजाब का रहने वाला न होकर गांव गिरजावाला का रहने वाला है तथा सन् 1954 से वहीं रह रहा है। भूमि आवंटन नियमों के अन्तर्गत भूमि पाने का हकदार होने के कारण इसे भूमि का आवंटन किया गया था।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गुरदयाल सिंह संघु : क्या आप यह मान कर चलते हैं कि भूमि आवंटन नियमों के अन्तर्गत वह भूमि पाने का अधिकारी है ? नम्बर 2 कुरडाराम को आप भूतपूर्व सैनिक कहते हैं, वह पंजाब का भूतपूर्व सैनिक है। जो चार उसके पास सर्टीफिकेट्स हैं उनमें पंजाब दिया हुआ है और वह 1957 से पहले राजस्थान में कभी नहीं आया और न रहने वाला है अगर यह तथ्य

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)
आपके सामने साबित हो जाय तो आप यह मान कर चलेंगे कि भूमि जो उसको आवंटित की गई है वह गलत है ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, करणपुर से आने वाले माननीय सदस्य 7 वीं दफा प्रश्न पूछ रहे हैं कुरडारामजी के संबंध में और सरकार का उत्तर हमेशा ही कान्सटेन्ट रहा है कि यह पहले पंजाब में भर्ती हुआ था। वहां से डिस्चार्ज होने के बाद यह पंजाब पुलिस में भर्ती हुआ। सन् 1954 से गिरसावाला गांव में रह रहा है। इसके संबंध में एक रिव्यू एप्लीकेशन हुई थी और उस समय भी 1967 के अन्दर कलेक्टर ने सारा फैसला देख कर किया कि यह वहां रह रहा है। अब राजस्थान में रह रहा है। हिन्दुस्तान में कोई भी एक्स आर्मी पर्सनल जमीन के लिए एन्टाइटल्ड है और राजस्थान गंग कैनाल परमानेन्ट लेण्ड अलाटमेंट रूल्स के रूल 3 का प्रावधान इस प्रकार है :

"All ex-members of the Armed Forces of any of the integrating states of Rajasthan or of India including members of I.N.A. who hold or cultivate in the territory of Rajasthan, shall be entitled to apply for allotment."

इसमें कलेक्टर ने इस रूल के अन्दर सब जांच करने के बाद, रेलेवेन्ट रिकार्ड के ऊपर विश्वास करने के बाद यह फैसला दिया है। राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि उस फैसले में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मेरा कहना है कि जो आपने रूल पढा है उसके अन्दर लिखा है :

"If he is residing in Rajasthan since before 1946."

यह लिखा हुआ है आप पढिए। अगर यह लिखा हुआ है तो किस आधार पर आप उसको जमीन दे सकेंगे ? यह पढ़िए।

श्री परसराम मदेरणा : According to Gang Canal Permanent Allotment Rules all ex-members of the Armed Forces of India whose homes are situated within the territory of Rajasthan shall be entitled to apply for allotment. There is no place restriction or the restriction of any minimum period of residence in Rajasthan. All that is necessary is that he should be an ex-member of the Armed Forces and he should have his home within the territory of Rajasthan.

कलेक्टर का फैसला इस प्रकार है :

"In the present case, there is no doubt that though the applicant was initially enrolled and discharged from armed forces from Punjab, he had settled down in Rajasthan since 1950 and since then he has been residing in Tehsil Ganganagar where he has also purchased a plot and constructed his house.

Page No 13

(11) (13)

(श्री परसराम मदेरणा)
according to rule 31 (7) of these rules, therefore, the applicant is entitled to permanent allotment."

इसलिए हमने परमानेंट अलॉटमेंट किया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : आप पढ़िए। इसमें लिखा है :

"Every allotment should be made only to ex-service personnel who have been residing in Rajasthan since before 1946."

श्री परसराम मदेरणा : मैंने अभी सबसे पहले अंग्रेजी का रूल पढ़ा है, आप कहें तो इसको दुबारा पढ़ दूं या इसका हिन्दी अनुवाद करके भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लूणाराम।

ग्राम रिड़ी की जलदाय योजना

19. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जलदाय योजना ग्राम रिड़ी के अधीनस्थ ग्रामों को कब तक पानी की सप्लाई चालू कर दी जायेगी ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : इस योजना के अन्तर्गत 12 ग्रामों में से ग्राम रिड़ी को अप्रेल, 75 से जल वितरण प्रारम्भ किया जा चुका है। नौ अन्य ग्रामों को मार्च, 76 के अन्त तक जल दिए जाने की आशा है। व दो ग्रामों को अगले वित्तीय वर्ष में जल दिया जा सकेगा।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया है कि ग्राम रिड़ी को जल प्रदान कर दिया गया है, मैं निवेदन करूंगा कि सिर्फ एक कुए के ऊपर मोटर लगाकर चन्द मोहल्लों के लोगों को यह जल दिया गया है और अभी सारे गांव को जल नहीं दिया गया है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, खुद माननीय सदस्य इस बात को मान रहे हैं कि एक कुए पर वहां टोंटियां लगाकर जल दिया जा चुका है। यही तरीका है रीजनल वाटर सप्लाई के अन्तर्गत जल देने का। यही तरीका है कि एक कुए पर या एक जगह पर जहां पर कि रिजवायर की कोठी होती है उसके अन्दर टोंटियां लगा कर गांव के लोगों को पीने के पानी की सुविधा प्रदान कर दी जाय। इसी तरीके से दिया जाता है और वहां पर भी दिया गया है।

श्री लूणाराम : माननीय मंत्रीजी ने कहा कि रिजर्वायर से पानी दिया जा रहा है। लेकिन वह सूखा पड़ा है जिसके अन्दर एक बूंद भी पानी नहीं गया है। गांव बहुत बड़ा है जहां की हजार डेढ़ हजार की आबादी है। इतनी बड़ी बस्ती में एक कुए के ऊपर मशीन लगा कर जलदाय विभाग के जल दिया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था करके समूचे गांव में पानी देने की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री चन्दन मल बैद : मैंने पहले ही निवेदन किया है कि रिजर्वायर की कोठी में टोंटियां लगा कर वहां पर पानी दिया जा चुका है। माननीय सदस्य का यह कहना है कि गांव बहुत बड़ा है और उसकी आबादी को देखते हुए और भी पानी दिया जाय, इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बद्रीप्रसाद।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर रिडी गांव के बारे में माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है उसके बारे में एक सवाल मैं भी माननीय मंत्रीजी से करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने यह कहा है कि रिडी गांव में एक कोठी पर टोंटियां लगा कर पानी दिया गया है और माननीय मंत्रीजी का कहना है कि पानी दिया गया है। मैं इस बात को चैलेंज करता हूं। मैं स्वयं रिडी गांव जाकर आया हूं और पिछले साल मैंने यहां पर एक प्रश्न भी रखा था। आप कहते हैं कि पानी दे दिया गया है, मैं आपको आज की तारीख में भी चैलेंज करता हूं कि एक गांव को भी पानी नहीं दिया गया है। रिडी गांव में डेढ़ हजार की आबादी है और 12 गांवों को पानी देने की योजना है उसमें से एक गांव को भी पानी दिया गया हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य, जो वहां के ही सदस्य हैं और जो उसी कांस्टीट्यूएंसी से आने वाले हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि कुए से पानी दिया गया है, वहां पानी दिया जा चुका है। इसके बदले जो माननीय सदस्य उस कांस्टीट्यूएंसी से नहीं आते जिनको उसके बारे में जानकारी नहीं हो सकती वे कहते हैं कि पानी नहीं दिया गया है तो पहले आप दोनों फैसला कर लें कि कौन सही है ?

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया : मैं माननीय सदस्य को, माननीय मंत्री महोदय को और उनके विभाग को चैलेंज करता हूं। आप रिडी की जांच करवा लें। जिस किसी अधिकारी ने आपको गलत सूचना दी है उसके खिलाफ आप एक्शन लें कि उसने आप को गलत सूचना क्यों दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्री प्रसाद गुप्ता,

श्री चन्दनमल बैद : अफसर के विरुद्ध तो कार्यवाही करनी पड़ेगी लेकिन माननीय सदस्य के विरुद्ध भी क्या कार्यवाही की जाय।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : पानी एक दिन भी नहीं दिया गया है, माननीय सदस्य से पूछ लीजिए।

श्री लूणाराम : मैं निवेदन करता हूं···

श्री अध्यक्ष : अब हो गया खत्म।

श्री लूणाराम : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य का फरमाना भी ठीक है और जो कुछ मैं कह रहा हूं वह भी ठीक है···

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कह रहे हैं वह भी ठीक है।

श्री लूणाराम : मैं अर्ज कर रहा हूं···

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मंत्री महोदय कह रहे हैं वह सही ठीक है।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, गांव बहुत बड़ा है, डेढ़ हजार की बस्ती है। उसके अन्दर पांच कुओं में से एक कुए से पानी दिया गया है। जैसा कि मंत्री महोदय फरमा रहे हैं एक हार्स पावर की मशीन एक कुए में लगाई गई है और वह भी खराब हो गई जिससे पानी नहीं दिया गया है। माननीय सदस्य जो फरमा रहे हैं वह सही है कि उस कुए से भी पानी नहीं दिया जा रहा है। यह स्कीम 12 गांवों के लिए बनाई गई थी और उसमें से सिर्फ एक रिढी गांव के अन्दर एक कुए पर मशीन लगा कर पानी देने की व्यवस्था की गई है। वह मशीन भी गिर गई जिससे वहां पर भी पानी नहीं मिल रहा है इसलिए उस गांव को तो कम से कम किसी न किसी तरह से पानी देने की व्यवस्था की जावे।

श्री शंकरलाल (पाली) : इसकी तो जांच होनी चाहिए, साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह तो बहुत गंभीर मामला है। इसमें तो जांच करवाई जानी चाहिए। वहां पर एक हार्स पावर की मशीन लगी थी वह भी खत्म हो गई, इसकी जांच होनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : वह तो खत्म हो गई।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : किसी कुए से पानी मिल नहीं रहा है। आखिर पानी ही जीवन है, पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए।

श्री शंकर लाल (पाली) : जांच करवाने में क्या आपत्ति है, साहब।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं कहता हूं कि मशीन ही नहीं है।

श्री दीपंकर : मंत्री महोदय जांच करवाने की घोषणा करें....

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री चन्दनमल बैद : एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मशीन लगी ही नहीं और एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मशीन खराब हो गई।

श्री शंकरलाल (पाली) : दो तरह के बयान आ रहे हैं इसलिए तो इसकी जांच करवाई जाय।

श्री अध्यक्ष : पंचायत मन्त्रीजी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मशीन भी गायब हो चुकी है वहां से।

(व्यवधान–शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

ग्राम पंचायत अजबपुरी (बानागाओ) के सरपंच का मामला

40. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की आज्ञा से सरपंच, ग्राम पंचायत

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
अजबपुरा, तहसील थानागाजी, जिला अलवर को अपने पद से हटा दिया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त आज्ञा के बाद सरपंच से पंचायत के उप-सरपंच को चार्ज दिला दिया गया ? यदि हां, तो कब ? कृपया चार्ज की नकल सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार की आज्ञा के खिलाफ सरपंच ने हाई कोर्ट में रिट दायर करके स्टे की आज्ञा प्राप्त की ? यदि हां, तो कब ? कृपया आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि हाई कोर्ट से स्टे प्राप्त होने के पहले ही सरपंच से पंचायत का चार्ज दिलाया जा चुका था और स्टे प्राप्त होने के बाद सरपंच को पंचायत का चार्ज दुबारा दिला दिया गया? यदि हां, तो कब और कैसे और किस आज्ञा से ? कृपया आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरपंच को दुबारा चार्ज दिलाने की हाई कोर्ट की कोई आज्ञा नहीं थी और दुबारा चार्ज दिलाना नियमानुसार नहीं है ?

(6) हाई कोर्ट में सरकार द्वारा रिट के उत्तर में व स्टे के उत्तर में क्या जवाब पेश किया गया ? कृपया प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

पंचायत मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां। आदेश दिनांक 19–7–75 द्वारा सरपंच पद से पृथक् कर दिया गया है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : पंचायत मंत्री जी आप कहां बीच में आ गए। पहले इस पंचायत को तो निपटने दें।

श्री रामनारायण चौधरी : (2) जी नहीं। सरपंच से उप सरपंच को चार्ज दिलाने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी।

(3) जी हां। दिनांक 29-7-75 को उच्च न्यायालय, जोधपुर से स्थगन आदेश प्राप्त किया है जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) पंचायत का चार्ज दिलवाने हेतु दिनांक 1-8-75 को लिखा गया था परन्तु उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश दिनांक 2-8-75 को मौके पर पेश कर देने से चार्ज नहीं दिलाया जा सका।

(5) दुबारा चार्ज दिलाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(6) उच्च न्यायालय में जवाब पेश करने के लिए आफिसर इंचार्ज नियुक्त कर दिया गया है। निश्चित तिथि को उत्तर प्रेषित किया जायेगा।

(आदेश–प्रति के लिए परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरी निश्चित जानकारी है कि सरपंच से उप-सरपंच को चार्ज दिला दिया गया था और अधूरा चार्ज कह कर स्टे आर्डर प्राप्त होने पर दुबारा चार्ज दिलाया गया है। मंत्री महोदय कलेक्टर से जांच करवा कर सही जानकारी प्राप्त कर लें। यह सूचना गलत दी गई है।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे पास में जो जानकारी उपलब्ध है, मान्यवर उसके अनुसार जिलाधीश के द्वारा उप सरपंच को चार्ज नहीं दिलवाया जा सका था और 1-8-75 को जिलाधीश ने सम्बन्धित तहसीलदार को आदेश दिया था कि उप सरपंच को चार्ज दिलवा दिया जाय परन्तु उससे पूर्व 28-7-75 को राजस्थान हाई कोर्ट से स्टे आर्डर जारी हो गया और जब चार्ज दिलवाने को तहसीलदार मौके पर गया तो 2-8-75 को स्टे आर्डर प्रस्तुत कर दिया। इसलिए चार्ज नहीं दिलवाया जा सका।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी निश्चित जानकारी है कि उप सरपंच को चार्ज दिलवाया जा चुका था लेकिन उसको यह कह कर कि अधूरा चार्ज हुआ है चार्ज वापिस सरपंच को दिलवाया गया है। क्या आप इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : जांच करवाने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मोहरसिंह।

कुओं पर बिजली के मिनिमम चार्जेज

41. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर):–क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ट्यूब वैल्स वाले किसानों को बिजली विभाग की तरफ से काफी परेशान किया जा रहा है ?

(2) क्या इस सिलसिले में यह सही है कि खेती के प्रयोजनार्थ बनाये गये कुओं के लिये कनेक्शन मिलना भारी दुविधाजनक व काफी खर्चीला होता जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि मिनिमम चार्जेज के 1950) रु. भरने ही होते हैं चाहे पानी 10 हाथ नीचा हो चाहे 80 हाथ नीचा ?

(4) क्या यह सही है कि मोटर धीरे चलता बता कर किसानों से भारी चार्ज किया जाता है ?

(5) क्या यह सही है कि फसल पकने के वक्त भी पूरी बिजली नहीं दी जाती ?

(6) क्या यह सही है कि पास के कुए से मिल सकने वाली बिजली न देकर किसान को भारी खर्चा करने को मजबूर किया जाता है ?

(7) क्या यह भी सही है कि फसल के खराब हो जाने पर भी किसान को रेमिशन नहीं दिया जाता ? अगर हां, तो इन सारी परेशानियों से ट्यूब वैल्स वाले किसानों को बचाने हेतु सरकार ने क्या इलाज कब तक करने का सोचा है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) :

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। मिनिमम चार्जेज का आधार पम्प की हार्स-पावर है न कि कुए में पानी की गहराई।

(4) जी नहीं।

Page No 18

(8)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(5) जी नहीं। उपलब्ध बिजली का वितरण पूरी तरह किया जा रहा है। उपलब्धता में कमी होने के कारण लोड स्टेगरिंग अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग फीडर्स पर किया जाता है।

(6) जी नहीं। बिजली डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम से या किस स्थान से दी जाये यह तकनीकी आधार पर ही तय किया जाता है।

(7) फसल खराब होने पर रेमिशन देने का सम्बन्ध विद्युत् मण्डल से नहीं है।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे राजस्थान के किसानों से सम्बन्धित यह प्रश्न है। यह सीधा उन पर असर डालता है, और मंत्री महोदय ने हर आइटम के जवाब में 'जी नहीं,' 'जी नहीं' कह कर इसका उत्तर दे दिया। इस सम्बन्ध में क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि वे इसकी जांच कराने को या कोई कमेटी बिठाने को तैयार हैं? किस प्रकार किसानों को 13 से 23 की रेट लगा कर परेशान किया जाता है। किसान बीस हजार रुपया खर्च कर कुआ बनाता है और उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है और फिर उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। यह कहा जाता है कि मीटर धीरे चलता है और इस प्रकार उसके ऊपर दो, तीन हजार का ड्यूज निकाल दिया जाता है। फसल के टाइम पर बिजली नहीं दी जाती और कनेक्शन काट दिया जाता है। इस प्रकार से बिजली विभाग द्वारा किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। इस प्रश्न का जवाब 'जी नहीं' 'जी नहीं' में दिया जाता है। क्या मंत्री महोदय खुद चल कर देखेंगे? क्या वे स्वयं 20/30 कुओं का सर्वेक्षण करने को तैयार हैं? सौ में से कितने पर्सेन्ट कुए आज लॉस में चल रहे हैं? आज पचास पर्सेन्ट कुए बिलकुल ही लॉस में चल रहे हैं। क्या मंत्री महोदय इसका सर्वेक्षण कराने को तैयार हैं? क्या वे इसके लिए इस सदन में हां करेंगे या 'जी नहीं' कह कर इस प्रश्न को भी टाल देंगे? उन्हें इस प्रश्न पर 'हां' कह कर जांच करानी चाहिये। कृपया इसका जवाब दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसकी जांच करानी चाहिये। यह बात हो रही है।

श्री झाबरमल सुण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न के भाग 7 की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रश्नकर्ता यह प्रश्न पूछने से भूल गये हैं। जब बिजली नहीं दी जाती है और मिनिमम चार्जेज लिए जाते हैं तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि वोल्टेज कितना होता है और बोर्ड की ओर से जो वोल्टेज देने की गारन्टी है वह कितनी है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इन सारे कुओं की एप्लीकेशन को उन्होंने देखा है? कब तो एप्लीकेशन दी और कब एप्लीकेशन स्वीकृत हुई? मैं चैलेन्ज करके कहता हूं एप्लीकेशन की स्वीकृति चाहे किसी ने की हो, ए.ई.एन. ने की हो, एक्स.ई.एन. ने की हो, तीन डिस्ट्रिक्ट की बात जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब वहां पर कुओं को बिजली का कनेक्शन देने की रेट दो हजार रुपये से कम नहीं है। इससे कम

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
दिये बिना कनेक्शन नहीं मिलता है। यह मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं। आज बिजली विभाग में दो हजार से कम लिए बिना कनेक्शन नहीं दिया जाता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह दो हजार किस का ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कनेक्शन देने का है।

एक माननीय सदस्य : रिश्वत है।

श्री जगमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली विभाग से फसल के पकने के समय बिजली नहीं मिलती है। इस तरह की व्यवस्था है यह आय दिन की बात हो गई है। मंत्री महोदय इस बारे में ऐसी व्यवस्था करने का आश्वासन इस सदन को दें कि जो कुछ शिकायतें हैं उनकी वे जांच करायेंगे। आज वास्तव में किसान को परेशान किया जा रहा है। और इस कारण उत्पादन पर असर पड़ रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में भी यह आम शिकायत है कई बार अधिकारियों को और कलेक्टर को मैं कह चुका हूं। कनेक्शन काट दिए जाते हैं और रात को भी बिजली पूरी सप्लाई नहीं हो पाती है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकतर कनेक्शन फरवरी और मार्च के महीने में ही काटे जाते हैं जब कि फसल के पकने का समय होता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक का जो जवाब दिया गया था, उसमें सीधा ही यह पूछा गया था कि जान बूझकर बिजली विभाग खास तौर से किसानों को परेशान करने की गरज से बिजली के कनेक्शन काट देता है, उसके जवाब में कहा गया है 'जी नहीं'। कई माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, विशेषकर माननीय श्री हाण्डा जी ने यह कहा कि दो हजार रुपये से ऊपर लेकर ट्यूब वैल्स को कनेक्शन दिया जाता है····

एक माननीय सदस्य : यह कनेक्शन देने की रिश्वत है।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य ने जिस भावना से कहा है····

कई माननीय सदस्य : आपके विभाग में दो हजार रुपये से नीचे कोई कनेक्शन नहीं मिलता है। आपको फ्री कर सकते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरी बात को सुन लें। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं परन्तु साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई एक स्पेसिफिक केस मुझे दें ताकि मैं उसकी जांच करा सकूं और वह व्यक्ति विद्युत मण्डल की सर्विसेज में नहीं रहेगा····

(शोरगुल)

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह जनरल शिकायत है। आप इसके बारे में जांच करा लें। कौन से कनेक्शन के लिए कब एप्लाई किया और दूसरे का नम्बर तोड़ कर दूसरे को क्यों पहले कनेक्शन दे दिया गया ? बात साफ हो जायेगी।

Page No 20

(२०)

श्री केशरीमल : बिना पैसा लिये कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। एक एक पूछ लें ताकि जवाब हो जाये . . .

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, ...

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : पहले मंत्री महोदय का जवाब तो सुन लें।

श्री भोमाराम : अध्यक्ष महोदय . . . .

श्री अध्यक्ष : आप बहुत कम सुनते हैं। जब मैं कहता हूं तो आपको समझ लेना चाहिए। घंटी बजते ही चुप हो जाना चाहिए . . .

(शोरगुल)

मेरा यह निवेदन है मंत्री महोदय को जवाब देने दीजिए। उनके जवाब के बाद सप्लीमेन्टरी पूछ लीजिये। लेकिन एक-एक पूछते जायं ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जो व्यग्रता है, जो परेशानी है, उसको मैं समझता हूं मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं है। मैं इस बारे में माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं इस दृष्टि से मैं खुद चाहता हूं कि ये जो शिकायतें रोजमर्रा आती हैं वे आवें न आवें और किसी तरह से कार्य ठीक तरह से चल सके। लोगों को कोई परेशानी न हो। तो इसका एक ही उपाय है–जब तक कोई स्पेसिफिक केस न दें और उसकी जांच करा कर दो–चार को सजा न दी जाए तब तक यह बीमारी नहीं हटेगी। मुझे एक दो स्पेसिफिक केस बता दें। उसकी मैं आपकी शामलात से जांच करवाऊंगा और जहां यह पाया गया कि कोई गलती है तो उस कर्मचारी, अधिकारी को निश्चित तौर से सजा दूंगा! यह बात साबित होते ही उसको विद्युत मंडल में नहीं रखा जायेगा, यह मैं आपको कह सकता हूं . . . .

श्री दीपकर : अध्यक्ष महोदय . . . .

(शोरगुल)

कई माननीय सदस्यों ने लिखित रूप में ऐसी शिकायत दी है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनको आप निकाल दें। उनको सस्पेन्ड कर दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऐसे व्यक्ति, जो रिश्वत लेने का दोषी पाया गया, को विद्युत मण्डल में नहीं रखा जावेगा।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब सुन लीजिए। He is speaking.

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्यों ने यह बात भी यहां पर कही है कि ये कुओं के कनेक्शन माह फरवरी और मार्च में ही क्यों काटे जाते हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह वर्ष का अन्तिम माह होता है। काफी दिनों से मिनिमम चार्जेज की बात आ रही है और वह इस महीने में बनता है। इस सम्बन्ध में मैंने तत्काल कदम उठाये हैं कि फरवरी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

और मार्च माह में किसानों के कुओं के कनेक्शन नहीं काटे जावें। यह स्पष्ट आदेश दिया है कि इस माह में कोई कनेक्शन नहीं काटा जायेगा। अगर किसी प्रकार मीटर के धीमे चलने या चोरी करने का कोई मामला है तो उसके लिए आदेश दिये गये हैं कि इसका केस बनाया जाये और उसकी जमानत ली जावे ताकि फसल के वक्त बिजली का कनेक्शन नहीं कटे और उसे 31 मई तक का समय दे दिया जाये कि वह अपना पैसा जमा करा दे। इस प्रकार उनके कनेक्शन चलते रहें ताकि उनको कोई दिक्कत न हो। तो यह अभी तक परेशानी थी। उस परेशानी को मिटाने के लिए मैंने स्पष्ट आदेश दिये हैं और इन आदेशों के तहत अब कोई कनेक्शन नहीं काटा जा सकता है। और, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने देखे हैं डिस्ट्रिक्टवाइज आंकड़े मंगाकर कि कितने कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कनेक्शन विजीलेन्स स्क्वाड के माध्यम से या लोकल लेवल के माध्यम से कटे हैं उनका औसत मैंने निकालकर देखा है तो किसी डिस्ट्रिक्ट में वह दो परसेंट आता है और किसी में एक परसेन्ट आता है और किसी में उससे भी नीचे आता है। उससे यह मानकर चलते हैं कि कुछ प्रमुख लोगों के कनेक्शन कटे हैं उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में उनकी अपनी कुछ हैसियत है। जब ऐसे लोगों के कनेक्शन कटे हैं तो उन्होंने एक लाबी क्रियेट की है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मन्जूर किया है कि उन्होंने चोरी की है और पैसे जमा करवाये हैं। उन पर केसेज लगाये गये हैं और उन्होंने एडमिट किया है और वह पैसे जमा करवा रहे हैं। वहां के ऐसे लोगों के जब कनेक्शन कटे तो उन्होंने एक लाबी बनाई और एक वातावरण तैयार किया कि राजस्थान विद्युत मण्डल राजस्थान के अन्दर किसानों को परेशान कर रहा है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपका सहयोग चाहता हूं। आप सहयोग दीजिये। मैं भी किसी करप्ट पर्सन को पसन्द नहीं करता हूं राजस्थान विद्युत मण्डल में। आपके सहयोग से 2-4 आदमियों को सजा दिलवा दी जायगी तो आप राजस्थान की बहुत बड़ी सेवा करेंगे...

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय करप्ट पर्सन्स को पसन्द नहीं करते हैं। एक केस आपके पास आये तो जो एन्क्वायरी का तरीका आपने बनाया हुआ है...

श्री हीरालाल देवपुरा : आप बतायें...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आप सुनने की क्षमता रखें।

आपकी एन्क्वायरी का जो तरीका है उसमें 6 महीने से लम्बा समय लग जायेगा और वक्त के साथ में सही बात नहीं की जायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस के सभी माननीय सदस्यों का इस पर कन्सर्न है तो क्यों न आप एक एन्क्वायरी कमीशन जनरल तौर पर बैठायें? क्यों स्पेसिफिक केस का इन्तजार करते हैं?

(व्यवधान)

सारे काश्तकार परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं। आप जनरल एन्क्वायरी करायें।

श्री अध्यक्ष : श्री हाण्डा।

श्री भोमाराम : कन्जूमर ने रिपोर्ट दे दी···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप संसदीय परम्पराओं का ध्यान नहीं रखते हैं। आप सुनते ही नहीं हैं। मैने हाण्डा का नाम बोला है। हाण्डा पहले बोल लें और बाद में आप बोल लें, लेकिन इतना ध्यान तो रखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सीधा सा प्रश्न है कि कब तो कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन दी गयी और कब स्वीकृत की गई केवल आप इसी का सर्वे करायें सारे राजस्थान का तो आपके सामने स्थिति बहुत स्पष्ट होकर आ जायेगी। कान्कोटली मैंने एक केस आपको लिखकर भेजा था मानावाले का कि चार साल से ट्यूब वैल खुदे हुए हैं लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिला, और उन लोगों का कहना यह है कि मंत्रीजी के आदेश से कनेक्शन नहीं दिलाया जब कि आपने दो साल का कोटा पूरा किया था। कनेक्शन मिले थे जरूर।

दूसरी बात यह कहता हूं कि किसी जिले में एक पर्सेन्ट आया और किसी जिले में दो पर्सेन्ट आया तो मैं चेलेन्ज के साथ में कहता हूं कि आप झुन्झुनूं जिले का सर्वे कराइये तो 80 पर्सेन्ट से ज्यादा को कनेक्शन नहीं मिला है···

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : It is sarcastic remark on the members. कि लाबी तैयार की है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर लाबी होती तो बिड़ला से आप 55 लाख रुपया पहले वसूल कर लेते और और लोगों से पैसा बाद में वसूल करते।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विजयसिंह (मांडल) : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्हें केवल सहयोग चाहिए माननीय सदस्यों का और वे सारी बात मिटाना चाहते हैं, लेकिन मैंने गत बजट सत्र में आपको एक दिया था मामला जिसमें एक आदमी से चक्की के लिए कनेक्शन देने के लिए 3 या साढ़े तीन हजार रुपये मांगे थे ! उसमें क्या कार्यवाही करवाई आपने ? नम्बर मिला है दरखवास्त के ऊपर और उसको ऊपर लगा दिया है उसके बाद में भी नहीं होता है तो क्या सहयोग चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह। I will give time to all of you.

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय सहयोग चाहते हैं एम. एल. एज. का तो निश्चित तौर से राजस्थान के एम. एल. एज. का सहयोग मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक प्रश्न के जवाब का सवाल है हमें उनकी इन्टेग्रिटी पर किसी को शक नहीं है, लेकिन हमें शक तो इस बात पर है कि राजस्थान विद्युत मण्डल और इलेक्ट्रिसिटी विभाग के जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं क्या वे निष्पक्ष तौर से जांच करेंगे ? इसकी पूर्ण रूप से जांच करेंगे ? क्योंकि वहां के

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

साहमनेन, जूनियर इन्जीनियर और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर वह सब लोग मिले हुए हैं तो उनकी जांच को सही मायने में हम जांच नहीं मानते हैं। माननीय मंत्री महोदय, क्या ऐसी चीजों की जांच दूसरों से करायेंगे? आपके खुद के अन्दर निष्ठा नहीं हो ऐसी बात नहीं है लेकिन जो आपके नीचे के अधिकारी हैं वे क्या सही मायने में जांच करेंगे? सक्सेना जैसे अधिकारी को आप जांच सौंपेंगे जो सही मायने में ईमानदार नहीं है और जिनका प्रमोशन आप बराबर कर रहे हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप किन से कराना चाहते हैं जांच? आप ऐसे तरीके निर्धारित करेंगे कि मामला लम्बा हो जाय। जो जिम्मेदार हैं उनको बचाते हैं ऐसे लोगों से जांच करायेंगे? जांच आप उनसे करायेंगे ताकि जांच में निष्पक्ष हों।

श्री अध्यक्ष : श्री सूण्डा।

श्री झाबरमल सूण्डा : अध्यक्ष महोदय, मिनिमम चार्ज किया जाता है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि मिनिमम चार्ज आप ले लें। उसको आप पहले से बढ़ाते आये हैं तो आप मिनिमम गारन्टी भी दे दें, मिनिमम वाल्टेज और मिनिमम आवर्स की। आप एक हफ्ते में 200 घण्टे और 400 वाल्टेज 10 पर्सेन्ट एवव और बिलो तो भी ठीक है। अगर बिजली बराबर सप्लाई नहीं करते हैं जब कि फसल खड़ी होती है और फसल खराब हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन हो? 200 घन्टे और बराबर वाल्टेज की बिजली नहीं मिलने से जो नुकसान किसानों को होगा तो वह नुकसान बोर्ड को भरना होगा।

श्री मोहर सिंह : जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया कि पर्टीक्यूलर केस बतलाओ तो मैं एक पर्टीक्यूलर इलाका बतलाता हूं। झुन्झुनूं जिले में चिड़ावा और झुन्झुनूं के बीच में 15–20 गांवों का सर्वे करा लें आपके विश्वस्त अधिकारी को भेजकर। जो सारे प्वाइंट्स मैंने बतलाये हैं उनके लिए आपको वहां जाकर हां कहना पड़ेगा। क्या इस चीज के लिए आप तैयार हैं? 15–20 गांवों की जांच करवा लें उससे सारे राजस्थान की स्थिति मालूम हो जायेगी। हांडी में से एक चावल देखा जाता है। वही बात आपको सही मिलेगी सारे राजस्थान में। यह छोटा सा सवाल नहीं है। क्या आप झुन्झुनूं जिले के 10 गांवों की जांच करवाने को तैयार हैं? ज्यादा से ज्यादा उनमें दो दिन लगेंगे। इस बात के लिए आप कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि ज्यादा समय न लें। इसी प्रश्न पर 25 मिनिट खर्च हो गये हैं...

श्री मोहरसिंह : प्रश्न महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण नहीं होता तो 5 मिनिट में ही खत्म कर देता। दो मिनिट प्रश्न काल में बाकी रहे हैं उसमें मंत्री महोदय का जवाब सुन लें। उसके बाद में प्रश्न काल को उसके समय में समाप्त करना पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं है कि एक घन्टे तक एक ही प्रश्न चले। इस पर ज्यादा बात करने के लिए बहुत सी बातें हैं। यह प्रोसीजर आप एडाप्ट कर लें तो मैं टाइम दे दूंगा। रूल्स आफ प्रोसीजर में बहुत से प्रोसीजर्स हैं जिनके तहत इस मामले को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अवर में ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं।

श्री दीपंकर : हॉफ एन अवर का बतला दें।

श्री अध्यक्ष : दीजिये। कौन मना करता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट निवेदन किया था कि जांच के अन्दर मैं केवल उन्हीं आफिसर्स पर भरोसा करके नहीं चलना चाहता और जैसा कि मैंने माननीय सदस्यों की ओर संकेत किया था कि उनकी शामलात से जांच करवाई जायगी। उसमें मैं नहीं समझता कि कोई सन्देह हो। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी अधिकारी का यहां पर नाम लें और उसके खिलाफ स्पेसिफिक चार्ज लगायें, जांच में नाम लें और उसके खिलाफ चार्ज लगायें, लेकिन इस तरह से यहां पर नाम लेना गलत होगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : अधिकारी की बात गलत नहीं है। पहले भी आनन्दमार्गी मंगलबिहारी के लिए कहा था और बाद में आपने माना। माननीय मंत्री महोदय को एक अधिकारी लॉबी में बैठकर गालियां देता है तो हम कैसे उसको बरदाश्त कर सकते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आप यह अगर मानते हों कि मैं किसी की बोली पर चलता हूं तो यह गलत है। इन्फार्मेशन जो नीचे से आती है वह अधिकारियों से लेनी होती है, लेकिन यह जवाब डिक्टेट कर दें और मैं इसको कह दूं इस तरह का मैं बना हुआ नहीं हूं। उस तरह से न मैंने जवाब दिया है न देने की इच्छा रखता हूं और न दूंगा।

कुछ बात माननीय सदस्य ने कहीं। कनेक्शन की तारीख के बारे में कहा, तो उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि एप्लाई कब किया और कनेक्शन कब मिला ! अध्यक्ष महोदय, एप्लीकेशन्स कई हैं और काफी आती हैं, और यह बात सही है कि जब एप्लाई किया तो उसके 2-4 महीने तक तो कनेक्शन नहीं मिल सकता है। मैं यह नहीं कहता कि कनेक्शन हमें प्रायोरिटी के आधार पर देना होगा। बीच में ऐसा समय आ गया जिस समय मैंने कनेक्शन देना बन्द किया था। वह काफी लम्बा अवसर निकला है। माननीय हांडा जी ने यह कहा है कि उनके यहां रिश्वत लेकर कनेक्शन दिये हैं। अगर ऐसा हुआ है तो मैं उन पर एक्शन लूंगा। आप नाम बता दीजिए मैं सस्पेण्ड करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप क्या करेंगे, ऐसे अफसरों के खिलाफ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं उनको सस्पेण्ड करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आर. एस. ई. बी. के चेयरमैन आपकी बात मान लेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आप इसकी चिन्ता क्यों करते हैं। आप तो मेरे पास नाम भेज दें।

श्री दीपंकर : जो अधिकारी हमारे मंत्री को बदनाम करे, उसके लिए मैं माननीय सदस्य के सहयोग के लिए तैयार हूं। जो माननीय सदस्य गहलोत साहब ने कहा है, उसके पीछे बहुत सच्चाई है।

श्री हीरालाल देवपुरा : उसके बारे में मैंने निवेदन किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कार्यक्रम कमेटी में यह बात स्पष्ट है कि यह इलेक्ट्रिसिटी इन्सपेक्टर की जिम्मेदारी के कारण कनेक्शन नहीं मिलते हैं।

(व्यवधान : अश्रव्य)

उसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्स्पेक्टर की बात की है।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने कहा है कि उसको कनेक्शन नहीं मिला। यह जरूरी नहीं है कि हर आदमी को कनेक्शन मिले ही। मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा, मुझे उनका पूरा सहयोग मिलेगा। मैं उसकी जांच कराने के लिए तैयार हूं। अगर आप यह बता देंगे कि उसके अन्दर अधिकारी मिले हुए हैं तो मैं उसकी जांच करा लूंगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपको यह किसने कहा है...

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गहलोत साहब ने प्रोसीजर की बात कही थी। मैं निवेदन करूंगा कि जो आपका प्रजेण्ट ढांचा है, उसके अनुरूप अगर जांच करायेंगे और जो शिकायत करते हैं तो वह तो उसके विरुद्ध आयेंगे ही। आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं वह वही आदमी हैं जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में सतर्कता आयोग द्वारा सस्पेण्ड करने की सिफारिश की गयी है। आपने उसी आदमी को वापिस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सेक्रेटरी बना रखा है। इससे हम क्या उम्मीद करें।

कई माननीय सदस्य : Correct, Correct.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

एक माननीय सदस्य : महावर साहब वाला प्रश्न तो रह ही गया।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति का आठवां, नवां व दसवां प्रतिवेदन

श्रीमती नगेन्द्र बाला (सभापति, प्राक्कलन समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति 1975-76 का सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पथ) से सम्बन्धित आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं परिवार नियोजन विभाग विषयक प्राक्कलन समिति 1969-70 के 17 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिश पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति 1975-76 के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग विषयक प्राक्कलन समिति 1968-69 के 11 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति 1975-76 के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : बजट पर सामान्य वाद-विवाद ।

श्री शंकरसिंह ।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने वर्ष 1976–77 का बजट प्रस्तुत किया है। मैं उनको बधाई देते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े साजबाज से बजट को रखा है। वर्ष 75-76 में किसी प्रकार का कर नहीं लगाया था। लेकिन जहां कोई कर लगाया जाता है। जो वित्त मन्त्री जी ने बजट रखा है और उसमें जो विकास के लिए रखा है, उसके लिए मैं वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं। 1 जुलाई 1975 को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो कार्यक्रम राष्ट्र के सामने रखा, जो भी जिस स्थान पर है, हर व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाये। अजमेर जिले में जो जिला स्तर पर कमेटी गठित की गई, उसमें खास तौर से गांवों से प्रतिनिधि लेने चाहिये थे, लेकिन दुर्भाग्य से कोई आदमी नहीं लिया गया है जो कि ग्रामीण आदमियों की समस्या को बता सके। मुझे इस बात का खेद है। इसके अतिरिक्त मैं आवासीय-खण्डों के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। राज्य स्तर पर बड़ी तेजी से भूखण्ड दिये गये। राज्य सरकार का यह प्रयत्न सराहनीय है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कई जगह पर ऐसी जगहों पर भूखण्ड दिये गये है जहां दूसरे लोग अतिक्रमण किये हुए थे। फिर भी कहने पर जिलाधीश ने अतिक्रमण हटाकर कब्जे दिलाये हैं। जो भू अलाटमेंट कमेटी है, जब कि 1 तारीख को अलाटमेंट कमेटी की मीटिंग थी तो पता चला कि कमेटी भंग हो गई है। क्षेत्रीय विधायकों के नोटिस आते हैं। लेकिन जो गांव प्रतिनिधि है, वे सरपंच हैं। वह जगह बता सकते थे। लेकिन वह कमेटी भंग करने से अब वह नहीं है। मैं राजस्व मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह आवण्टन कर सकती थी। अब ऐसी स्थिति में पटवारियों ने सरकारी और अपने ही व्यक्तियों को अलाटमेण्ट कर दिए हैं। राजस्व मन्त्री जी से मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि अभी भी बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को जमीन उन काश्तकारों को अलाट करनी चाहिए थी जो स्वयं काश्त करते हैं या हल चलाते हैं और जिनके पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, उनको नहीं दी जाकर ऐसे लोगों को दे दी गई जो और कोई काम करते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो बिजनेस करते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, उनके नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर राजस्व मन्त्री जी इसकी जांच कराने को तैयार हों तो मैं बता सकता हूं। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत, मन्त्री महोदय से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि किशनगढ़ तहसील में एक गांव है सिनोदिया, वहां के पटवारी ने गांव के किसानों को और भूमिहीन लोगों को दबाया कि जमीन नहीं है। यही नहीं, 20-12-75 को दस आदमियों को भूमि अलाट कर दी गई और यह उन आदमियों को की गई जिनके पास पहले से जमीन थी। कई लोगों ने लिखकर भी दिया है, और तहसीलदार के दबाने से रतना बाई ने साफ लिखा है कि उनके दबाने से हमने लिखा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जनता के चुने

(श्री शंकर सिंह रावत)
हुए प्रतिनिधियों के द्वारा सही स्थिति का अवलोकन कराकर भूमि का आवंटन किया जाता तो इस प्रकार की अनियमितताएं नहीं हो सकती थीं। जो अच्छे किसान और जरूरतमन्द लोग थे वे भूमि आवंटन से वंचित नहीं रह जाते। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सलाहकार समिति के द्वारा यह काम सही ढंग से कराया जा सकता था और लोगों को फायदा हो सकता था। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, अति वर्षा से अजमेर जिले में बहुत नुकसान हुआ, गरीब लोगों के कई मकान बह गये, वहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट और यू. आई. टी. के लोगों के साथ मैं खुद भी मौके पर गया था, होना यह चाहिए था कि जो मकान नदी के किनारे पर हैं उनको हटाना चाहिए था लेकिन उन लोगों के मकान तोड़ दिये गये और उनको बसाने का कोई भी प्रबन्ध नहीं किया गया। यही नहीं दूसरी जगह भी मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। मैं खुद मौके पर गया और मैंने जिलाधीश महोदय को भी निवेदन किया कि केवल वे ही मकान तोड़े जायं जो नाले के पास हैं और उनको तोड़ने से पहले कोई और व्यवस्था भी की जाय। अध्यक्ष महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम के दौरान, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि समय को देखते हुए, यह जरूर है कि इमर्जेन्सी लागू होने के बाद एक-डेढ़ महीने तक तो इसका असर अच्छा हुआ लेकिन अब फिर उसके पहले जैसा ही होने लग गया है। आज भी जब मुख्य मन्त्री जी सचिवालय में पहुंच जाते हैं या बड़े-बड़े मन्त्री या अधिकारी लोग चले जाते हैं तो मौके पर जाकर देखते हैं कि कौन कौन समय पर नहीं आया है, यह हाल इमर्जेन्सी लागू होने के एक-डेढ़ महीने तक तो रहा था, लेकिन आज पहले जैसी ही स्थिति फिर होने लग गई है और इमर्जेन्सी के जरिये जो हम विकास और सुधार लाना चाहते हैं वह नहीं हो रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि कम से कम इस आपात स्थिति के अन्दर बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर जो काम हमको देश के लिए करना है उसके लिए एक समय निश्चित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि 35 ावों को यू. आई. टी. में मिला तो दिया गया लेकिन आज उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से तो उनको जो सुविधायें पहले मिल रही थीं उनसे भी उनको वंचित कर रहे हैं और जो उनको लाभ मिलने चाहिए वह नहीं मिल रहे हैं। यह कोई उचित बात नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कार्य हम दिल से करना चाहते हैं वह नहीं हो रहा है और हम देखते हैं कि कई लोगों की मनमानी खत्म नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि जो बीस सूत्री कार्यक्रम हमने जनता के सामने रखा है, कम से कम हमारी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों और कर्मचारी दोनों मिलकर ही इसको सफल बना सकते हैं, तभी यह उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में अभी बजट में वित्त मन्त्रीजी ने प्रावधान किया है। बिजली के लिए 28 व्यक्तियों को कनेक्शन देने की बात भी कही गई है। अजमेर में विद्युत् मन्त्रीजी ने कहा था कि, हम आपका सहयोग चाहते हैं, मैं मानता हूं

(श्री शंकर सिंह रावत)

लेकिन आज विद्युत मन्त्रीजी ऐसे पद पर बैठे हैं उनका स्वयं का यह उत्तरदायित्व है कि जो भी शिकायतें आवें उन पर वे स्वयं ध्यान देकर कार्यवाही करावें जिससे कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में सहायता मिल सके। लेकिन अगर हम शिकायत लिख कर देते हैं तो आप उसकी जांच अधिकारियों से करवाते हैं, इसका मतलब है आपको जन प्रतिनिधियों में विश्वास नहीं है, इससे लोगों में असन्तोष फैलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्व. पी. के. चौधरी साहब ने भी कहा था कि आपको तो अपने कर्मचारियों का विश्वास है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का विश्वास नहीं है। इसलिए आज जो भी कनेक्शन दिये जा रहे हैं या जो कुछ भी इस प्रकार की चीजें है, मैं रिश्वत की बात नहीं कहता, रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले दोनों ही अपराधी हैं, लेकिन यह मानकर चलना पड़ता है कि हमारे काश्तकारों को समय पर बिजली उपलब्ध नहीं होती है जो कि बहुत ही अनुचित बात है, उनको तंग किया जाता है हर तरह से। इस तरह की कार्यवाहियों से हमको दुःख होता है कि जो नीति सरकार की है वह सफल नहीं होती है।

यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि डेयरी और दूध के लिये प्रावधान रखा है। अजमेर की डेयरी के लिए मैं निवेदन कर दूं कि उसका दूध अजमेर और दिल्ली को सप्लाई किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम गहराई से सोचें तो उसमें कितना खर्चा है और उसकी आय कितनी है इसका अवलोकन किया जाय तो मालूम पड़ेगा कि इसमें घाटा है और उस घाटे की पूर्ति करना है जो 19 करोड़ का घाटा है और दूसरी तरफ लोग अनियमितताएं करते चले जावें। केवल पैसा ही खर्च करना और यह दिखाना कि हमने इतना रुपया इस काम के लिये खर्च किया, यह कोई शोभा की बात नहीं है। जितना टैक्स का पैसा हम वसूल कर रहे हैं उससे यह भी देखना चाहिए कि देश को उससे क्या मिल रहा है, यह देखने की बात है। अगर नसीराबाद और ब्यावर नगरों में भी दूध की सप्लाई करते और उसके बाद जो भी दूध बचता और उसको दिल्ली भेजते तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन केवल यह दिखाने के लिये कि हमको दिल्ली भी दूध पहुंचाना है और फिर घाटा हो जाय, इस बात को मैं उचित नहीं मानता हूं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं डेयरी के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां पर पूरा दूध मिल जाय उसके बाद ही दूसरी जगह सप्लाई किया जाना चाहिए तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना यह है कि आपने काफी अस्पतालों को क्रमोन्नत करने के लिए प्रावधान किया है। मुझे यह भी कहना है कि आप फलोदी जैसी जगह के अस्पताल को भी क्रमोन्नत करने जा रहे हो और वह इसलिए कि सिंचाई मन्त्रीजी उधर से आते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नसीराबाद का एरिया है वहां पर कैन्टोनमेन्ट है आज वह लीज पर चल रहा है वहां से लोगों को हटाया भी जा सकता है। उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कम से कम इतना ही

(श्री शंकर सिंह रावत)

किया जाता कि वहां के अस्पताल में 20 की जगह 50 बेड कर देते तो मुझे खुशी होती। आप कोई भी प्रावधान करो, कहीं भी करो इससे मुझको एतराज नहीं है परन्तु दूसरे क्षेत्र वालों को भी वंचित नहीं रखना चाहिए। मैं इस बात को शिकायत के रूप में नहीं कह रहा हूं, मगर राज्य सरकार को भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करना चाहिए। इसके बारे में हमने पहले भी निवेदन किया था। आपने जो भी प्रावधान रखा है वह वहां की पहले भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां का सर्वे कराकर रखते तो और उसको लागू करते तो उपयुक्त था, लेकिन होता क्या है कि बजट में तो प्रावधान रख दिया, इतने करोड़ लगाये अमुक चीज पर। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, होगा वही कि लड़ने वालों को, भाग दौड़ करने वालों को वहां से पैसा मिल जायगा और वास्तव में भौगोलिक दृष्टि से विकास होना चाहिए, उससे वंचित रह जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक औषधालय है, वह सी श्रेणी का है, उसको क्रमोन्नत किया गया है। वहां सौ घर ऐसे हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के है। शिड्यूल्ड कास्ट्स को सुविधा देने के लिये ऊंचा बनाने के लिए, उनके विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं और यह बीस सूत्री आर्थिक प्रोग्राम में भी रखा है। लेकिन आज भी जो डिस्पेंसरी है आयुर्वेद की उसको क्रमोन्नत किया गया है, उसमें न नर्स गई है, न कम्पाउन्डर है। सिर्फ नाम मात्र के लिए क्रमोन्नत किया है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, आयुर्वेद मंत्री महोदया हैं, उनको मैंने कई बार कहा है कि इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से हर क्षेत्र को देखें। मैं समझता हूँ कि कोई मंत्री चुन कर आता है, वह जनता की भलाई करने के लिए आता है, भले ही वह अपने क्षेत्र में काम करे इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से कार्य करेंगे तो शिकायत नहीं आयेगी।

मैं विद्युत और कृषि उत्पादन के लिए निवेदन कर देना चाहता हूँ। कृषि ऐसी चीज है जिसके लिए राष्ट्र चिन्तित है। कर्मचारी वर्ग है वह मंहगाई के लिए चिल्लाता रहता था। वह कहता है, हमें मंहगाई भत्ते से मतलब नहीं है, हमें आप सस्ता अनाज दीजिए, सारी चीजें उपलब्ध कराइये। किसान पैदावार अपने साधनों से करके राष्ट्र को ऊपर ला रहा है लेकिन उसके सामने आज समस्या बनी हुई है। रबी की फसल का अनाज सस्ता होता जा रहा है, उससे वह चिन्तित है। मंहगाई भत्ता कर्मचारी के लिए जिस स्तर पर है, उससे पैसा नहीं छीन रहे हैं लेकिन किसान जो थोड़े साधनों से अनाज पैदा करता है, उसकी चिन्ता आपको करनी चाहिए। कपड़ा, लोहा और बिजली है, यह उसको सस्ती उपलब्ध करानी पड़ेगी।

मैं बिजली के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। किसान, वह ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इतना दुखी नहीं है जितना विद्युत विभाग से दुखी है। मैं जानता हूं कि किसान रिश्वत देना नहीं चाहता। लेकिन एक तरफ किसान की पैदावार दो सौ रुपये क्विन्टल की जगह अस्सी रुपये क्विन्टल बिकवाना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ उसको विद्युत के लिए दो हजार, पन्द्रह सौ रुपये

(श्री शंकरसिंह रावत)

रिश्वत के देने पड़ते हैं। मजबूरन वह देता है क्योंकि समय पर उसको बिजली चाहिए। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, विद्युत् मंत्री से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि स्वयं आप खुद दौरा करने ऐसी जगह जायं और देखें कि जान बूझ कर आपके डिपार्टमेंट के लोग उनके साथ अत्याचार करते हैं। समय पर उनको बिजली नहीं देते हैं। पूरा वाल्टेज नहीं देते हैं। आपको यह सर्वे कराना चाहिए कि किसान को कितने वाल्टेज की जरूरत है। आपने 100 वाल्टेज का ट्रान्सफार्मर लगा दिया लेकिन सवा सौ वाल्टेज विद्युत् लोगों को दी है। आप सवा सौ वाल्टेज का ट्रान्सफार्मर नहीं लगा सकते। आपका यह कहना है कि जिस वक्त ट्रान्सफार्मर आयेंगे तब लगायेंगे। लेकिन इस कारण से कई किसानों के मीटर जल गये हैं और उनको ठीक कराने के लिए तीन सौ, चार सौ किसान को खर्च करने पड़े हैं। विद्युत् न मिलने से, समय पर पानी नहीं मिलने से, मैं समझता हूं, देश के कृषि उत्पादन में रुकावट आती है। इसलिए इस विभाग में सतर्कता होनी चाहिए। देश के कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, मैंने आप से निवेदन किया, विद्युत् विभाग कम से कम ऐसा होना चाहिए जो किसान की जरूरत का ध्यान रखे। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें पूरा पैसा मिल रहा है, आज मंहगाई के मामले में कर्मचारी किसान से ज्यादा सुखी हैं, पहले मंहगाई थी उस समय कर्मचारी जरूर घबड़ा गये थे क्योंकि तीन सौ, चार सौ तनख्वाह मिलती थी उससे उनकी पूर्ति नहीं होती थी। लेकिन आज किसान घबड़ा रहा है, कर्मचारी को आज फर्क नहीं पड़ा है, उसका वेतन उतना का उतना है लेकिन पहले जहां दो सौ रुपये में वह एक बोरी अनाज लाता था, आज दो सौ रुपये में दो बोरी खरीद सकता है। मेरा निवेदन है कि आप को कृषि उत्पादन के लिए सोचना चाहिए।

यही नहीं, आवासन बोर्ड के लिए आज 19 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं और आप कुल अठारह सौ भवनों का निर्माण करने जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, वित्त मंत्री को मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि 19 करोड़ आपने आवासन के लिए रखे हैं, तो आपको भवनों के अनुपात में जिलावाइज पैसा देना चाहिए क्योंकि उसमें होता यह है, मैं समझता हूँ, भौगोलिक दृष्टि से आवास की हर शहर में जरूरत है। 19 करोड़ लम-सम में रख कर आप चाहते हैं, जिसकी शक्ति ज्यादा होगी, जो ज्यादा बोलने वाला होगा उस जिले में ज्यादा पैसा चला जायगा। अच्छा होता, वित्त मंत्री जी यह रखते, शहर की जनसंख्या या आवास के आधार पर इस तरह के अनुपात से जो 19 करोड़ का बजट है, जो पैसा आवास के लिए रखा है, वह जिलावाइज खर्च करेंगे।

यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, गृह निर्माण समिति को एक तरफ आवास खण्ड दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप गृह निर्माण करेंगे। अजमेर जिले में आप जांय, वहां पर एक नरोल गांव है। वहां पर लड़ते लड़ते उस गृह निर्माण समिति को पैसा मिला है, पहली किश्त मिली है। अभी नींव में पत्थर पड़े हैं लेकिन नोटिस दुबारा वसूली के लिए आ गये हैं। गृह निर्माण समिति को जो आबंटित करना चाहते हैं धनराशि, मैं निवेदन कर रहा था, वह जिलावाइज होनी चाहिए। थोड़ी भी मिले, लेकिन गृह

(श्री शंकर सिंह रावत)

निर्माण समितियों को जिलावाइज मिलती है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तो अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे थोड़ी देर का समय और चाहूंगा।

दूसरी अर्ज है कि वित्त मंत्री महोदय ने 49 करोड़ का घाटा बताया है। उसकी पूर्ति करनी चाही है अन्य आय से, फिर भी 19 करोड़ का घाटा बताया है। घाटे की पूर्ति करने के लिए, अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने कर किस पर लगाये हैं। रेफ्रीजीरेटर पर कर कम किया है। आज व्यापारी और उन लोगों पर, जो पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं, कर कम करना चाहते हैं। गर्मी में उनके कमरे में पंखा लगा हुआ है, कूलर है,

(12.26 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

लेकिन वित्त मंत्रीजी, जिस किसान से आप सफेद गेहूं लेते हैं वह गर्मी में हल चलाता है। उसके लिए आपने क्या किया है? आपने यह नहीं देखा कि कितनी गर्मी में वह हल चलाता है और आपको अन्न उत्पादन करके देता है। आपने व्यापारी के लिए कर में कमी कर दी ताकि वह पंखे के नीचे बैठे, ठन्डा पानी पी सके। लेकिन जो धूप में काम करता है, उसकी सिंचाई की दर अपने बढ़ाई है। यह उचित नहीं है। किसान देश के लिए अन्न का उत्पादन कर रहा है। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा, आप इस बात का अध्ययन करें। किसान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, जब वह होम मिनिस्टर थे, किसान की कमर टेढ़ी है। जिस दिन इस किसान की कमर सीधी होगी उस दिन सिर उठा कर बात करेगा। आज आप क्या कर रहे हैं, विद्युत से जो पंखे चलने वाले हैं उसके लिए आपने विद्युत दर नहीं बढ़ाई है लेकिन बाहर किसान धूप में हल चलाता है उसके लिए सिंचाई की दर बढ़ा दी। इस कारण से किसान को जो सौ मन का पहले पैसा मिलता था, वह अब ढाई सौ मन पर मिलेगा, ढाई सौ मन बेचेगा तब उतनी धनराशि मिलेगी। मैं निवेदन करूंगा कि जवाब देते हुए आप किसान के लिए जरूर सोचें...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री शंकरसिंह रावत : मेरा निवेदन है कि कपड़े के ऊपर आपने दस पर्सेन्ट के बजाय सात पर्सेन्ट किया है। आज किसान के लिए तीन चीज जरूरी हैं, रोटी, कपड़ा और आवास। तीन उत्तरदायित्व आपके हैं, निवास के लिए आवास देना, पहनने के लिए कपड़ा देना, खाने के लिए भोजन देना। लेकिन आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं। कपड़े पर इस प्रकार टैक्स लगाया है, वह दस पर्सेन्ट के बजाय आप पांच प्रतिशत रखते तो ज्यादा उपयुक्त होता।

अधिक समय न लेते हुए इतना ही मैं निवेदन करूंगा कि जो बजट रखा है उसका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इसे भौगोलिक दृष्टि से खर्च किया जाय। आप किसान को राहत देना चाहते हैं। वह आज चिन्तित है क्योंकि भाव गिरते जा रहे हैं। आप न्यूनतम भाव तय करके किसान की समस्या हल करें क्योंकि वह कृषि उत्पा-

(श्री शंकर सिंह रावत)

दन देश के लिए करता है । आज अस्सी पर्सेन्ट लोग गांवों में रहते हैं, उनके लिए आपको सोचना पड़ेगा (समय–समाप्ति सूचक घंटी) शहरों के अन्दर बीस पर्सेन्ट रहते हैं, उनके लिए आप ज्यादा सोचते हैं। किसान यह समझता है कि वह देश के लिए काम कर रहा है । लेकिन जब उसे यह स्थिति मालूम होगी तो वह सोचेगा कि मुझे मेरे लिए ही करना है, देश के लिए कुछ नहीं करना है तो आपके हाथ पांव बंध जायेंगे, आप खड़े के खड़े रह जायेंगे । लेकिन किसान को आज यह मालूम नहीं है । किसान का क्रूड आइल आज मंहगा डीजल मंहगा, और साबन मंहगे और उसकी पैदावार को सस्ते भाव पर बिकवायेंगे, उस पर नियंत्रण नहीं करेंगे । मैं कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, जो खाद्य मिनिस्टर भी हैं कि वह इस बात का अध्ययन करें कब सोचेंगे ? बाजार में अनाज आ रहा है, भाव बिल्कुल गिर रहे हैं क्या सरकार बाद में सोचेगी ? तो कम से कम यह घाटे का बजट किसान को ऊंचा लाए और जो दो नंबर के पैसे वालों को बहुत गर्मी हो रही है, उनमें और गर्मी लाई जाए ताकि वे समझें कि किस तरह से अनाज आ रहा है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि बजट को कम से कम एक साल के लिए भौगोलिक दृष्टि से चलायें ताकि बजट के संबंध में शिकायत नहीं आए । आशा है, वित्त मंत्री अपने उत्तर में किसानों पर जो कर लगाए हैं, उस संबंध में कहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सज्जन सिंह ।

श्री सज्जन सिंह (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में प्रवेश करते समय मेरे एक मित्र ने मुझे सलाह दी कि silence is golden और मैंने स्वतः ही उन्हें कह दिया कि Timidity is not a virtue

श्री ओंकारलाल चौहान : But speech is silver.

श्री सज्जन सिंह : इस बजट को देखकर अर्थशास्त्र के किसी प्रकांड विद्वान् से सलाह करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती । आज देश में एक लहर है । प्रधान मंत्री ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम, कांग्रेस द्वारा जनता को दिए हुए आश्वासनों को क्रियान्वित करने के लिए, गतिशील करने को दिया है और एक फिजा बन गई है कि उस आर्थिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है । यह तो खुशी की बात है कि हमारी सरकार जागरूक हुई और इस पर कुछ काम भी कर रही है लेकिन जब मैंने माननीय वित्त मंत्री के बजट अभिभाषण को सुना तो मुझे यह महसूस हुआ कि इस देश की फिजा की सारी उपलब्धियों का यश हमारी सरकार ही लें, हमारे मुख्य मंत्री ही लें और उनके काम जब राजस्थान में मैं देखूं तो देखूं कि ब्योरोक्रेसी के माध्यम से किए जा रहे हों तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह सरकार आखिर हम लोग चलाते हैं या सदन के माननीय सदस्य चलाते हैं या ब्यूरोक्रेसी चलाती है ? मैं आश्चर्य भी नहीं करता क्योंकि ऐसा बजट तो राष्ट्रपति शासन में कोई भी ब्यूरोक्रेट बना सकता था । केन्द्रीय सरकार के डाइरेक्टिव्ज को फ्लाउट करने की बात कोई नहीं कर

Page No 33

(श्री सज्जन सिंह)

सकता, केन्द्रीय सरकार के दिए हुए डाइरेक्टिव्ज के पर्सपेक्टिव में आपको अपनी प्लानिंग करनी होगी, आपको अपना बजट बनाना होगा।

एक जगह वित्त मन्त्री ने बड़े जोश के साथ कहा है कि भारत सरकार से अधिक सहायता प्राप्त करने के हम प्रयत्न जारी रखेंगे। वह भी उस प्रसंग में आपने कहा है कि जब अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई तो चालू वर्ष में भारत सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई, फिर भी आपने अधिक प्रावधान करके खर्च किया। यह तो आपकी जिम्मेदारी थी और अगर आपने ऐसा कुछ किया भी है तो आपको उसके लिए यश लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी आपने अपना कर्त्तव्य निभाया। आप अगर ऐसा नहीं करते तो लोग भूख से मरते और भूख से अगर लोग मरते तो समाज में आप कलंकित होते और दुनियां की निगाह में आप गिरते। तो जो आप कर्त्तव्य निभाते हैं वह आपकी प्राइमरी रेस्पांसिबिलिटी है। उसके लिए आप इतने सस्ते यश की चारण की तरह आशा लेकर घूमते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता।

आपने बिजली की दरें बढ़ा दीं, आपने 13 पैसा प्रति यूनिट की जगह 23 पैसा प्रति यूनिट कर दिया। आपने लैंड रेवेन्यू बढ़ाया। आपने सरचार्ज बढ़ाया। आपने क्रूड के भाव को बढ़ाया, डीजल के भाव को बढ़ाया। ट्रैक्टर्स की कीमत बढ़ गई। कृषि इनपुट्स में फर्टीलाइजर की कीमत बढ़ी, पेस्टीसाइड्स की कीमत बढ़ी बाजार में जब कृषि उत्पादन के भाव निरंतर गिरने के मामले में भी आप यश कमाने की सोचें, हर बात में शोभा लेने की बात करते हैं तो राजस्थान की एग्रीकल्चरल इकानामी को क्रिपिल करने के विषय में आप क्या करते हैं, इस पर मैं थोड़े बहुत विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह हमारी सरकार ने कभी चिंतित होकर सोचा नहीं, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि हमारी सरकार का आउटलुक ब्यूरोक्रेसी का आउटलुक है और ब्यूरोक्रेसी भी वह जो जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं। आप जब बजट बनाते हैं, नए करों का प्रावधान करते हैं तो आपको सोचना होगा कि आप कौनसे पर्टीक्यूलर सैक्टर में कितने रिसोर्सेज जुटाने की बात सोचते हैं। जिस काश्तकार की कमर पहले ही टूट चुकी है, उससे आप क्या आशा करते हैं? यह तो ठीक है कि बाजार में भी भाव बढ़ रहे थे जिसकी वजह से वह मार्केटिंग के बाद सरप्लस बचाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। आपने अपने विचारों से, अपनी कल्पना से, परिवर्तित परिस्थितियों के कारण एफ्लूएंट सोसाइटी का तबका समझ लिया। आपकी यह मान्यता बन गई कि राजस्थान का हर किसान कुलक है, हर किसान रेफ्रीजरेटर खरीद सकता है, कार खरीद सकता है उसकी आर्थिक क्षमता बहुत ऊंची हो गई है, उसका जीवन स्तर बहुत ऊंचा उठ गया है। आपने जब कभी भी अपने राजस्थान के रिसोर्सेज को मोबील इज करने की बात सोची तो केवल एग्रीकल्चरल सैक्टर को ही टच करने की बात सोची।

मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ आप उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और उद्योगों में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, राजस्थान में नये नये उद्योग लगें, इस उद्देश्य

(श्री सज्जन सिंह)
से नई नई सहूलियतें देना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपका दिया हुआ धन राजस्थान में उपयोग में न आकर दूसरे प्रदेशों में चला जाए, यह आश्चर्य की बात है। सवाई माधोपुर का सीमेंट का कारखाना पिछले 6 महीने से और उससे भी अधिक समय से बंद पड़ा है। आपका उत्पादन घटे, वहां मजदूर बेरोजगार हो जायं, उनके प्रति आपके सद्भाव आपके विचार, आपको कल्पना, आपकी योजना, आपका कार्य, आपकी कार्य क्षमता क्या है, इसका प्रदर्शन मैं इस बजट में देखना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह डिनाई नहीं करता कि आपके अपने रिसोर्सेज जुटाने के लिये आपको अपने सारे रिसोर्सेज को मोबेलाइज करना होगा। इससे राजस्थान का विकास अवरुद्ध नहीं होता, राजस्थान की प्रगति नहीं रुक सकती और मैं तो कहूंगा कि इससे राजस्थान की तरक्की कभी भी नहीं रुक सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अभी अभी सामन्तवादी ताकतों के हाथ से मुक्त हुआ है राजस्थान की जनता भी सारे आराम भोगेगी। मैं इसलिये वित्त मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता में बरदाश्त करने की क्षमता है लेकिन राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है जो अनपढ़ है जो सिवाय खेती के कुछ करते नहीं हैं, सिवाय खेती के उनके पास करने को दूसरा कोई धन्धा नहीं है, उस तबके को बार बार आप टच करते हैं पहले भी आपने उस तबके को टच किया। मेरी समझ में नहीं आता कि आप बार बार उस गरीब तबके को क्यों टच करते हो। आप बार बार उसी तबके पर टैक्स लगाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या समझ कर आप उस तबके पर टैक्स लगाने की कल्पना करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर पंजाब का किसान ज्यादा से ज्यादा टैक्स देता है या टैक्स देने की क्षमता अधिक रखता है तो मुझे कोई उससे एतराज नहीं होता। मान्यवर, अगर ऐसे ही कोई दूसरे प्रांतों के किसान ज्यादा से ज्यादा टैक्स देते हैं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है, मान्यवर, वह प्रान्त हैं जिनका उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा हुआ पहले से ही है क्योंकि प्रकृति की उन पर हमेशा से ही कृपा रही है। इसके अलावा हमने भी उनको दूसरे साधन खेती के लिये सिंचाई के उपलब्ध करा दिये जिससे वहां पर उत्पादन बहुत अधिक होता है। इसके अलावा, मान्यवर, वहां दूसरे भी इन्डस्ट्रियल बेस इतने बढ़े हुए हैं कि जिससे वहां पर तरक्की बहुत अधिक हुई है। उसे देख कर हमें आश्चर्य होता है। इधर आप हरियाणा के काश्तकारों को देखेंगे कि उन्होंने कितनी तरक्की की है तो आपको आश्चर्य होगा। मान्यवर, हरियाणा के किसानों को वहां के मुख्य मंत्री ने समृद्ध कर दिया। जब हम गांवों में बैठे हुए हरियाणा के किसानों के बारे में सोचते हैं तो हमें थोड़ा दर्द होता है कि हरियाणा और पंजाब की सरकारों की तुलना में हमारी सरकार क्या हमारे किसान को दे रही है? क्या फायदा हमारे किसानों को पहुंचा रही है?

मान्यवर जब मैं कृषि उत्पादन के आंकड़ों को, जो कि हमारा सांख्यकीय विभाग देता है, देखता हूं तो मुझे ऐसा दिखाई

(श्री सज्जन सिंह)

देखा है कि जिस वर्ष राजस्थान में वर्षा अधिक हुई, उस वर्ष राजस्थान में अधिक बाजरा हुआ, उस वर्ष राजस्थान में अधिक ज्वार हुआ। जिस वर्ष राजस्थान में अधिक वर्षा हुई तब हमारे यहां पर तिलहन भी बहुत अधिक मात्रा में हुआ। लेकिन जिस वर्ष राजस्थान में वर्षा कम हुई तो आपके यहां प्रोडक्शन में स्टीप फाल हुआ। आपका जो प्रोडक्शन का फिगर है उसमें कमी आयी। मान्यवर, इस वर्ष के आंकड़े आपके सांख्यकीय विभाग के देखने को नहीं मिले मैं यह तो मानता हूं कि आपका विभाग सांख्यकीय विभाग के माध्यम से यश की प्राप्ति करने में कमी नहीं रखता। उदाहरण के तौर पर जिस साल फ्लड आया उस साल हमारे यहां पर बाजरा बहुत अधिक मात्रा में पैदा हुआ बम्पर क्रोप हुई तो बहुत मात्रा में लेवी दी और आपने बफर स्टोक क्रियेट कर लिया लेकिन इस साल आपका सांख्यकीय विभाग आंकड़े स बारे में दे नहीं सका। वैसे तो, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि मन्त्री जी काफी आशावादी हैं। वह एक अच्छे समाजवादी हैं और जो समाजवादी व्यक्ति होता है वह आशावादी होता ही है। उन्होंने हमें कहा था कि खरीफ की फसल बहुत अच्छी होगी क्योंकि बहुत अच्छी वर्षा हुई है। लेकिन, श्रीमान्, आप जाकर देखें कि अब उस क्रोप में बीमारी लग जाने से उसका बन्टाढार हो गया है जब आपको पता चला कि बाजरे में बीमारी लग गयी है और उसे खाने से गेस्ट्रो-एन्ट्राइटिस की बीमारी हो जाती है तो आपने खुद ने उसे नहीं खाने की सलाह दी, और मान्यवर, आपको पता है, कि जब बाजरे में एक बार बीमारी लग जाती है तो वह रुक नहीं सकती। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जब आपको पता चला कि बाजरे में बीमारी लग गयी है तो क्या कर रहा था आपका पेस्टीसाइड सैक्शन आफ दी एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट? उसने क्या किया? इसी प्रकार, मान्यवर, इस साल भी फसल में कई जगह बीमारी लग गयी है मैं बहुत ही जिज्ञासा पूर्वक देख रहा हूं कि अब की बार आपका सांख्यकीय विभाग आंकड़े कैसे प्रस्तुत करेगा? मैंने खूब टटोला लेकिन मुझे वह पुस्तक नहीं मिली। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से आपका यह मोरल दृष्टिकोण होना चाहिये कि आप उत्पादन बढ़ायें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मन्त्रीजी को यह फिर निवेदन करना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि रबी की फसल बहुत अच्छी होगी, यह सही साबित नहीं होगा क्योंकि रबी की फसल में इस बार गेहूं में रोली की भयंकर बीमारी लग गयी है और रबी की फसल बरबाद हो चुकी है जो कि उनकी नोलेज में नहीं हालांकि आपके डिपार्टमेंट को पता लग गया था लेकिन आपका डिपार्टमेन्ट इसमें कुछ भी तकनीकी मदद नहीं कर सका। ऐसी तकनीकी राय है कि गेहूं में जब एक बार बीमारी लग जाती है तो वह रुक नहीं सकती। उस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। न केवल वह बीमारी एक ही खेत में फैलती है बल्कि वह सारे खेतों में फैल जाती है और, मान्यवर, वह कभी रुक नहीं सकती। तो मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि वह इस ओर ध्यान दें। उपाध्यक्ष महोदय, हमने ऐसा सुना, यहां माननीय सदस्य बता रहे थे कि आपने पेस्टीसाइड का छिड़काव जालौर जिले में सांचौर में करने की कल्पना भी की थी और वह पेस्टीसाइड का छिड़काव हेली कोप्टर से करना था। उपाध्यक्ष

(श्री सज्जन सिंह)

महोदय यह तो सही है कि आज के आधुनिक जो भी तरीके है उनके साधन तो राज्य सरकार के पास ही हैं और उनमें ही इसकी क्षमता होती है लेकिन बाद में वह आप नहीं कर सके। तो वित्त मंत्रीजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपने बजट बनाया है अगर वह आप अपने स्वयं के लिये, स्वयं के परिवार के लिये बनाते या राजस्थान के धनी सम्पन्न परिवार वालों के लिये बड़े बड़े उद्योगपतियों या बड़े बड़े व्यापारियों के लिये बनाते तो ऐसा बजट उचित होता आपने जो आपने आंकड़ों का माया जाल फैलाया है वह हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि पता नहीं आपने राजस्थान की जनता को क्या समझा, आपने राजस्थान की जनता के बारे में क्या सोचा शायद आप उसे बहुत ही सम्पन्न समझ गये होंगे। आपको मालूम होना चाहिये कि राजस्थान का किसान एक बहुत ही गरीब है। आपने क्या समझ कर फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ा दी, जब कि आप किसानों के खेतों में होने वाली बीमारी को रोक नहीं सके, आपने लगान पर सरचार्ज बढ़ा दिया आपने, ट्रैक्टर में कोई सब्सिडी नहीं दी, आपने सिचाई पर, बिजली पर, एग्रीकल्चर इनपुट्स पर पैसा बढ़ा दिया और आप प्रगतिशील और गरीब लोगों की हिमायती होने का दावा करते हैं। यह कैसे करते हैं मेरी सहज बुद्धि में तो यह बात आती नहीं। मैं आपके आंकड़ों के माया जाल से तो कुछ समझूंगा नहीं लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि राजस्थान की तरक्की होगी वह रुक नहीं सकती है। आपका यह कहना कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, मैं इससे प्रभावित नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, आज ही हाउस के मेम्बर्स में काफी हीट पैदा हो गयी थी जब एक प्रश्न के जवाब में आपने यह कह दिया कि हमारी तो मजबूरी है हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लीज होल्डर को यह काम करना चाहिये वह नहीं करता है तो हम क्या करें? मान्यवर, राष्ट्रीय उत्पादन भी राजस्थान का उत्पादन है उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है आपने घोषणायें की हैं कि प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ा है-वह भी मेरी समझ में नहीं आता, मैंने सतत प्रयत्न किया फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार आप इस ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से राजस्थान के गरीब तबके का भला करेंगे? आपने जो यह बजट बनाया है यह तो कोई भी ब्यूरोक्रेट प्रेसीडेन्ट रूल में बना लेता! आखिर हम लोग यहां पर क्यों आते हैं? क्या जरूरत है बजट बनाकर उस पर विचार-विमर्श करने की? मैं समझता हूं कोई आवश्यकता नहीं, आपका ऐसा बजट तो प्रेसीडेन्ट रूल में आपकी पार्लियामेन्ट पांच मिनिट में पास कर देती। आखिर यह प्रक्रिया बनाई तो किस लिये? मान्यवर, हम यह महसूस करते हैं कि हम इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचें और इस पर एक्शन लें। लेकिन हम यह महसूस करते कि आप यह सोचते हैं कि हम ही फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट वाले बजट बनाते हैं और हमारी ही जिम्मेदारी है बजट बनाने की, मैं मानता हूं यह सही है लेकिन आप बार बार एक ही सैक्टर को टच क्यों करते हैं? बार बार काश्तकार पर ही क्यों कर-भार लगाते हैं? इसमें आपको सोचना चाहिये।

मान्यवर, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो इन्सान में कमजोरियां होती हैं वह सारी की सारी

(श्री सज्जन सिंह)

कमजोरियां आप में भी हैं और उन कमजोरियों के कारण आप भावनाओं में बह जाते हैं और अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम कराते हैं। मान्यवर, अभी का उदाहरण मैं देना चाहता हूं मैंने वित्त मंत्रीजी से पूछा कि क्या आपके इलाके में फ्लड आते हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे यहां तो आंसुओं के फ्लड आते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप जाकर उस एरिया को देखें जहां पर फ्लड आया है, जहां पर हजारों लोग बह गये, हजारों मकान बह गये और लोग तबाह हो गये लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री महोदय ने उस दृश्य को जाकर एक बार भी नहीं देखा। उनको तो अपना चूरू का जिला ही दिखाई देता है। सबसे ज्यादा पैसा खर्च वह अपने ही इलाके पर करते हैं यह बात मैं जब करता हूं तो माननीय सदस्य मुझे कहेंगे कि क्षेत्रीयता की मैं बात करता हूं लेकिन बजट को देखने से पता चलता है कि ये क्षेत्रीय असन्तुलन की बातें आप करते हैं। इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, अभी चूरू जिला में नल की योजनायें पी. एच. डी. ने सभी जिले में नल का काम करीब करीब कम्पलीशन की स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सुमेरपुर चुनाव क्षेत्र भी राजस्थान का ही एक अंग है। वहां पर भी एक नल योजना, रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम, सन् 1972 में आपने स्वीकार की थी और वह अब तक धूल मिट्टी में पड़ी हुई है। वहां पर नल फेंक दिये गये, वहां पर बड़े बड़े हौद बना दिये लेकिन पानी उस कुए से बाहर नहीं निकाला गया। यही कृपा हुई आपके बिजली विभाग की जिस विभाग का एक स्वायत शासन संस्था दुरुपयोग करती है, जो बिलकुल भ्रष्ट तरीके करके दुरुपयोग करती है, जिस पर आपका डाइरेक्ट नियंत्रण नहीं है, फिर भी मंत्री महोदय इसके लिये कहते हैं कि आप स्पेसिफिक कम्प्लेन्ट लाइये, मैं जांच कराऊंगा और जो दोषी व्यक्ति होगा, उसको दण्डित किया जायगा। यह तो हम भी जानते हैं, हर साधारण व्यक्ति जानता है कि जांच में कोई चीज प्रमाणित हो जाये तो फिर भ्रष्टाचार जैसी चीज ही नहीं रहे। कई चीजों के बारे में जबानी कह देते हैं लेकिन जांच में सामने नहीं आते हैं और आपसे यह कहा जाय कि आप जांच करवा लीजिये और आप आश्वासन देकर हमें सन्तुष्ट कर दें तो आप विश्वास कर लेते हैं कि हम सन्तुष्ट हो गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मंत्री मण्डल के माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर देना चाहता हूं और अत्यन्त नम्रतापूर्वक निवेदन कर देना चाहता हूं जब कभी आप आश्वासन देते हैं तो आपको उसकी गंभीरता को इवेल्यूएट करना चाहिए। आपके आदेश कितने माने जाते हैं, आपके आदेशों की कितनी अनुपालना होती है, उनका एक्जीक्यूशन कौनसी मशीनरी कर है, उस मशीनरी का कितना कमिटमेंट है आपकी पालिसी की तरफ, ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखकर आपको आश्वासन देना चाहिये।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि सुमेरपुर की एक नल योजना जो सन् 72 में स्वीकार हुई थी उस पर अभी तक आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई...

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सदस्य आपकी वाणी का स्वर बदलिये · · ·

एक माननीय सदस्य : यही स्वर काम करेगा।

श्री सज्जनसिंह : हां, मैं सीखा नहीं, हां, मैं सीखूंगा नहीं, हां, मैं सीखने की इच्छा नहीं रखता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि ऐसे ही एक शुभ चिन्तक मित्र ने कहा था कि Silence is golden. और मैंने यह निवेदन कर दिया था– Timidity is not a virtue. और मैं अब पुनः यह निवेदन करता हूं कि अगर वाणी बदलने का तात्पर्य आप यह समझते हों कि मैं मंत्रियों के पीछे 50 चक्कर खाऊं, तो यह मैंने नहीं सीखा है। स्वाभिमानी व्यक्ति हूं और स्वाभिमान से जीना चाहता हूं। स्वाभिमान से जीना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है और उस स्वाभिमान को मैं किसी तरह खोना नहीं चाहता हूं। मैं जनता का चुना हुआ एक प्रतिनिधि हूं और उस नाते मैं यह महसूस करता हूं कि आज जिस कुर्सी पर आप लोग बैठे हैं, कल सम्भवतः मेरी इच्छा या नेता बने तो मैं भी उस कुर्सी पर बैठ सकता हूं। तो यह वाणी बदलने की बात, स्वर के बदलने की बात नहीं हो सकती है। मैं भिखारी बनकर यहां नहीं आया हूं–जनता का प्रतिनिधि बनकर यहां आया हूं जो सुनना चाहते हैं, सुनें और जो नहीं सुनना चाहते है, नहीं सुनें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना यह अधिकार समझता हूं और आपकी कृपा समझता हूं कि आप मुझे सुनाने का अवसर भी देते हैं · · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ++

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : Please don,t intrrupt.

श्री सज्जनसिंह : मैं आचरण में उसी संहिता का हमेशा विचार रखता हूं जो एक अच्छे पार्लियामेन्टेरियन में होनी चाहिये। मैंने किसी माननीय सदस्य को और किसी मंत्री को कभी डिस्टर्ब नहीं किया, चाहे वे कितने ही शुभ चिन्तक हों और मैं भी इस चीज को कभी टालरेट नहीं करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं प्लानिंग में कोई डिफेक्ट है, फन्डामेन्टली डिफेक्ट है और इसके मैंने बुनियादी कारण भी निवेदन कर दिये कि आप भी ह्यूमन बींग हैं और ह्यूमन वीकनेस से ग्रसित हैं और उसी से प्रभावित होकर आप कह देते हैं कि चुरू जिला ही उपेक्षित रहा है और जब कभी मुख्य मंत्री कहते हैं तो कह देते हैं बांसवाड़ा क्षेत्र उपेक्षित रहा है– यह मनुष्य की स्वभावजन्य कमजोरी है। बांसवाड़ा वाले बांसवाड़ा की सोचेंगे और चूरू वाले चूरू की ही बात सोचेंगे और जो दूसरे मंत्री हैं वे भी अपने अपने क्षेत्र की ही बात सोचेंगे · · · ·

श्री लूणाराम सारण : चूरू में सारा चूरू नहीं है केवल मात्र सरदार शहर है।

श्री सज्जन सिंह : यह आपका दृष्टिकोण है।

मैंने पहले ही निवेदन किया और मैं आपसे कर बद्ध प्रार्थना करता हूं कि कृपा

XX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेश से निकाले गये।

(श्री सज्जन सिंह)

पूर्वक मुझे सुनें, जो समय दिया गया है, जिसकी सीमायें मैं जानता हूं और जिसकी परिधि के बाहर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैंने वह सीखा नहीं और उस समय के अन्दर ही मुझे आपके समक्ष अपने विचार प्रकट करने का अवसर दीजिये।

मनुष्य अन्य कमजोरियों से ग्रसित है और हमारे माननीय मंत्री मण्डल के सदस्य जब बजट बनाते हैं, जब अलोकेशन करते हैं, जब डिपार्टमेंटल अलोकेशन करते हैं तब उन्हें यह भूल जाना चाहिये और याद रखना चाहिये कि this is the Government of the people, by the people, for the people और उसमें आप अगर इस तरह से भी असन्तुलन की बात सोचेंगे तो हार्टबर्निंग व कहीं न कहीं होगी। कोई न कोई तो हिम्मत करके कहेगा। चाहे बहुत से माननीय सदस्य उस बात को महसूस करते हों किन्तु कहने की हिम्मत नहीं रखते हों, वह बात और है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं इस साल के बजट में सोशियल सर्विसेज के बारे में। 200 मिडिल स्कूल खोलने का प्रावधान रखा है। बड़ी खुशी की बात है आपने 1500 अध्यापक प्राइमरी स्कूलों की देन का प्रावधान रखा है, यह भी बड़ी खुशी की बात है कि आप गांवों में अध्यापकों को भेजेंगे लेकिन हम जानते हैं कि ये 200 स्कूल ऐसी जगह खोलेंगे जहां पर आपके चहेते लोग होंगे, जहां पर आपके विभाग के अधिकारी केवल मात्र आपकी विम पर चलते हों, जहां पर आपको अपना फेवरेबल आदमी मिलेगा, वहां पर मिडिल स्कूल खुलेंगे और वहां पर ही अध्यापकों की नियुक्ति की बात की जायेगी। रीज-नल बेसिस पर जहां पूर्ण इस बात की आवश्यकता है, वहां इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता है और अगर यह ध्यान दिया जाता तो आपके बजट में ऐसे प्रोविजन्स होते कि आप केवल मिडिल स्कूल खोलकर ही सन्तोष नहीं कर लेते हैं। क्या राजस्थान की जनता को हायर सैकेन्डरी स्कूल की आवश्यकता नहीं है? क्या राजस्थान की जनता को कालेजों की आवश्यकता नहीं है? क्या राजस्थान की जनता को डिग्री कालेजों की आवश्यकता नहीं है? और क्या राजस्थान की जनता को टेक्निकल और पोलो टेक्निकल स्कूलों की आवश्यकता नहीं है? एक तरफ आप यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक सोशियल सर्विसेज दें और दूसरी तरफ उनके लिए रिसोर्सेज की बात सोचते हैं? टैक्सेशन को आप ऐसे सैक्टर पर लगाने की कल्पना करते हैं जो आलरेडी बहुत दबा हुआ है, जो आलरेडी बहुत ज्यादा ग्रसित है, जो आलरेडी अनआर्गेनाइज्ड है, जो बिल्कुल म्यूट और सबमिसिव है और विश्वास करते हैं इन्डस्ट्रीज के लोगों पर जो आर्गेनाइज्ड हैं, जो फीडिंग करना जानते हैं, जो अन-करप्ट को करप्ट करना जानते हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें हिम्मत की आवश्यकता होती है, उसमें एक हौंसले की आवश्यकता हुआ करती है। वह हिम्मत और हौंसला मैं इस वर्ष के बजट में नहीं देखता। कल मेरे एक मित्र माननीय सदस्य ने यह कहा कि भई, यह प्रिइलैक्शन बजट नहीं है। हर काम इलैक्शन के दिनों में ही करते हैं, पांच साल सो जाते हैं, पांच साल ब्यूरोक्रेसी के भरोसे सो जाते हैं। यह मेरी बुद्धि में आता नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित

(श्री सज्जन सिंह)

करना चाहता हूं कि हमारा बजट एक कल्याणकारी समाज का बजट होना चाहिये। प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि हम गरीब की हालत सुधारना चाहते हैं। हर जगह 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, जनमानस पर यह छाप डालने की कोशिश की कि हम देश की उन्नति चाहते हैं, गरीब को ऊपर उठाना चाहते हैं, उसका उत्थान करना चाहते हैं। पहले भी कल्पना इसकी की थी। अब कौनसी नयी बात हो गयी? जिस दिन से प्रधान मंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की, दुहाई तो उसकी बहुत बड़ी देते हैं, परन्तु उनकी अन्य नीतियों के विषय में जब मैं देखता हूं तो आपकी नीति बिलकुल ढिलमिल लगती है। उन नीतियों का प्रदर्शन मैं इस बजट में नहीं देखता हूं तो मुझे दुःख के सिवाय और हो ही क्या सकता है।

मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता था कि आपने प्रशासनिक सेवाओं को सुधारने की बात भी बजट भाषण में कही है और बड़े गर्व के साथ यह घोषणा की है कि दो हजार से अधिक कर्मचारियों की छुट्टी की है और 200 से अधिक अधिकारियों की छुट्टी कर दी है। लेकिन मैंने बार बार इस पवित्र सदन के प्रांगण में यह आरोप लगाया है लैंड रेवेन्यू के बारे में एक आर.ए.एस. अधिकारी ने 4 हजार बीघा जमीन पर मेरे क्षेत्र में कब्जे कर लिया सीलिंग का कानून खूंटी पर धर दिया। चार दफा इन्क्वायरी हो गई और इन्क्वायरी रेवेन्यू कमिश्नर 6 महीने से दबाकर बैठा है उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो मैं यह कैसे मान लूं कि अधिकारियों की आपने छुट्टी की है, उनकी बिलकुल निष्पक्ष होकर छुट्टी कर दी है? हो सकता है उनके अन्दर बेचारे ऐसे गरीब अधिकारी होंगे जिनका पक्षधर नहीं था उनका गला घोंट दिया हो। जब भारत सरकार ने निर्देश दिये कि उनकी अपील की गुन्जाइश रखनी होगी तो आपने भी घोषणा की कि आप भी अपील सुनेंगे। हो सकता है, बहुत से आदमियों के प्रति बड़ा अन्याय हुआ हो तो यह कैसे विश्वास कर लें कि आपने प्रशासन को गतिशील बना दिया है? आपने उसको बड़ी भारी सुधारने की कोशिश कर दी और आपने खर्चे में बड़ी भारी कटौती कर दी? मैं देखता हूं जीपें हैं, पैट्रोल मंहगा हो जाने के कारण हर अधिकारी को जीप की आवश्यकता है। एक तरफ तो माननीय मंत्री महोदय गरीब को उठाना चाहते हैं, गरीब तबके का उत्थान करना चाहते हैं और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी के पर्टीकुलर सैक्शन को सारी सुविधायें उपलब्ध कर दीं, उनके बैठने के लिये एक गाड़ी न होकर डीजल की 50/56 हजार की, मैं तो सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता हूं, उनको देंगे और वह राजस्थान में दौरा करते फिरेंगे। आंकड़े जो सदन में बताते हैं वे सारे झूंठे हैं। सारे बेबुनियाद हैं। हो सकता है कुछ पर्सेन्टेज सही भी हों। लेकिन मुख्यतः यह आरोप हम लगाते हैं। आप प्रशासन में खर्चा घटाना चाहते हैं तो यह जो अनुत्पादक खर्चे हैं, गाड़ी कर्मचारी, पंचायत समिति, कम्युनिटी डवलपमेंट के जब आपने उस आयडियोलोजी, फिलोसफी को खूंटियों पर धर दिया, जब आपने उसको कोल्ड स्टोरेज में धर दिया, आप यह महसूस करते है कि ये डिफन्क्ट हैं, डेड हैं, बेकार हैं, फेल हो चुकी हैं, फिर क्या वजह है बारह बारह वर्ष तक चुनाव नहीं कराते हैं, फिर क्या

(श्री सज्जन सिंह)

प्रमुख, प्रधानों का मेला भरवाते हैं ? जयपुर में क्यों बुलाते हैं ? क्यों उनकी तनख्वाह बढ़ाते हैं ? पहले दो सौ रुपया देते थे उसी प्रधान को अब तीन सौ रुपया देते हैं । अब मैं यह पूछता हूं, भाई, आपके जिम्मे काम क्या है तो सिवाय प्राइमरी टीचर्स को तनख्वाह बांटने के और कुछ काम विकास अधिकारी, जो एक्सटेन्शन ग्रेड का अधिकारी है, वेदर फ्रोम एग्रीकल्चर और फ्रोम एनीमल हस्बेन्डरी, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव नहीं, शिक्षा में माहिर नहीं, हाई स्कूल के टीचर होंगे या प्रमुख शिक्षक होंगे, इस प्रकार बंटाधार पांच छः वर्ष में हो गया क्योंकि पंचायत समितियां डिफंक्ट हो गयीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल नहीं रहा । अगर आप यह समझते हैं कि पंचायती राज को नहीं चलाना चाहते हैं तो इसको समाप्त कर दीजिये । जब हम यह मांग करते हैं कि चुनाव क्यों नहीं होते हैं तो पंचायत मंत्री सगर्व खड़े होकर वहां भाषण झाड़ देते हैं कि चुनाव की कल्पना तो केवल एक फासिस्ट सरकार ही कर सकती है । समझ में नहीं आता है कि जब हमारी प्रधान मंत्री स्वयं यह कहती हैं कि Democracy is the only type of Government that is suited to this country. दूसरी तरफ चुनाव कराने से कतराते हुए उसके एक्जिस्टेन्स को नहीं बता सकते और यह कह देते हैं कि यह तो फासिस्ट मनोवृत्ति का सूचक है । तो फिर उनको घटाया जा सकता था, करोड़ों रुपयों के खर्चे का सही उपयोग किया जा सकता था, उन कर्मचारियों को दूसरे विभागों में लगाया जा सकता था टीचर्स को स्कूलों के सुपुर्द किया जा सकता था । जिला स्तर पर यदि पांच इन्सपेक्टर है तो छः कर दीजिये । जब आप यह महसूस करते हैं कि यह अनउपजाऊ फौज है कर्मचारियों की, जब आप यह महसूस करते हैं कि ग्राम सेवकों की अनउपजाऊ फौज है, कुछ नहीं करती है, उनमें क्या प्रशासनिक सुधार कर दिया, क्या गति लादी गयी इस बजट में इसका दिग्दर्शन मैं कहीं कुछ नहीं देखता ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहने को बहुत बातें हैं लेकिन अब मैं आपकी नजरों की तरफ देखता हूं तो मैं यह महसूस करता हूं कि मैं शायद अपनी सीमा अवधि को लांघ रहा हूं । इसलिये विशेष निवेदन नहीं करते हुए मैं हमारे वित्त मंत्री महोदय का ध्यान अनुत्पादक खर्चे की ओर दिलाते हुए इतना ही कह कर संतोष कर लूंगा कि इस पर पुनर्विचार कीजिये । इस पर गम्भीरता से पुनर्विचार करना चाहिये । यह कोई मर्यादा का प्रश्न नहीं है इसको आपको संतुलित बजट बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । आपने उस सैक्टर को राहत दी है जो सैक्टर एफ्लुएन्ट कहलाता है, वह सैक्टर जो मेन्युपुलेशन कर सकता है, जो टैक्सों की चोरी कर लेता है । किसान बेचारा कौनसा सरचार्ज और लैंड रेवेन्यू बचा लेगा ? वसूली के लिये तो आपने कहा कि सख्ती से वसूली की । श्रीमान्, सांडेराव में चार हजार बीघा जमीन पर कुछ गुंडे तत्वों ने कब्जा कर लिया । सीलिंग के बारे में बोलते हुए 20 बार निवेदन कर चुका हूं कि जब तक उस जमीन को आप भूमिहीनों में वितरित नहीं कर देते हैं तब तक मैं राजस्थान पर कलंक मानता हूं । उस कलंक को धोने की व्यग्रता आपने नहीं बताई लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि उस भूमि का लगान

Page No 42

(४२)

(श्री सज्जन सिंह)

कितने वर्षों का बाकी है। चार हजार बीघा नहरी जमीन का पिछले पांच साल से लगान वसूल नहीं किया गया और आपने यह बड़ा गर्व किया है कि हमने बड़े जोश-खरोश से वसूलियां की हैं। हां, गरीब लोगों को आपने परेशान किया है इसमें कोई सन्देह नहीं है। जो बेचारे डरते हैं, जो पटवारियों से डरते हैं, मिनिस्टर्स की कार और झण्डी देख कर तो उनके हौसले पस्त हो जाते हैं, उन लोगों के ऊपर तो जरूर सख्ती है लेकिन ऐसे जो लुटेरे हैं समाज में, जो कि डकैत हैं, गुण्डे हैं, बदमाश हैं उन लोगों को आपने टच नहीं किया और उनको इसलिए टच नहीं किया क्योंकि उन्होंने कोई न कोई जामा पहन रखा है, किसी न किसी की शरण ले रखी है, किसी न किसी का हाथ पकड़ रखा है, किसी न किसी के चरण छू लिये हैं। इसके कारण अभी तक वसूलियां नहीं हुई।

श्रीमान्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके बजट में जो आपने किसान की कमर तोड़ने की कल्पना की है उस पर आप पुनर्विचार कीजिए। 8 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, राजस्थान के घाटे को बहुत फुर्ती के साथ मिटाने वाली बात नहीं है। उस घाटे की पूर्ति आप अन्य जगह से कर सकते हैं। अगर आप बिजली रेट्स इन्डस्ट्रीज में और वह भी ऐसी इन्डस्ट्रीज में जो कि टैक्स की चोरी करते पकड़ी गयी हैं, जो आज दिन भी अपना उत्पादन नहीं बढ़ा कर किन्हीं न किन्हीं कारणों से मेनुपुलेट करके फैक्ट्री को बन्द कर देते हैं, लेबर को बेरोजगार कर देते हैं–उन लोगों से अधिक वसूल करते, उनके ऊपर आप उत्पादन कर लगा देते तो भी मेरी समझ में आता। इसलिए मैं बहुत नम्रतापूर्वक, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्रपोजल्स पर पुनर्विचार होना चाहिए, पुनः इस पर्सपेक्टिव में विचार होना चाहिए कि राजस्थान का गरीब किसान जो बड़ी मुश्किल से कुछ पैदावार करने की क्षमता बना पाया है जिसको सरकार ने पानी तो दिया लेकिन पानी भी उसको पूरी जमीन में नहीं दिया, सर्टेन पर्सेन्टेज में पानी दे दिया और उसकी इन्टेन्सिटी कभी सोचते हैं और कभी रेट्स बढ़ा देते हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मान्यवर फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि वह जमीन सांडेराव की कभी न कभी तो आप लेंगे ही उन लोगों से, और कभी न कभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों में वितरित करेंगे उस जमीन पर आप किस बात की रिजर्व प्राइस लेना चाहते हैं और अगर आप रिजर्व प्राइस लेंगे गरीब आदमियों से जिनकी गरीबी आप मिटाना चाहते हैं तो वह रिजर्व प्राइस कहां से देंगे? कहां से कर्जा लायेंगे? कौनसी एजेन्सी ऐसी है जो कि आपको पैसा चुका देगी? कौनसी ऐसी एजेन्सी आपने कायम कर दी जिसकी वजह से वह आप का कर्जा चुका दें? उसके बाद वह बीज भी लाये, हल भी लाये और दूसरी चीजें भी लायें और अपना उत्पादन भी बढ़ायें और जीवन स्तर भी बढ़ाय। इन बातों पर आपको गम्भीरता से विचार करना होगा। आपको यह सोचना होगा कि आप ऐसे तबके का पक्ष कर रहे हैं अपने बजट में जो कि पहले ही एफ्लुएण्ट हैं, जो मनी

(श्री सज्जन सिंह)
लैण्डिग का धंधा करते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया होता तो समझ में आता।

आपने भांग पीने वालों पर टैक्स लगाया, आपने शराब पीने वालों पर टैक्स लगाया—यह बात तो समझ में आई लेकिन आप सिनेमा देखने वालों से कहते हैं कि वहां पर बहुत भीड़ लगती है। तो भीड़ तो हजारों भिखारियों की लगती है और सिनेमा के सामने कोई रोटी तो मिलती नहीं है जो जायें। वहां इस बात को भीड़ लगेगी कि कुछ अच्छा समय गुजार दें। शायद उनको रहने के लिए अच्छे मकान नहीं हैं, शायद उन्होंने जिन्दगी में कभी कूलर की हवा नहीं खाई, शायद उन्होंने कभी जिन्दगी में आराम कुर्सी पर बैठ कर उसके सुख और सुविधा का आनन्द नहीं लिया हो इसलिए वह घन्टे दो घन्टे आराम से गुजार देना चाहते हैं उनके ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया। यह तो आपने बड़ी उपलब्धि की लेकिन आपने मनी लैन्डर्स पर टैक्स नहीं लगाया, आपने एफलुएन्ट लोगों पर टैक्स नहीं लगाया, आपने उन इन्डस्ट्रीज को अनटच्ड रखा जिनको आप शायद प्रोत्साहित तो करना चाहते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी आप जानते हैं कि the greatest tax evaders in Rajasthan are the industrialists. जो कि यहां से पैसा ले जाकर दूसरी इन्डस्ट्रीज कायम करेंगे, बीस जगह अपने एकाउन्ट्स रखेंगे और उन एकाउन्ट्स में मेनुपुलेट करेंगे जो कि आज आर्गेनाइज्ड हैं, जिनका कि चेम्बर है और जिनकी लाबीज बाकायदा चलती हैं, जो कि आपके पास एप्रोच कर सकते हैं। उन लोगों को आप टच नहीं करते। इस बात का दर्द है मुझे और मैं चाहता था कि मैं आपको सुनाऊं। मुझे विश्वास है आपने सुना तो है, विचार तो आप करेंगे नहीं और राहत आप कुछ देने वाले हैं नहीं और जवाब भी मैं जानता हूं आप नहीं देंगे क्योंकि एक माननीय सदस्य ने मुझे याद दिलाया था कि तुम्हें अपनी वाणी बदलनी पड़ेगी और उसके लिए मैंने यह कहा था Silence is golden, which I have not learnt till now.

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मला कुमारी।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने इस वर्ष का जो अनुमानित बजट पेश किया वह वास्तव में देखने में बड़ा ही आकर्षक प्रतीत होता है। उन्होंने इसके स्वरूप को जो आकर्षक बनाया है उसके लिए मैं वित्त मंत्रीजी को बधाई देती हूं। परन्तु जब हम इस बजट को पढ़ते हैं और इस पर गहनता से विचार करते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि यह बजट बहुत ही परम्परावादी बजट है। वही पुराना ढांचा, वही पुराना राग। केवल इसमें आंकड़े ही बदल दिये गये हैं।

इस वर्ष हमारी प्रगतिशील जो नीतियां हैं, बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम है, कई लोग इस बजट से उन नीतियों की पूर्ति की आशा लगाये बैठे थे। मान्यवर, आपने अपने बजट में इस बीस सूत्री कार्यक्रम का स्पर्श तो किया है इसके बारे में कुछ संकेत तो दिया है परन्तु फिर भी बीस सूत्री कार्यक्रम का वास्तविक अर्थ क्या है उसके बारे में प्रकाश नहीं डाला। बीस सूत्री कार्यक्रम का वास्तविक अर्थ यही है

(श्री निर्मलाकुमारी शक्तावत)

कि समाज में जो व्याप्त असमानता है उसे दूर किया जाये । बजट के माध्यम से किस प्रकार से असमानता दूर करेंगे, किस प्रकार से गरीबी मिटाने की बात करेंगे और किस प्रकार से आप विकास के लिए प्रावधान करेंगे इसकी ओर संकेत नहीं है । जो हमारा राजस्थान प्रान्त है जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है यदि इसमें इसी प्रकार का बजट पेश होता रहा और वही पुराने आंकड़े जोड़ तोड़ कर रखे जाते रहे, वही लाभ हानि की व्यवस्थ की जाती रही तो मान्यवर हमें तरक्की करने में बहुत लम्बा समय लग जायेगा ।

मान्यवर, मैं एक बात यह भी कहना चाहती थी कि इस बजट में आपने यह बताया कि शुद्ध लाभ 18 करोड़ 64 लाख का है और इसकी पूर्ति के लिए 8 करोड़ के टैक्स लगाये हैं । परन्तु इस टैक्स का भार किसके ऊपर पड़ेगा । इसके ऊपर आपने गौर किया है ? इन करों का प्रत्यक्ष रूप से तथा अप्रत्यक्ष रूप से भार जनता के ऊपर पड़ेगा, वह गरीब जनता जिसका विश्वास ही हमारी एक मुख्य धरोहर है यदि हमने इस विश्वास को खो दिया तो हमारा जो प्रजातान्त्रिक ढांचा है वह आज की स्थिति में नहीं रहेगा, उसका स्वरूप कुछ विकृत हो जायेगा । अतः मैं यह कहना चाहती थी कि खास तौर से जनता का विश्वास ही हमारी धरोहर है और उसे संभाल कर रखना है ।

मान्यवर, आपने अपने बजट में मूल्यों की गिरावट की बात भी की । मूल्यों का गिरना सन्तोषप्रद स्थिति है लेकिन कुशल अर्थशास्त्री की निगाह से यह बात छिपी हुई नहीं है । अतः मूल्यों में गिरावट बहुत ज्यादा हो और मूल्यों में बढ़ोतरी भी बहुत ज्यादा हो तो यह दोनों ही स्थिति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती । आज इस समय राजस्थान में किसानों के द्वारा जो कुछ उत्पादन होता है उसका मूल्य सूचकांक, जो ग्राफ है, वह दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है । यदि इस प्रकार की स्थिति रही, किसानों के द्वारा पैदा की जाने वाली वस्तुओं के भाव निरन्तर गिरते रहे तो हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था डगमगा जाएगी । हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था विकृत हो जाएगी । हमें खास तौर से जो खाद्यान्न तथा वाणिज्यिक फसलें हैं उनकी ओर ध्यान देना होगा । एक किसान कार्मशियल क्रोप इसलिए बोता है कि साल भर के लिए वह कुछ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रोटी कपड़े का जुगाड़ कर सके । परन्तु निरन्तर खाद्यान्नों के साथ साथ कैश क्रोप भी गिरती जा रही हैं, तिलहन है, कपास है, गन्ना है सब के भाव निरन्तर गिरते जा रहे हैं । तो इसलिए राज्य सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा कि किसानों को उनकी जो पैदावार है उसका उत्पादन मूल्य तो मिले ही परन्तु साथ ही साथ उनको पारिश्रमिक भी मिले । यदि पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, उत्पादन मूल्य से भी कम जहां फसल बिकेगी तो क्या स्थिति होगी, मान्यवर, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं । हमने बहुत लम्बे समय से बफर स्टाक की बात की । कई बार बफर स्टाक के बारे में इस सदन में सुझाव भी दिए गए हैं । आज इस वर्ष में जब कि फसल बहुत अच्छी है हम बफर स्टाक जमा लें । परन्तु मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि किसानों के पास जो अनाज है उसको कोई भी खरीदने वाला

(श्री निर्मला कुमारी शक्तावत)

नहीं है। बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत आपने भूमि सुधारों के बारे में बात की। सीलिंग से प्राप्त जो भूमि है उसको आप भूमिहीनों को बांट देंगे। बड़े लम्बे चौड़े आंकड़े प्रस्तुत किए गए कि इतनी भूमि हमें सीलिंग से मिल जाएगी और इतनी भूमि भूमिहीन व्यक्तियों को बांट देंगे। परन्तु, मान्यवर, जरा आप गौर कीजिए, क्या कभी आपने यह सोचा है कि जो जमीन मिल रही है वह किस प्रकार की है। सीलिंग के द्वारा जो प्राप्त भूमि है, भूमिपति वही जमीन देता है जो उसके पास निकृष्ट होती है और खास तौर से उस स्थान पर जो सामान्य जमीन है, जो सामान्य जमीन की किस्म है उसको नहीं देकर गई गुजरी जो जमीन होती है उसको देता है। तो ऊपर से तुर्रा यह है कि इसका तीस गुना मुआवजा जो आपको भूमिपति को देना है वह किसानों से लेकर देना चाहते हैं। कहां गया वह बीस सूत्री कार्यक्रम ? कहां गया वह गरीबी हटाने का उद्देश्य ? मैं निवेदन करना चाहती हूं, मान्यवर, कि सीलिंग की भूमि को किसान लेने के लिए तो आता है परन्तु उसकी कीमत सुन करके जो कि वहां पर सामान्य तौर पर जो भूमि की कीमत है उससे बहुत अधिक होने के कारण वह स्वतः ही भूमि लेने से मना कर देता है, निराश होकर लौट जाता है। तो इतनी भयंकर जो परिस्थिति है उसमें सुधार लाना होगा। अच्छा होता कि आप इस पर ध्यान देते, आपको बजट में यह प्रावधान करना चाहिए था कि किसानों को जमीन मुफ्त देने के लिए आप एक विशेष प्रकार की व्यवस्था करते। मैं तो यह भी सुझाव देना चाहूंगी और कई दफा पहले भी दे चुकी हूं और आज फिर भी यह सुझाव देना चाहूंगी कि आप जो भूमि आवंटित करते हैं तो उसके साथ ही साथ वह साल भर तक आसानी से फसल पैदा कर सके उसके लिए भी आपको धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए। आप धनराशि दीजिए जिससे कि वह खाद की, बीज की और अन्य प्रकार की व्यवस्था कर सके, तभी जा करके बीस सूत्री कार्यक्रम सफल हो सकेगा।

मान्यवर, एक और निवेदन करती हूं और वह यह है कि सिंचाई की दरें जो हैं वह भी आपने बहुत अधिक बढ़ा दी हैं। इस समय गरीब किसान के ऊपर पहले ही बहुत अधिक भार है। रसायन खाद की बढ़ी हुई कीमतें, ऊपर से उसकी फसल में भी बहुत ही मन्दी चल रही है और फिर ऊपर आपने सिंचाई की दरें भी बढ़ा दीं और खास तौर से आपने बहुत अधिक सिंचाई की दर जो है वह गन्ने पर बढ़ाई है। मान्यवर, मैं उस क्षेत्र से आती हूं जो गन्ना उत्पादन बाहुल्य क्षेत्र है। गन्ने की कीमत के बारे में कई बार मैं इस सदन में अपनी बात पेश कर चुकी हूं, पिछली बार भी यह बात निवेदन कर चुकी हूं और आज फिर निवेदन कर देना चाहती हूं कि गन्ने का मूल्य जो है, वहां की भोपालसागर शुगर मिल है उसका साढ़े दस रुपया निश्चित किया गया है जब कि पिछले वर्ष साढ़े बारह रुपया वहां गन्ने का भाव था। इस प्रकार का अन्तर आखिर क्यों हुआ ? अब इस समय बहुत रो धोकर 11 रुपया 75 पैसे गन्ने का भाव निश्चित किया है। कैसी करुण दास्तान है, मान्यवर। किसान अपने सामने लकड़ी को 20) रु. क्विन्टल

Page No 46

(४६)

(श्री निर्मला कुमारी शक्तावत)

बिकते हुए देखता है जब कि वही गन्ना जो कि उसने अपने खून पसीने से पैदा किया है उसकी कीमत उस लकड़ी से आधी है। इस प्रकार की दयनीय स्थिति है। अगर इस प्रकार की दयनीय स्थिति रहती है तो हम किसानों की स्थिति को नहीं सुधार सकेंगे और बीस सूत्री कार्यक्रम हमारा सफल नहीं हो सकेगा। मंत्री महोदय से भी कई बार बातचीत हुई। वह कहते हैं कि भारत सरकार के द्वारा गन्ने का भाव निश्चित किया जाता है। तो क्यों नहीं आप भारत सरकार से यह बात करते हैं कि इस प्रकार गन्ना जो है उसकी कीमत सही हो नहीं तो गन्ना उत्पादन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आपने ऊपर से सिंचाई की दरें और बढ़ा दीं। तो मैं तो यह कह सकती हूं कि आपने वह स्थान जो कि राजस्थान का क्यूबा बन सकता था लेकिन आपने गन्ना उत्पादन कम करें इस ओर संकेत दिया है। यदि आप सिंचाई की दरें उस समय बढ़ाते जब कि सिंचाई की वर्तमान व्यवस्था में कुछ सुधार करते तब भी मैं यह बात मान सकती थी। वास्तव में सिंचाई की जहां पर कच्ची नहरें हैं, जहां पर दलदल हैं, जहां पर मच्छर और मलेरिया की समस्याएं हैं वहां पर यदि आप व्यवस्था ठीक करके सिंचाई की दरें बढ़ाते तो स्वागत योग्य था परन्तु आपने इस समय जो सिंचाई की दरें बढ़ाई है, जहां पर वास्तव में कोई भी सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है तो ऐसी स्थिति में सिंचाई की दरें बढ़ाना स्वागत योग्य नहीं है। मान्यवर, या तो आप वर्तमान में जो सिंचाई की व्यवस्था है उसमें सुधार लाइये या सुधार नहीं ला सकते हैं तो यह आपने जो दरें बढ़ाई हैं उनको कम करिये वरना यह व्यवस्था एक किसान के लिए भूचाल वाली स्थिति पैदा कर देगी।

मान्यवर, आपने कर बढ़ाने के लिए देश में बनने वाली विदेशी किस्म की जो शराब है उसके ऊपर भी बिक्री कर बढ़ाया है और वह बढ़ा कर बीस पर्सेन्ट से 25 पर्सेन्ट कर दिया है। ठीक है, यह बात स्वागत योग्य है परन्तु क्यों नहीं आपने इस 25 के स्थान पर 50 पर्सेन्ट बढ़ा दिया। इससे सम्भव था कि हमारे बजट का संतुलन भी बढ़ सकता था. परन्तु आपने यह नहीं बढ़ाया। मान्यवर, राजस्थान के बजट में इस समय 17 करोड़ 46 लाख के करीब आबकारी से आय होती है। उस आय को वित्त मंत्रीजी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसे छोड़ते हुए बड़े हिचकिचाते हैं। मैं इन मंत्रीजी को यह याद दिलाना चाहती हूं कि, 1931 में गांधी इर्विन समझौते की इन मंत्रीजी को याद दिलाना चाहती हूं हमारे नीति निर्देशक तत्व की। उनमें किस की ओर संकेत किया है। यदि इस प्रकार की अवस्था रही, इसी प्रकार से धन अर्जित करते रहे तो समाज विकसित नहीं हो सकता। वह धन हमारे किस काम का जो शारीरिक, पारिवारिक और राष्ट्र के विघटन के बाद पैदा होगा। वह धन हमारे किस काम का जिसमें कई घर में चिराग नहीं जलें। वह धन हमारे किस काम का जिसमें कई महिलाएं अपने तन को नहीं ढक सकें और सुकुमार कलियां फूल बनने के पहले ही मुरझा जायं। इसी संदर्भ में मैं करों के संबंध में एक बात और निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने दवाइयों पर, तैयार कपड़े पर और लाइट डीजल पर जो कुछ छूट दी है निःसंदेह इससे गरीबों को राहत

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

मिलेगी। परन्तु मंत्री महोदय जो है वह विलासिता से जीवन बिताने वाले व्यक्तियों को राहत देना भी नहीं भूले। और तभी तो रेफ्रीजरेटर और एयर कन्डीशनर्स के ऊपर उन्होंने कर की छूट दी है। यद्यपि यह सत्य है कि हमारे जो पास के स्टेट्स हैं उनमें बिक्री कर कम है और यहां पर इन चीजों का ज्यादा है परन्तु इस समय क्या आवश्यकता आ पड़ी? क्यों इस प्रकार कर कम किया और हमारे बजट को असंतुलित आकार दिया गया?

मान्यवर, मनोरंजन कर आपने बढ़ा करके एक सामान्य व्यक्ति के मनोरंजन के अधिकार के ऊपर भी आघात किया है। वित्त मंत्रीजी ने सिनेमा घरों के सामने जो भीड़ खड़ी रहती है उसको देख करके ही यह कल्पना कर ली कि ये सारे के सारे समृद्ध व्यक्ति हैं और सारे के सारे व्यक्ति मनोरंजन कर दे सकते हैं। परन्तु यह सिनेमा देखने वाले सभी व्यक्ति समृद्ध व्यक्ति नहीं हैं। वहां वे व्यक्ति भी आते हैं जो दिन भर की थकावट से, दिन भर की परेशानी से, दिन भर की चिन्ताओं से मुक्त होकर सस्ता मनोरंजन करना चाहते हैं तो, मान्यवर, आप अपर क्लास के टिकिट बढ़ाइये जहां पर कि समृद्ध लोग बैठते हैं परन्तु वह क्लास जहां पर कि निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग बैठते हैं, वहां पर कर की छूट आपको देनी होगी।

अब मैं बजट के उस पक्ष पर आती हूं जिसमें कि आपने व्यय का प्रावधान रखा है किन-किन मदों पर किस-किस प्रकार कितना-कितना व्यय होगा? सिंचाई और विद्युत् के ऊपर 105.50 करोड़ रुपये व्यय होंगे। यह हमारे बजट का 60 प्रतिशत होगा। यह कदम सराहनीय है। क्योंकि विद्युत और सिंचाई ही वह धुरियां हैं, वह गाड़ी के पहिये हैं जिनके ऊपर चल कर हमारे प्रान्त के विकास की गति को बढ़ाना है। सिंचाई की योजनाएं तो कई हैं, वे आपकी अधूरी हैं। 17 वर्ष पहले राजस्थान कैनाल के काम को शुरू किया था, पर कितना हुआ? मान्यवर, सिंचाई के कार्य और विद्युत् के कार्य राजस्थान की सभी भौगोलिक स्थिति को देख कर करना होगा और उसके दक्षिणी भाग को भी आपको नहीं भूलना होगा। दक्षिण भाग में केवल उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ही नहीं आते हैं। दक्षिणी भाग में चित्तोड़ भी आता है जहां पर कि पिछले चार वर्षों से व्यथित चातक पक्षी की तरह बिजली का इन्तजार कर रहे हैं। वे आस लगा कर बैठे हैं। उन्हें विद्युत् के कनेक्शन नहीं देंगे तो उनकी यह आशा निराशा में परिणित हो जायेगी। मैं आशा करती हूं कि इस बार आपके बजट में कम से कम उनकी आशा है, उसको निराशा में परिणित नहीं करेंगे। सिंचाई के बारे में यह निवेदन करना चाहती हूं कि चित्तौड़ में सिंचाई की कई योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। चित्तौड़ वह स्थान है, जहां पर कि देश की राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए कई व्यक्तियों ने बलिदान किया है। आज भी आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए यह जिला अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। यदि आप इनको बिजली और सिंचाई की सुविधा देते हैं, तो आर्थिक क्रान्ति के लिए आप उनका रास्ता साफ करेंगे, उनका रास्ता प्रकाशमान करेंगे।

बजट में आपने श्वेत क्रान्ति की बात कही है। श्वेत क्रान्ति ही क्यों? तीनों

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

क्रान्तियां हरित, श्वेत और पूरी औद्योगिक क्रान्ति करनी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस बार भी आपने एक करोड़ से भी अधिक उद्योगों के ऊपर राशि की कमी कर दी है। उद्योगों के विकास के लिए एक करोड़ कम करने का क्या औचित्य था? यह समझ में नहीं आता है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को आप केवल खेतों में ही नहीं खपा सकते हैं। इसको खपाने के लिए आपको उद्योग लगाने होंगे। उदयपुर संभाग, जहां पर कि अरावली की शृंखलाएं हैं, उनके अन्दर मूल्यवान मिनरल्स छिपे पड़े हैं। वहां पर विविध उद्योग क्यों नहीं लगाते? आपने ने विविध उद्योगों से अपना कितना विकास कर लिया है। परन्तु हमारे झामरकोटडा को रॉक फास्फेट और सलादीपुरा की पाइराइट्स अभी भी ऐसी ही पड़ी हुई है। क्या हम इनका उपयोग कर उद्योग का विकास नहीं कर सकते? इसके साथ ही, मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में लाइम स्टोन भरा पड़ा है। इसके लिए केवल दो सीमेन्ट फैक्ट्री ही लगाई गई हैं, वे अपर्याप्त हैं। वहां पर कई सीमेन्ट फैक्ट्री बना कर आप अपने प्रान्त की आवश्यकता को ही नहीं, देश की आवश्यकता को ही नहीं परन्तु विदेश को निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। मेरा अभिप्राय कहने का यह है कि इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये साथ ही वन सम्पदा, दक्षिणी राजस्थान में है वह बहुमूल्य सम्पदा है। इसके आधार पर, वन सम्पदा पर आधारित उद्योग भी आप लगा सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान में अधिकांशतः आदिवासी लोग रहते हैं। उन्होंने गरीबी को छाया में जन्म लिया है और जो भाग्य रेखा में उलझे हुए हैं, इन आदिवासियों का भाग्य परिवर्तन वन सम्पदा के माध्यम से, उस पर आधारित उद्योगों की स्थापना कर के, आप कर सकते हैं। इस ओर आपने ध्यान नहीं दिया है और बजट प्रावधानों को भी आप कम करते चले गये हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को आप किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे, किस प्रकार उसकी व्यवस्था करेंगे? इसके बारे में सोचना जरूरी है। इसके लिए कुटीर उद्योगों को विकसित करना चाहिये। उनको इन्सेन्टिव देने के लिए आपको एक विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि आपने विद्युत् की दर में एक पैसे की वृद्धि की है। 5 पैसे से 6 पैसा बढ़ाया है क्यों नहीं आप इसको दस या पन्द्रह पैसे कर दें जिससे उद्योगों के विकास के लिए आपको अधिक धनराशि मिलती। परन्तु इसकी ओर आपने नहीं सोचा है। इसके अलावा आपने बड़े उद्योगों को संरक्षण दे रखा है, जो चोर बाजारी करते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनकी रेट्स बढ़ानी चाहिये।

मान्यवर, एक निवेदन यह और करना चाहती थी कि इस वर्ष आपने एप्रोच रोड के ऊपर एक विशेष धनराशि का प्रावधान रखा है। यह प्रगति का प्रतीक है क्योंकि सड़कों का विकास प्रान्त के विकास की धुरी है। इसका विकास बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर के विकास के लिए जिस प्रकार नाड़ी यन्त्र को भी व्यवस्थित करना होता है उसी प्रकार प्रांत के विकास के लिए सड़कों का विकास जरूरी है। हमारे प्रांत का ध्यान इस ओर अभी तक बहुत कम गया है। न्यूनतम

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जो सड़कें बनाई गई वह केवल थोड़ी बहुत बनी हैं और वे भी अधूरी पड़ी हुई हैं अकाल राहत कार्यों के अन्दर केवल वहां पर मिट्टी डलवा दी गयी। उसके बाद, समय के परिवर्तन के साथ-साथ वह मिट्टी भी वहां से उड़ गयी और अब वहां पर जाकर देखा जाय तो यह सड़कें न रह कर सड़कों के मात्र अवशेष रह गये हैं। इनको आपको सुधारना होगा। यह जो सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं, इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर, उन पर ध्यान देना चाहिए। इस बार बजट में प्रावधान रखा गया है, आशा है इस ओर आप अपना ध्यान मोड़ेंगे।

मरु विकास मण्डल और आदिवासी विकास बोर्ड की स्थापना की गयी है। यह सराहनीय कदम है और मैं इसका स्वागत करती हूं क्योंकि राजस्थान में आये दिन अकाल पड़ते हैं और इस अकाल का स्थायी हल ढूंढा जाना चाहिए। पिछले दशक का इतिहास देखें तो मालूम होता है कि करीब डेढ़ अरब रुपया इस पर व्यय किया गया है। दस वर्षों में अगर यही डेढ़ अरब रुपया ठीक तरह से स्थायी कार्यों पर व्यय होता तो संभव था कि हम अपने प्रान्त से अकाल की छाया को रोक सकते थे। परन्तु फिर भी देर से आये तो समझ गये, दुरुस्त आये इसलिए यह जो कदम उठाया है इसका मैं स्वागत करती हूं।

सामाजिक सेवाओं, जिसमें शिक्षा चिकित्सा तथा पीने की पानी की व्यवस्था आदि शामिल है, इसका भी आपने बजट में प्रावधान रखा है। शिक्षा पर आपने 80.34 करोड़ रुपया, चिकित्सा पर 21.15 करोड़ रुपये तथा पेय जल के लिये 21.73 करोड़ रुपये रखे हैं। मान्यवर, शिक्षा शब्द में बहुत आकर्षण छिपा है। शिक्षा शब्द के उच्चारण के साथ ही हमारे दिमाग में एक स्वर्णिम रेखा खिंच जाती है जिसमें भविष्य का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। परन्तु शिक्षा के बारे में अभी तक आपका परम्परावादी दृष्टिकोण है, वह मिटा नहीं है। व्यवसायिक शिक्षा का गाना गाते मुझे चार वर्ष हो गये हैं परन्तु हम व्यवसायिक शिक्षा को टालते जा रहे हैं। कह देते हैं बजट अलाऊ नहीं करता है। हमारे पास इसके लिए पैसा नहीं है। दस×दो×तीन की शिक्षा की जो बात थी उस पर भी एक धुंध छा गई है। 55 वर्ष पहले कलकत्ता विश्व विद्यालय ने इस प्रकार की शिक्षा पद्धति के बारे में लोगों को जानकारी दी थी। इस पर एक पीढ़ी गुजर गई अब जाकर सिद्धान्ततः आप सहमत हुए हैं परन्तु फिर भी इसको कब लागू करेंगे, यह बात साफ नहीं है। यह बात समझ में नहीं आती है। आखिर कब आप हमारे राष्ट्र के भावी नागरिक के जीवन के हितों को सुरक्षित करेंगे। कब उनके भविष्य के बारे में एक निश्चित वातावरण बनायेंगे।

मान्यवर, राजस्थान में आपने स्कूलों के भवनों की इमारतों के लिए, रख रखाव के लिए, परिवर्तन करने के लिए 50 लाख रुपयों का प्रावधान रखा है। एक बात यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह रख रखाव के कार्य, भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य कहां पर होंगे? केवल शहरों में, महाविद्यालयों के भव्य भवनों के निर्माण में। गांव के व्यक्ति को तो आप यह बात कह कर छोड़ देते हैं कि आपको ये सारे कार्य जन सहयोग से करने हैं?

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

इन मूढ़, अशिक्षित असंगठित ग्रामीणों को जन-सहयोग का पाठ कब तक पढ़ाते रहेंगे, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। आज हमारे प्रान्त की जनसंख्या के अनुपात को हम देखें तो 80 पर्सेन्ट ग्रामीण जनता है तो केवल 20 पर्सेन्ट के लिए ही हम सारी सुविधाएं जुटाते जा रहे है और 80 पर्सेन्ट की उपेक्षा करते आ रहे हैं। यह ग्रामीण और नगरीय भेद कब तक बना रहेगा। कब तक आप उनकी उपेक्षा करते रहेंगे? इसलिए मेरा यह सुझाव है कि आप रख-रखाव और भवन-निर्माण के लिए जो धन-राशि खर्च करने जा रहे हैं उसमें 80 और 20 का रेश्यो होना चाहिए तभी जाकर आप जनता के साथ में न्याय कर सकेंगे।

200 मिडिल स्कूल खोलने की बात आपने कही है। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप शिक्षा की शृंखला को मिडिल तक ही क्यो सीमित रखना चाहते है? आपने 72–73 में 1500 मिडिल स्कूल खोलने की बात कही फिर सो की बात कही। फिर 50। आपने मिडिल स्कूलों का तांता लगा रखा है। आप सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी की बात ही नहीं सोचते है। क्या आप हमारी भावी पीढ़ी को मिडिल तक ही सीमित रखना चाहते हैं? आपको बजट में सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी की तरफ ध्यान देना चाहिए। कालेज और महा विद्यालय की तरफ ध्यान नहीं दें तो कोई बात नही है पर सैकेण्डरी स्कूल पर पहले ध्यान दें। आपने सबजेक्ट्स खोलने के लिए विशेष प्रकार का प्रावधान रखा है, लेकिन सबजेक्ट्स भी आप व्यवसायिक शिक्षा सम्बन्धी खोलते तो कितना उपयुक्त होता लेकिन उस ओर आपका ध्यान ही नहीं जाता।

मान्यवर, इसी के सम्बन्ध में मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में एक मिलिट्री टाइप सैनिक स्कूल चलाया जा रहा है उसका सारे का सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार वहन करती है, लेकिन राज्य सरकार का भी उसमें कुछ शेयर होता है। राज्य सरकार को स्टूडेन्ट्स को स्कालरशिप के लिए पैसा देना पड़ता है, परन्तु राज्य सरकार हमारी कई मदद दे रही है। वहां पर किस प्रकार की स्थिति है उसके बारे में कई पेरेन्ट्स आकर मुझसे मिले और माननीय मुख्य मंत्रीजी जब उस स्कूल में पधारे थे उस समय वहां के प्रिन्सीपल ने स्कूल में स्पीच दी वह मैंने सुनी बड़ी दर्दनाक थी। उन्होंने कहा कि हमारे इस स्कूल के पास में सीमेंट फैक्ट्री है तो सीमेन्ट की धूल, एक तरह की डस्ट है वह वहां पर फैल जाती है, जिसके बारे मे कई बार मैं सदन में निवेदन कर चुकी हूं वह उन बच्चो के लिए हानिकर है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अभी तो इन्डस्ट्री के लिए कह रही थीं।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : उस डस्ट को आज के वैज्ञानिक युग में कन्ट्रोल किया जा सकता है। डस्ट कन्ट्रोल प्लान्ट लगाकर आप उसको एक तरह से रोक सकते हैं। परन्तु डस्ट कन्ट्रोलर की बात नहीं होती है। मैंने पिछली बार विधान सभा में प्रश्न किया था परन्तु मंत्रीजी ने उत्तर दे दिया कि डस्ट कन्ट्रोल प्लान्ट लग गया है, लेकिन वहां अभी तक नहीं लगाया है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि डस्ट कन्ट्रोल प्लान्ट के माध्यम से उसको रोका जा सकता है।

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

इसलिए मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि वहां पर एक केन्टीन चलती है तो उस पर भी सैल्स टैक्स लगा रखा है। देश में 17 सैनिक स्कूलों की केन्टीन पर सैल्स टैक्स नहीं है, परन्तु चित्तौड़ में चलने वाली केन्टीन पर सैल्स टैक्स लगाया हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है? चित्तौड़गढ़ शक्ति तथा भक्ति का प्रतीक है और वहां पर स्थित सैनिक स्कूल वहां का गौरव है। यदि वहां से सैनिक स्कूल हट जाय क्योंकि वहां का सारा स्टाफ यह चाहता है कि यहां पर सैनिक स्कूल ठीक नहीं है, तो चित्तौड़ नगर ही नहीं प्रान्त को इससे बहुत नुकसान होगा। तो बजट में राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इसीलिए, मान्यवर, मैं बहुत अधिक निवेदन न करके अन्त में बजट का स्वागत करना चाहती हूं, क्योंकि इसमें चिकित्सा और पेय जल के लिए विशेष प्रकार का प्रावधान रखा गया है जो कि एक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है, इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतीराम यादव।

श्री चतुर्भुज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी

श्रीमती सुमित्रा सिंह : रतीराम यादव का नाम ले लिया है।

श्री रतीराम यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य का 76-77 का बजट हमारे सामने सदन में माननीय वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है। इस बजट को पढ़कर मैं कई दिनों से लगातार यही सोचता रहा हूं कि इस बजट को क्या संज्ञा दी जाय? माननीय वित्त मंत्रीजी को इतना सुन्दर बजट पेश करने पर किन शब्दों के अन्दर मैं धन्यवाद दूं, किन शब्दों से उनकी प्रशंसा करूं? यह मेरी समझ में अभी तक नहीं आया है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो बजट पर जो हमारी इच्छा, आकांक्षाएं वर्तमान समय में, मौजूदा हालत में 20 सूत्री प्रोग्राम के चलते हुए हम अपने हृदय में संजोये हुए थे उन सब आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया गया है। यह बजट समाजवादी व्यवस्था लाने वाला बजट नहीं होकर उसी तरह से एक पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक बजट माननीय वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, और मुझे इस बात के कहने में कोई आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि माननीय वित्त मंत्रीजी जिस वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं उनको इसी तरह का बजट सदन में लाना चाहिए था चाहे आज किन्हीं कारणों से वे उन पांतों के अन्दर बैठे हैं जो पांतें, जो वर्ग किसान और मजदूरों की समाजवादी व्यवस्था लाने वाला है, जो समाजवाद की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। उनके अन्दर बैठकर और कुछ मीठे नारे लगाकर, कुछ वेष समाजवादी व्यवस्था के ढंग के बदलकर वह बेसिक कुछ बातें बतायें, लेकिन दरअसल जो असली रूप है उनका जिनके लिए उन्हें संरक्षण देना चाहिए उन्होंने अपने वर्गहित को ध्यान में रखा है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट है यह पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था लाने के अन्दर जो वर्ग गरीब होते हैं ऐसे गरीब किसानों और मजदूरों और पिछड़े वर्ग के ऊपर जो उन्होंने भारी टैक्सों का बोझ लादा है इस बजट में मैं समझता हूं उन्होंने इन वर्गों पर हमला किया है।

(श्री रतीराम यादव)

मान्यवर, इस बजट के द्वारा हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वही काम किया है जैसे कि कोई आदमी दूसरे के कन्धे पर रखकर बन्दूक चलाता है, लेकिन अगर जब बन्दूक अपने कन्धों पर रखें तो उनको महसूस होगा कि उस बन्दूक में कितना वजन है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने वर्गहितों की रक्षा की है, लेकिन इनके वर्ग से जो आदमी लड़ते हैं, जिनका संघर्ष है इस बात के अन्दर उन किसानों और मजदूरों के ऊपर, उन हरिजनों के ऊपर, भूमिहीनों के ऊपर इन्होंने टैक्सों का जो भारी बोझ लादा है तो उसकी एक वजह है। वजह क्या है, मान्यवर, आज हम जो पूंजीवादी जगत के अन्दर आर्थिक संकट देखते हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था के अन्दर आर्थिक संकट आया हुआ है, उस अपने वर्ग के आर्थिक संकट को गरीब वर्गों के ऊपर डालने की इसके अन्दर उन्होंने कोशिश की है। जो कि अखिल भारतीय पैमाने पर की जा रही है विश्व के पैमाने पर की जा रही है पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीपति वर्ग के द्वारा हमारे राज्य के अन्दर, माननीय वित्त मंत्रीजी ने उसी का परिचय दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट इस रूप में मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रधान मंत्रीजी का 20-सूत्री प्रोग्राम है उसको पूरा करने वाला बजट नहीं है। यह बजट एक प्रकार से उस 20-सूत्री प्रोग्राम को फ्लाउट करने वाला है। चाहे मजबूरन अथवा देश के अन्दर जो एक आम फिजां फैली हुई है उसके कारण, और जो हमारे यहां पर 20-सूत्री प्रोग्राम के तहत कुछ काम हुए हैं, कुछ कानूनों में तब्दीलियां हुई हैं, बेशक कुछ अच्छे काम हुए हैं, इसलिए इनके असर के तौर पर, और चाहे कुछ उन्होंने बजट में प्रावधान किये हैं, लेकिन सब के अन्दर दिखाई नहीं पड़ता है जो कि उनका स्वरूप है, जो उनकी विचारधारा है। दिखाई यही पड़ रहा है कि किसी प्रकार की अगर उन्होंने राहत देने का सोचा भी है या अनायास ही वह राहत दे दी गई तो वही उसके पीछे भावना है। मैं आगे यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि किस तरह से इन्होंने इस 20-प्वाइण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत इस भावना को परिलक्षित किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह घाटे का बजट है। मैं समझता हूं कि घाटे का बजट प्रस्तुत करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन देखना यह पड़ेगा कि घाटा कैसे पेश किया गया है? घाटा किस लिए रहा है? हमारा घाटा आखिर किस कारण है? हम समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं। हम समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं। समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाना चाहते हैं। उनके लिए विशेष खर्च हमको करना पड़ रहा है। इसलिए हमें बजट के अन्दर घाटा रहा है। और, इन वर्गों पर हम किसी प्रकार का टैक्स का बोझ नहीं लादते हैं। इसके बाद कुछ घाटा रहता है तो वह समझ में आने वाली बात है। लेकिन जहां घाटे का बजट पेश किया जाता है, उस घाटे की पूर्ति कैसे हो, प्रश्न यह भी देखना पड़ता है। घाटे की पूर्ति करने के लिए हम साधन ढूंढते हैं। हमें उनके लिए साधन ढूंढने चाहिए। जब हमको समाजवाद लाना है तो जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, अभी तक जिनको आजादी आने के बाद कुछ मिला नहीं है, ऐसे लोगों को कुछ देने की बात करते हैं, राहत पहुंचाने की बात करते हैं।

(श्री रतीराम यादव)

दूसरी तरफ जो ऊंचा वर्ग है। जिसने हमेशा शोषण किया है। उनसे कुछ छीनने की बात करते हैं, उनसे कुछ लेकर ऐसे गरीब वर्ग को देने की बात करते हैं। तो फिर अगर घाटा रहता है तो समझ में आ सकता है। मान्यवर, दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि घाटे के बजट को पूरा करने के लिए अगर हम अपने राज्य की स्थायी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगर कोई कल-कारखाना लगाते हैं जिनसे स्थायी रूप से हमारे राज्य की आमदनी बढ़े, बार-बार घाटे का बजट नहीं पेश करना पड़े तो भी बात समझ में आ सकती है। लेकिन इस बजट में केवल वित्त मन्त्रीजी ने टैक्सों के आधार पर इस घाटे को पूरा करने की बात कही है। वह यह समझते हैं कि हम आमदनी बढ़ाने के लिए...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक-सूचक-घण्टी)

(गण पूर्ति के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : यस प्लीज।

श्री रतीराम यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय वित्त-मंत्री जी ने बड़ी चतुरता से इस बजट को बनाया है। और यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि मैं राजस्थान को अब कर्ज से दबाना नहीं चाहता हूं। इसलिए इन्होंने बड़ी-चतुरता के साथ अनेक प्रकार के टैक्स लगा कर इस घाटे को पूरा करने का प्रयत्न किया है। अपने वर्ग को, अपने वर्ग के हितों को बचा कर गरीब लोगों पर लगाकर फिर आमदनी दिखाने का प्रयत्न किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देकर स्पष्ट करूं कि ऐसा हुआ होगा। किस तरह से उनकी मनोवृत्ति ऐसे टैक्सों से विकास कार्य करने की दिखाई पड़ती है। मिसाल के तौर पर मैं 20 प्वाइण्ट प्रोग्राम की बात कहूं। हमने सबसे पहले अभी कहा है, सबसे पहली बात भूमि सुधार की कही है। भूमि सुधार के अन्दर सीलिंग को लागू करें तो जो सरकार की दूसरी जमीन पड़ी है। ऐसी जमीन को भूमिहीनों को बाटेंगे। यह 20-सूत्री प्रोग्राम का पहला सूत्र है। अब हमें देखना है कि इस 20 प्वाइण्ट प्रोग्राम में वित्त मंत्री जी ने बजट में क्या क्या प्रावधान किया है। मैं अलवर जिले की एक मिसाल दूं। अलवर जिले में 88 हजार बीघा जमीन बांट दी गई है, लेकिन गरीब हरिजन की स्थिति नहीं है कि जमीन मोल ले सकें। इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया कि हम सरकारी जमीन को फ्री बांट देंगे। लेकिन वहां क्या हुआ। जो ऐसी जमीन पड़ी थी हरिजनों को 125 रुपये में दी गई। दूसरे जो सिवाय चक थी वह फ्री दी गई। वह दूसरे लोगों को दी गई है। मैं निवेदन करूंगा कि एक को पैसा देने की हैसियत हो सकती है दूसरे को पैसा देने की हैसियत नहीं है। मान्यवर, सरकारी जमीन चाहे वह कस्टोडियन की नहीं है। आज वह केन्द्रीय सरकार की नहीं है। ऐसी जमीन का रेट इतना ऊंचा रखना, यह किस मनोवृत्ति का परिचायक है। मान लीजिए, पैसा भी लेना था तो भी उसका पैसा पहले के मुकाबले ज्यादा लगाया गया है। हमारे जिले में पट्टेदारों को जमीन मिली। उसकी कीमत ठीक बता दें। शरणार्थियों को भरतपुर जिले में जो जमीन मिली उसका रेट 36 रु.

(श्री रतीराम यादव)

सबसे पहले कीमत ली गई। उसके बाद उसको डबल करके 72 रु. फी स्टैण्डर्ड हिसाब से उनको दी गई। मैं बता रहा हूं, 36 रु. बीघा में। सरकारी जमीन वह कस्टोडियन लैण्ड 625 रु. बीघा के हिसाब से 9,000 गुनी ज्यादा रेट गई। वह गरीब हरिजनों से वसूल की गई है, अलवर जिले में जिसका नतीजा यह हुआ 50% से ज्यादा जमीन अभी बेकार पड़ी है। क्योंकि हरिजन कहां से पैसा लायेंगे। आपने 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम को पूरा करने के लिए क्या प्रावधान रखा है? क्या आपने ऐसी कोई बात की है? फ्री लैण्ड हरिजनों को दी जाये या वह कीमत ली जाये यह नहीं। आप उन लोगों की मदद करने को तैयार हैं। उनको शेयर करने को तैयार है। जैसा कि आपने हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी में रखा है इस तरह से जमीन अलाट करें तो 1 रु. ले लें। या 10 रु. ले लें। इस तरह से लैण्ड मिलेगी। 300 रु. एडजस्ट कर लिया जाएगा, अगर कोई प्रावधान होगा।

इन भूमिहीनों को जो जमीन दे रहे हैं उस वर्ग को आप सचमुच में राहत पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा, मान्यवर, जहां इस बजट के अन्दर हम किसानों की मदद की बात करते हैं, जहां पर हम किसानों को राहत पहुंचाने की बात करते हैं तो वहां पर हमने क्या किया, सिंचाई की रेट बढ़ा दी, वह किस आधार पर बढ़ा दी। इस आधार पर और इसलिए कि हमारे दिमाग में यह बात है कि हम इसमें प्रधान मंत्री का उदाहरण देते हैं और इस बात को अच्छी तरह से साबित करने के लिए या उस कमजोरी को छिपाने के लिए कह देते हैं कि किसान खुशहाल हो गये हैं, उनकी बड़ी अच्छी हालत हो गयी है, इसलिए किसानों को भी कुछ त्याग करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है और मैं भी मानता हूं कि किसानों की हालत पहले से सुधरी है, उनकी हालत सुधरनी भी चाहिए, आखिर हमारे देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, कुछ अच्छे काम हमारी सरकार ने किये हैं और तरक्की के काम भी किये गये, इनसे कोई इन्कार करने की बात नहीं है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी अच्छे काम हुए हैं, उन अच्छे कामों का लाभ किस प्रकार से और कितने गरीब किसानों को मिला, कितने मजदूरों को, कितने हरिजनों को और गरीब आदमियों को मिला है। इनको अधिक लाभ मिला है या इनका जो शोषण करने वाले बड़े-बड़े इजारेदार लोग हैं, बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, बड़ी-बड़ी जमीनों के मालिक हैं, कई मिलों के मालिक हैं, उनको मिला या गरीब किसानों को मिला। प्रधान मंत्री ने तो ठीक कह दिया, हालत तो पहले से सुधरी है, लेकिन इन बड़े-बड़े लोगों के मुकाबले में उन गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों की हालत कितनी सुधरी है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस रूप में आप किसानों पर टैक्स लगाकर अपने मकसद को हल करना चाहते हैं उस रूप में किसानों की हालत नहीं सुधरी है। अभी किसान उस वर्ग के मुकाबले और आमदनी में ताकतवर नहीं हो पाया है, अभी उसके पास इतने साधन नहीं हैं, जितने मिल मालिकों के पास हैं, जितने इजारेदारों के पास हैं, और राजा महाराजाओं के पास में हैं, उनके मुकाबले में किसानों के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर आप किसानों की तरफ टैक्सेज बढ़ाते हैं तो

(श्री रतीराम यादव)

आपकी निगाह ऊपर की तरफ भी जानी चाहिये।

आपने सिंचाई की दरें बढ़ा दीं। मैं समझता हूं कि सरकार बढ़ाये लेकिन दूसरी तरफ तो देखिये कि इस दर के बढ़ाने से किसानों को आप क्या सहुलियतें देना चाहते हैं। यह भी आपको सोचना चाहिए राजस्थान के किसानों के लिए जहां गन्ना पैदा होता है, गन्ने की मिलें लगी हुई हैं। 26 लाख रुपया किसानों का मिल-ओनर्स की तरफ बकाया है, वह तो कम से कम चुकता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चीनी और गन्ने का सीजन बीता जा रहा है। यह पिछले साल का 26 लाख रुपया बकाया है जिसके लिये किसान लोग रो रहे हैं। राजस्थान में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर किसानों का करोड़ों रुपया चीनी मिलों में बकाया है। अगर आप सिंचाई की दरें बढ़ाते हैं तो आपको इस तरह भी देखना चाहिए और मैं तो कहूंगा चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। कोई भी उनका पैसा इस तरह से प्राइवेट की तरफ बकाया नहीं रहे या सरकार की तरफ नहीं रहे इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए। आपने सिंचाई की दरों को बढ़ा दिया इसके अलावा भी आपने दूसरे कार्य सामने रखे हैं। आपने जितना भी किसानों के ऊपर कोआपरेटिव का कर्जा है उसको वसूल करने के लिये भी सख्ती से डन्डा हाथ में लिया है। इधर किसानों की फसल की रेट गिर रही है। आठ-दस महीने से किसान बराबर परेशान है कि उसकी पैदावार के भाव बराबर गिरते जा रहे हैं और उसके मुकाबले में जो सामान उसको लेना पड़ता है कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिये, उसके भाव बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात को तो आप छोड़िये, उसको जिन्दगी बिताने के लिये और दूसरा सामान भी लेना पड़ता है, उसको भी कपड़े और चीनी की जरूरत पड़ती है, सीमेन्ट की जरूरत होती है, आप उन बातों को भी छोड़ दीजिये, मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो कृषि की पैदावार को बनाने के लिये सामान की जरूरत होती है, उसको डीजल चाहिए, उसको बिजली चाहिए उसको उर्वरक चाहिए, रासायनिक खाद चाहिये, क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि उनके रेट्स कहां पर हैं। किसानों की उपज का आधा भाव भी नहीं रहा, 60 रुपये मन के गेहूं के भाव आज 40 रुपये आ गये हैं और जो 35 रुपये मन से 16 रु. मन बिक रहे हैं कैसी अजीब स्थिति है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसान की पैदावार की रेट के मुकाबले और किसान को कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिये जो सामान चाहिये आपने उसी तरह के रेट्स बनाये हुए हैं उनको आपने डाउन लाने का कोई प्रयत्न किया नहीं इसलिए किसानों के ऊपर ज्यादा टैक्स की तलवार चला रहे हैं। ऐसी हालत में कैसे यह मान लिया जाय कि यह जो आपका बजट है वह समाजवादी व्यवस्था का बजट है या आपका समाजवादी दिमाग है या बीस सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने में आपकी कोई निष्ठा है। आप किसानों को, मजदूरों को और गरीब लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं राजस्थान के अन्दर निश्चित रूप से तो इस बजट के आंकड़े देखने से तो यह साबित होता है कि माननीय वित्त मंत्री जी, अभी चाहे आपके मन के अन्दर वजन पड़ रहा हो लेकिन आपका दिल और दिमाग

Page No 56

(56)

(श्री रतीराम यादव)

पूरी तरह से वैसा ही है जैसा कि पहले था, उसमें किञ्चित् मात्र भी बदलाव मुझे दिखाई नहीं देता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की रेट्स का सवाल है। यह आपने घरेलू बिजली की रेट्स 5 से 6 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पीछे आपकी क्या भावना है। वैसे कहने को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि 5 से 6 पैसा ही तो किया है और वह भी घरेलू बिजली के लिये। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपने 5 से 6 पैसा कर दिया जो घरों में बिजली का उपयोग करते हैं, उसमें आपने बढ़ाया है लेकिन किस पर इसका बोझ पड़ेगा, आम आदमियों के ऊपर इसका बोझ पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो टैक्स आपने घरेलू बिजली पर बढ़ाया है इसको वापिस ले लेना चाहिए और अगर आपको इसको लगाना ही है तो मैं आपको बताता हूं आप पावर टैक्स लगाइये। घर में यूज होने वाली बिजली पर क्यों लगाते हैं, पावर पर लगा दीजिये। पावर की जो बिजली यूज करते हैं जिनकी हैसियत ज्यादा है या जो बीच की हैसियत वाले हैं जो अदा कर सकते हैं और घरेलू लाइट जो गरीब के भी घर में बल्ब टिमटिमाता है उसको तो सभी इस्तेमाल करते हैं आम आदमी भी करते हैं। इसलिए अगर आप गरीबों को ऊंचा उठाना चाहते हैं और बीस सूत्री कार्यक्रम को पूरा करना चाहते हैं, गरीबों को कुछ राहत करना चाहते हैं तो आपको इसको वापिस ले लेना चाहिए। और आप लगाना ही चाहते हैं तो पावर पर लगा दीजिये अथवा आपकी जिद ही है कि टैक्स लगाना है तो आप दूसरे ढंग से यह टैक्स लगा सकते हैं, आप ग्रेडेड टैक्स लगा दीजिये। मान लीजिये कि कोई बीस मिनिट तक बिजली जलायेगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जायेगा और उसके ऊपर जलायेगा तो उस पर इस प्रकार से टैक्स लगाया जायगा, इस तरह का आप कोई स्तर कायम कर दें, कि 50 मिनिट तक इतना और सौ मिनिट तक इतना टैक्स लगेगा और बीस-तीस मिनिट पर टैक्स नहीं लगेगा। आप इस तरह से इस स्तर से टैक्स लगायेंगे तो आपकी जो जिद है कि 5 पैसे से 6 पैसा करना है घरेलू बिजली पर तो आप उसको ग्रेडेड ढंग से लगा दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बीस पाइन्ट प्रोग्राम में एक बड़ा अच्छा सूत्र है कि देश के अन्दर जो बुनकर समाज है उसकी हालत बड़ी दयनीय है। जब से मिल लगी, उनका धन्धा चौपट हो गया। इसलिए बुनकरों की हालत सुधारने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, उसके लिए हम कोई प्लान लायेंगे। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वित्त मंत्री जी ने इतना तो जरूर इसके अन्दर कहा है बजट में इस तरह कोरपोरेशन, बोर्ड बना दिया है। सम्पत राम जी उसके अध्यक्ष भी बना दिये हैं। ठीक है, यहां तक संतोष की बात है। लेकिन केवल इससे संतोष नहीं होगा। संतोष उस वक्त, राहत उस वक्त मिलेगी बुनकरों को, उस गरीब समाज को, जिसका धन्धा करघा चला कर रोजी कमाना था, जब उसके लिए आप प्लान लायेंगे। अभी भारत सरकार ने एक प्लान तैयार किया है और उसके तहत इस धन्धे के कुछ ट्रेनिंग सेन्टर खोलेगी। इससे बुनकर समाज

(श्री रतीराम यादव)

को कुछ अच्छी दस्तकारी के कार्य सिखाये जायेंगे । लेकिन राजस्थान के अन्दर इस तरह का सेन्टर नहीं खोलेंगे । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, केवल इससे काम नहीं चलेगा कि केवल आपने बोर्ड बना दिया । संतोष की बात तो तब होगी तब आप सोच लेंगे कि बीस पाइन्ट प्रोग्राम के अन्दर बुनकरों को राहत देनी है। तो राजस्थान के अन्दर भी इस तरह का ट्रेनिंग सेन्टर खोलना चाहिए, उसके अन्दर लोगों को धन्धा सिखाना चाहिए । इसके साथ जो बुनकरों का धन्धा है, उनके साथ में सस्ती रेट का वह जो माल बनायें, उसकी बिक्री के लिए सेन्टर कायम होना चाहिए, गारन्टी होनी चाहिए उनके सामान की बिक्री की । ऐसा प्रावधान करने की बात कहीं दिखाई नहीं पड़ती । आपने बजट रखा है ट्रेनिंग देने के लिए, या उनको सूत वगैरह देने के लिए या दूसरी तरह के लोन वगैरह देने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए ।

इसी तरह से सरकारी कर्मचारियों का जहां तक प्रश्न है, भारत सरकार अपने केन्द्रीय कर्मचारियों को और भत्ता दे चुकी है । आपके सामने राजस्थान के कर्मचारी बार बार, बहुत बार, मांग रख चुके हैं, इस सदन के अन्दर भी यह मुद्दा बहुत बार उठाया जा चुका है, और आपने बार बार कहा है कि हम विचार कर रहे हैं । लेकिन अफसोस है, यह बजट आया है इस बजट में इस तरह का संकेत नहीं है कि राज्य सरकार उन कर्मचारियों के भत्ते के बारे में क्या कर रही है ।

इसी तरह से यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की सिफारिशें सब जगह लागू हो गई देश के अन्दर लेकिन हमारे राजस्थान के अन्दर लागू नहीं हुई । उनको क्या राहत इस बजट में दी है, मुझे उसका कहीं कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ता ।

अल्प वर्ग का जहां तक सवाल है, यह भी हमारा कर्त्तव्य है कि हम उस तरफ भी ध्यान देते । आपने केवल यह कहा है इसके अन्दर कि हमने उर्दू अकादमी स्थापित कर दी है । मानता हूं स्वागतयोग्य बात है, अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे सारी समस्या हल हो जायेगी, क्या जो अल्प वर्ग राजस्थान में है मुसलमानों का इससे उनकी दूसरी समस्यायें हल हो जायेंगी ? आपने कभी यह सोचा कि मुसलमानों के अन्दर भी ऐसे गरीब लोग हैं, अब बुनकरों की बात आप लें तो मुसलमानों में भी बुनकर हैं, पिछड़ी जातियां मुसलमानों के अन्दर हैं । क्या आपने कभी सोचा, उन जातियों को पिछड़ी जातियों की लिस्ट में ले लें ताकि बजट में कुछ प्रावधान उनके लिए भी हो जाता । कभी नहीं सोचा । इसी तरह से शिक्षा के मामले में अगर पिछड़ी जातियों के अन्दर आ जायं उनको दूसरी सहूलियत मिलने लगें । लेकिन आपने कभी नहीं सोचा । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए था । इस बजट के अन्दर इस तरह का प्रावधान होना चाहिए । अगर नहीं हुआ है इससे जाहिर होता है कि आपका दृष्टिकोण है वह इससे दूसरी तरफ है··

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये । You have to limit yourself within the time limit.

श्री रतीराम यादव : अभी मैं खत्म कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : It is more than 20 minutes.

श्री रतीराम यादव : मान्यवर, इसी तरह से सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण का जहां तक प्रश्न है, इसमें थोड़ी बहुत अपंग, विधवा महिला और छोटे बच्चों को सुरक्षा मिलती थी, वह भी समाप्त कर दी है। इसके आंकड़ों से मालूम होता है कि उस मद में आधा कम कर दिया है। तो हम कैसे मान लें कि बीस पाइन्ट प्रोग्राम पूरा करने की तरफ वित्त मंत्री की निष्ठा है।

इसी तरह से, ठीक है, आपने नशीली वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया है, स्वागतयोग्य बात है, लेकिन अच्छा यह होता जब आप हिम्मत करके यह कदम उठाते, जैसी कि राजस्थान की जनता की भावनायें हैं, जो यहां पर बड़ा भारी आन्दोलन भी इसके खिलाफ चल रहा है कि शराब बन्दी होनी चाहिए, तो शराब को बन्द कर देते और दूसरी चीजों पर टैक्स बढ़ाते तो ज्यादा अच्छा होता।

मान्यवर, अब मैं एक बात के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। शायद वित्त मंत्री यह महसूस करते होंगे कि यह कम्युनिस्ट पार्टी केवल आलोचना करती है और सारे मेरे इस बजट को बुरा बुरा कहा है। मैंने निवेदन किया....

श्री उपाध्यक्ष : समालोचना भी करते हैं, आलोचना ही नहीं।

श्री रतीराम यादव : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हम यह कहते हैं कि यह समाजवादी बजट नहीं है, समाजवाद लाने वाला बजट भी नहीं है और यह गरीबों के हित में बजट नहीं है, यह उच्च वर्ग के हित में बजट पेश किया है। आप यह कह सकते हैं, यह पूछ सकते हैं, तो फिर मुझे पैसा चाहिए, पैसा कहां से लाऊं। मान्यवर, वित्त मंत्री को मैं वह भी रास्ता बताना चाहता हूं, जहां मैं बजट को प्रतिक्रियावादी, गरीबों के खिलाफ बजट कहता हूं, वहां मेरे सामने यह भी दृष्टिकोण है कि हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ है, राजस्थान के पास रिसोर्सेज इन्कम के बहुत कम हैं और वह बढ़ने चाहिए। राजस्थान की जनता का विकास होना चाहिए, राजस्थान की तरक्की होनी चाहिए, तो आखिर हमको और रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। तो कहां से बढ़ायें, वह भी मैं आपको रास्ता बताना चाहता हूं, आपके बजट में जिसका कहीं प्रावधान नहीं किया है। अभी अर्बन लैंड सीलिंग कानून लागू हुआ है और हमारे राजस्थान में में मोटे तौर पर जहां पांच शहरों में आपने लागू किया है, अभी मैंने तीन चार शहरों के केवल आंकड़े मोटे तौर से इकट्ठे किये हैं, 21 लाख वर्ग मीटर जमीन वहां से निकलेगी अब इस जमीन का क्या करेंगे आप? आप इस प्रकार बांट देंगे, जिनके पास रहने को मकान नहीं है। ऐसा तो मैं मानता नहीं क्योंकि हमारे देखने में आ रहा है। आप इसको अगर इस प्रकार भी बांटेंगे तो कुछ पर्सेन्टेज तो ज्यादातर आप नीलाम करेंगे, फ्री बांटने का मतलब, जहां तक अलाट करेंगे तो कीमत लेंगे। तो उससे करोड़ों रुपये, आपके पास और आयेंगे। इस बजट में कहीं कोई आपने इसका दिग्दर्शन नहीं कराया है उसे छिपा बैठे हैं। आपको टैक्स से ही आमदनी बढ़ती दिखाई देती है।

(श्री रतीराम यादव)

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स और पैसेन्जर टैक्स यह तीनों इतनी वड़ी मद हैं कि करोड़ों रुपये अभी इसके बकाया है राजस्थान के अन्दर बड़े लोगों की तरफ। आपकी निगाह क्यों नहीं जाती उस तरफ? आप वसूल करिये सख्ती के साथ, जिस तरह गरीब लोगों से, किसानों से, मजदूरों से कोआपरेटिव सोसाइटी के कर्जे कुर्की करके वसूल कर रहे हैं, उनके मवेशी नीलाम करके, बर तन नीलाम करके वसूल कर रहे हैं, आपकी निगाह उधर क्यों नहीं जाती? आपकी हिम्मत क्यों नहीं होती है। यह आपकी कमी है, वह दूर करनी चाहिए।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

केवल एक मिनिट!

इसी तरह से शहरों के अन्दर बड़े बड़े सेठ, मिल ओनर, बड़े बड़े जागीरदार, राजा महाराजाओं ने आवासीय भूमि पर बहुत बड़ी संख्या में कब्जा करके उन पर मकान बनाये हैं, एग्रीकल्चर लैंड पर मकान बनाये हैं लेकिन कन्वर्शन चार्जेज उनकी तरफ ड्यू हैं। उनको वसूल करने की जरूरत है। अपने वहां का उदाहरण दूं, हमारे महाराजकुमार प्रताप सिंह है, जिन्होंने फूल बाग के एग्रीकल्चर लैंड पर अपना महल बनाया है, 47 लाख पिछले सालों से उनकी तरफ कन्वर्शन का बकाया है। लेकिन इस राज्य सरकार की हिम्मत नहीं है, अलवर में जहां किसानों से पुलिस के बलबूते पर इस साल में कर्ज वसूल किये हैं, रिकवरीज की है, उस महाराजकुमार से 47 लाख में से 1 लाख वसूल कर लेते तो मैं समझ सकता था, वित्त मंत्री जी, आपका बजट गरीबों के हित में है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। Please sum up now.

श्री रतीराम यादव : एक महत्वपूर्ण बात निवेदन करके मैं खत्म करना चाहता हूं आप टेम्प्रेरी तौर से टैक्स लगाकर जो गाड़ी चलाना चाहते हैं, यह खतरनाक है। आपको याद होगा जब चीन से हम युद्ध में पिट गए, विश्व में भारत का सर नीचा हुआ उस समय हमारे समाजवादी देश सोवियत रूस ने सलाह दी थी पंडित नेहरू उस समय प्रधान मंत्री थे, कि पंडित जी काम जब चलेगा चाहे मैं आपको मदद दे रहा हूं, दूसरे भी दे दें लेकिन उधार खाने से देश आगे नहीं बढ़ता, देश की रक्षा उस समय होगी जब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे। इसलिए मैं आपको हथियार बनाने का कारखाना देता हूं, आप हथियार बनायें, देश की रक्षा के लिए सामान तैयार करें। इसी तरीके से राजस्थान में आप टैक्स बढ़ाकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो गाड़ी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इसलिए आपको बुनियादी तौर से सोचना पड़ेगा, राजस्थान की प्राकृतिक संपदा है, उसका उपयोग किया जाए।

बीकानेर में लिग्नाइट बहुत संख्या में पाया जाता है। परसों हमारे यहां जी.डी. आर. के राजदूत आए थे और जी.डी. आर. में लिग्नाइट के बहुत बड़े कारखाने हैं, आप उनका सहयोग लें, राजकीय क्षेत्र में कारखाना लगायें, देखिए आपके

(श्री रतीराम यादव)

पास रिसोर्सेज मिलते हैं या नहीं। आपके राज्य की आमदनी बढ़ती है, स्थाई तौर से बढ़ती है। इसी तरह से जिप्सम यहां खूब मिलता है, आप उसका कारखाना राजकीय क्षेत्र में लगा सकते हैं, आपकी परमानेन्ट आमद उससे हो सकती है। जैसे आपने रोडवेज का राष्ट्रीयकरण किया है तो निश्चित तौर से उत्साहजनक बात हुई कि आपकी आमदनी बढ़ी है। तो उसी तरह से पब्लिक सेक्टर में आपको बुनियादी उद्योग धंधे लगाने की आवश्यकता है, आप ढूंढ़िए, आपकी जमीन में ही वह खजाना भरा पड़ा है कि आपको आवश्यकता ही नहीं इस बात की कि आम लोगों पर टैक्स बढ़ायें।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरा सुझाव है कि उस रूप में हम गरीबों का उत्थान कर सकते हैं, गरीबों पर से हम टैक्सों का बोझ कम कर सकते हैं और अपने राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान का विकास करने के लिए हमें अपने स्वयं के साधन स्थाई तौर से खोजने की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट भाषण को पढ़कर मन में कुछ पीड़ा हुई। इसमें प्रधान मंत्री की तारीफ की गई, मुख्य मंत्री की तारीफ की गई, वित्त मंत्री ने स्वयं ने अपनी तारीफ की, मंत्रियों की भी तारीफ की और अधिकारियों की भी तारीफ की, तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे याने माननीय सदस्यों के लिए क्यों, कुछ नहीं कहा गया। तो मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि कम से कम जब अपने भाषण की समाप्ति करें तब तो हमारी कहीं न कहीं वाहवाही करें, क्या हम बिल्कुल बेकार हैं? 184 सदस्य सदन में बैठने वाले हैं। बजट भाषण में मंत्रियों के लिए कह दिया, वित्त मंत्री ने स्वयं ने अपने लिए कह दिया...

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): मंत्रियों के लिए कहां तारीफ लिखी है?

श्री यशवन्त सिंह नाहर : बहुत साफ है, बड़ी तारीफ की है कि इनकी वजह से ही सब कुछ हुआ और हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ...

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीगण को तारीफ कम लग रही है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : अध्यक्ष बिराजे हुए थे, उपाध्यक्ष के लिए कुछ कहते पर वह भी नहीं है। अब हम कहां जायं? जब हमारा बजट पेश हुआ तो दूसरे दिवस टाइम्स आफ इंडिया ने फ्रंट पेज पर एक हैडलाइन लिखी "टैक्स आन लक्जरी गुड्स कट इन राजस्थान।" इंडियन एक्सप्रेस में भी था। इसका मतलब राजस्थान में इन चीजों पर बिक्री कर ज्यादा था। फैक्ट तो यह था कि राजस्थान में इन चीजों की बिक्री नहीं थी, आपका 15 प्रतिशत टैक्स था। यह राय आपको किसने दी और कब दी? वर्षों के बाद आपको याद आया कि राजस्थान का सेल्स टैक्स खत्म हो रहा है उस को अब 10 पर्सेन्ट करो। दूसरी बात, मोजों पर भी होजरी कर बढ़ा हुआ था। राजस्थान की होजरी कल्याणकारी

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

अवस्था में नहीं चल रही थी। इसमें आपने 3।। पर्सेंट रखा। हिंदुस्तान के दूसरे राज्य में एक पर्सेंट है। 3।। पर्सेंट करके आपने किसका कल्याण किया? मैं न तो मोजे न बनियान पहनना पसंद करता हूं। आपने बिजली ड्यूटी 5 से 6 पर्सेंट कर दी। सिंचाई चार्जेज भी बढ़ाये गये। कल मेरी कान्सटीट्यूएन्सी से तार आया उसमें लिखा था कि 80) रु. गेहूं का भाव है। आप समझते हैं राजस्थान का किसान संपन्न होता जा रहा है। मैंने देखा, राजस्थान के सारे नक्शे को देखा और मैं राजस्थान का दौरा करता हूं। दो तीन पर्सेन्ट जमीदार हैं जिनके पास 200 या 400 बीघा जमीन है, उनकी बात छोड़िए। ग्रामीणों में 66 प्रतिशत काश्तकार हैं, गरीब हैं। 93 प्रतिशत पापुलेशन कृषि पर आधारित है। 98 प्रतिशत के पास शाम को खाने को नहीं है। किसको रिचनेस दे रहे हैं? किस व्यक्ति ने आपको प्रेरित किया? राजस्थान में काश्तकार संपन्न हो, हम सदन में बैठने वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि राजस्थान का काश्तकार इतना संपन्न हो जाए कि 6 तो क्या 7 पर्सेन्ट ड्यूटी दे दे लेकिन आज वह 4 पैसा भी नहीं दे सकता। अगर गरीब काश्तकार को बिजली ड्यूटी से मुक्ति देनी है तो इस ड्यूटी को कम करिए। स्लेब बना दिया जाय कि 10 एकड़ से नीचे वाले पर नहीं लगेगा, उससे ऊपर वाले पर लगेगा। मेरे भीलवाड़ा जिले में 3 बीघा या 4 बीघा भी जिनके पास सिंचित जमीन नहीं है, उसका क्या होगा?

इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस ओर विशेष तौर से ध्यान दें। जहां तक वित्त मन्त्री जी, आपको वोट देने का प्रश्न है मैं आपको वोट तो दूंगा अगर हमारे क्षेत्र के अन्दर काम नहीं करेंगे तो भी दूंगा लेकिन वित्त मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी आप एक बात जरूर याद रख लीजिये राजस्थान की जनता गरीब है और राजस्थान की जनता आपको तब वोट देगी जब आप उन गरीब लोगों पर कम कर भार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं माननीय खनिज मन्त्री जी कि हमारी राज्य सरकार फर्स्ट फाईव ईयर प्लान से लेकर फिफ्थ फाईव *ईयर प्लान तक राजस्थान* में बेनीफिशियरी प्लान्ट लगाने की बात कर रही है लेकिन आज तक वह नहीं लगा पायी है। पता नहीं वह लगेगा या नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर खनिज मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां राजस्थान में खनिज सम्पदा बहुत अधिक मात्रा में पायी जाती है और उनमें से 40 खनिज पदार्थ तो ऐसे हैं जो कि हिन्दुस्तान भर के रेअर मिनरल्स में आते हैं लेकिन आप उसका पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाये हैं और जब तक आप रेअर मिनरल्स का पूरी तरह उपयोग नहीं करेंगे तब तक आम राजस्थान की गरीब जनता की गरीबी दूर करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय, काफी प्रतीक्षा करने के बाद आपने थोड़ा समय जो बोलने के लिए दिया है उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : इसमें प्रतीक्षा की क्या बात है? जब आपका नम्बर आया तब आपको बोलने के लिये कहा गया।

श्रीमती मदन कौर : फिर भी काफी प्रतीक्षा करनी पड़ी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पता नहीं यह खेतसिंह जी किस प्रकार से लिस्ट बनाते हैं।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से हमारे देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा हुई तब से हमारे देश के राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चेतना का संचार हुआ है ऐसा हमारे बजट में दिया है और यह बात सही है कि जब से हमारे देश के अन्दर आपात स्थिति लागू हुई उसके बाद से सारे देश के साथ साथ हमारे राज्य में भी जन चेतना, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में निश्चित रूप से आयी। हमारे यहां पर एक नयी जागरूकता की लहर पैदा हुई है। हमारे समाज में जो कर्जदारी, सूदखोरी, मृत्युभोज और गुलामी प्रथा जिसे आज कल सागड़ी प्रथा का नाम दिया गया है जो कि हमारे देश के लिये एक कलंक था और जिन कुप्रथाओं के रहते हमारे देश के लिये एक कलंक था और जिन कुप्रथाओं के रहते हुए हमारे यहां की गरीब जनता कभी भी उठ नहीं सकती थी उन कुप्रथाओं को रोकने के लिये हमारी राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार ने इससे पूर्व भी समय समय पर कुछ कानून और नियम भी बनाये थे लेकिन वह सभी, कानून प्रभावहीन रहे। यहां तक हमारा जो राजस्थान मनीलैण्डर्स एक्ट था वह बनने के बाद भी हमारे यहाँ की अलमारियों की शोभा को बढ़ाता था। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भारत सरकार इस देश में शांति से क्रान्ति लाना चाहती थी और उसके लिए हमारी केन्द्रीय सरकार ने उन असामाजिक तत्वों को जो, कि देश में प्रजातन्त्र को खतरा बना रही थी. अपने तौर तरीके बदलने के लिये काफी समय दिया और मैं समझती हूं कि उन्होंने यह ठीक ही किया कि जहां तक शांति से काम हो सके उतना ही अच्छा है। जहां तक शान्ति से क्रान्ति लायी जाये वह उचित है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि आपात कालीन स्थिति लागू होने के बाद स्थिति में काफी सुधार हुआ है लेकिन मुझे आशंका है कि जिस शक्ति से हमने काम किया है उसमें अगर हमने ढील कर दी तो जो उपलब्धियां हमने आपातकालीन स्थिति के दौरान प्राप्त की हैं वह सभी बेकार हो जायेंगी। यह आशंका मुझे इसलिये है कि उन ताकतों से बराबर अभी तक खतरा बना हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समाज में एक ऐसा सशक्त वर्ग है जो कि परिस्थितियों से खुश नहीं है और वह वर्ग इससे अभी तक रीकन्साईल नहीं कर पा रहा है और आज भी वह इसी प्रतीक्षा में हैं कि क्योंहि सरकार इसमें कुछ ढील करे तो वे लोग वही स्थिति देश की कर दें। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि राजस्थान सरकार और हमारे देश की जनता इस ओर पूरी तरह से सतर्कता से कार्यवाही करेगी। अधिक मजबूती से उन कानूनों को लागू करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय वित्त मन्त्री महोदय ने बजट भाषण में भावों में गिरावट आने का हवाला दिया है। यह बात सही है कि खाद्यान्नों के भावों में भारी गिरावट आयी

(श्रीमती मदन कौर)

है। और भावों में गिरावट आने का श्रेय हमारी राज्य सरकार ने लिया है। यह बात सही है कि खाद्यान्नों के भावों में गिरावट आयी है और उसका मुख्य कारण है आर्थिक अपराधों की रोकथाम, और जमाखोरी को रोकने की वजह से निश्चित रूप से भावों पर असर पड़ा है। लेकिन इसके साथ एक बात यह भी है कि इस बार हमारे यहां पर प्रकृति ने भी काफी साथ दिया। हमारे यहां वर्षा अच्छी हुई, मौसम अच्छा रहा और वर्षा भी समय पर हुई इससे प्रोडक्शन काफी हुआ। लेकिन यह तो प्रकृति ने हमारा साथ दिया इसलिये फसल बहुत अच्छी हुई लेकिन क्या हमेशा ही प्रकृति हमारा साथ देगी इसी प्रकार इसकी मुझे आशंका है। हमारे यहां पर कहीं बाढ़ आयी तो फसल नष्ट हो गयी। कई इलाके ऐसे हैं जहां वर्षा नहीं होने के कारण हर साल सूखा पड़ता है और भयंकर अकाल की स्थिति पैदा होती है। पिछले साल भी हमारे यहां पश्चिमी राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा था और हमें अकाल राहत कार्य खोलने पड़े थे। इसलिये अगर एक बार अच्छी फसल हो जावे तो हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिये कि अगर आज फसल अच्छी हुई है तो कल भी फसल अच्छी होगी। आज भी हमारे बाड़मेर के गांवों में यह स्थिति है कि बाजरा कोई भी व्यक्ति 40 रुपये क्विन्टल भी खरीदने को तैयार नहीं है। और न ही राज्य सरकार खरीद रही है। जिन काश्तकारों ने 250 रुपये क्विन्टल बाजरा बोया और खाया वह आज उसी बाजरे को 40 रुपये प्रति क्विन्टल बेचने को बाजार में घूम रहे हैं लेकिन उस बाजरे का कोई खरीददार नहीं मिल रहा है। वैसे तो कहने को सरकार यह घोषणायें करती रहती है कि किसान को खाद्यान्न का उचित मूल्य दिलाया जायेगा लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि काश्तकार को खाद्यान्न का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि राज्य सरकार को किसानों के हितों को नजरन्दाज नहीं करना चाहिये और उनकी ओर विशेष तौर से ध्यान दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि आज बाजरा पर्याप्त मात्रा में सस्ते भावों में मिल रहा है राज्य सरकार को चाहिये कि उसे खरीद ले और उनके भण्डार बनाये जाने चाहिये जिससे इस वर्ष नहीं तो आगे वर्षों में जब जरूरत पड़े तो उसको काम में लिया जा सके। इसके लिये आपको बड़े गोदाम बनाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि जो पोलीथान के बेग्ज होते हैं उनमें बाजरा भर कर रख दिया जाना चाहिये और उस पर त्रिपाल से ढक देना चाहिये। पोलीथान के बेग्ज में अनाज ज्यादा देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिये मैं राज्य सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि इस साल बाजरा और ग्वार की फसल जो अधिक हुई है उसे खरीद कर रख लेना चाहिये ताकि अकाल के समय हमें अनाज बाहर से विदेशों से महंगा नहीं मंगाना पड़े। और जरूरत पड़ने पर उसे काम में लिया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान का पश्चिमी इलाका हमेशा अकालग्रस्त रहता है वहां पर हर साल सूखा पड़ता है और हमें हमेशा हर साल वहां पर अकाल राहत कार्य खोल कर करोड़ों रुपये

(श्रीमती मदन कौर)

खर्च करने पड़ते हैं। यह बात सही है कि इस साल अच्छी फसल हुई है तो वहां पर अस्थायी रूप से खुशहाली आयी है। इसके लिये सरकार को निष्क्रिय होकर नहीं बैठ जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में बार बार कहा है कि हमारा प्रदेश खेती के लिये वर्षों से महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता रहा है और जब वर्षा नहीं होती है तो सूखा पड़ता है। पिछले साल 74–75 और 75–76 में राज्य सरकार को कुल मिलाकर 45.32 करोड़ रुपये अकाल राहत के लिये खर्च करने पड़े इसके पहले भी राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्यों पर करोड़ों रुपये 68–69 और 70 वगैरह में खर्च किये। कितना किया यह तो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

इसलिये मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि सूखा निवारण के लिये राज्य सरकार को कोई स्थायी हल निकालना चाहिये। वैसे तो डी.पी.ए.पी. के कार्यक्रम चल रहे हैं, कई जगह पर प्रोजेक्ट आफिसर्स की नियुक्तियां भी की गयी हैं और प्रदेश में दस जिलों में डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत योजनायें भी बनायी जा रही हैं। एक मरु विकास बोर्ड भी बनाया गया है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उस मरु विकास बोर्ड की हैसियत क्या है? वह सिर्फ रिपोर्ट पेश कर सकता है राज्य सरकार को। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यह बोर्ड बनाकर और डी. पी. ए.पी. के अन्तर्गत नियुक्तियां करके आपने प्रशासनिक खर्चा तो बढ़ा लिया लेकिन वास्तविक विकास की गति आप नहीं दे पा रहे हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया कि अभी हमारे यहां पर अस्थायी खुशहाली आयी है लेकिन जब तक सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में आप सूखा निवारण के लिये स्थायी कारगर ढंग से कदम नहीं उठायेंगे तो स्थिति नहीं सुधरेगी। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां पर 85 प्रतिशत लोग कृषि पर अपना रोजगार चलाते हैं। लोग खेती करते हैं और खेती के लिये सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वह है पानी।

गंगा और कावेरी के पानी की बात हम सुनते थे लेकिन शायद आज तो उसको एक स्वप्न मान लिया जाय। मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ जो पानी आसानी से राजस्थान में आ सकता है चाहे वह जमुना का हो, गंगा का हो, कावेरी का हो, घग्घर का हो–हमें उस पानी का सही उपयोग करना चाहिये और उसको राजस्थान में लाने का प्रभावशाली कदम उठाना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहती हूं घग्घर का पानी हमारे राज्य से बहुत बड़ी मात्रा में पाकिस्तान को पहुंच जाता है। हालांकि कुछ उपयोग हमने अवश्य अभी किया है लेकिन अभी भी बहुत पानी पाकिस्तान को जाता है और हमारी धरती सूखी रह जाती है।

इसी तरह पश्चिमी जिले की लूनी नदी हमारे लिये बहुत उपयोगी है। उसमें हर साल बाढ़ आती है और बहुत सारा इलाका उस बाढ़ से नष्ट हो जाता है और पश्चिमी जिले की बहुत सारी धरती सूखी ही रह जाती हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं इन दोनों साधनों से जो पानी हमें मिलता है उसको प्राप्त करने के लिये हमें किसी के सामने नहीं जाना पड़ता है, किसी के सामने हमारे पक्ष को

(श्रीमती मदन कौर)

प्रस्तुत नहीं करना पड़ता है। यह पानी हमारा है, इसका उपयोग करना चाहिये। हम इन दोनों के पानी का काफी उपयोग कर सकते हैं। मैं सुझाव देना चाहती हूं कि इन दोनों स्रोतों से हम काफी पानी ले सकते हैं। इसके आस पास के इलाके का सर्वे कराना चाहिये, कहां इसका डाइवर्शन कर सकते है, कहां इसको स्टोर कर सकते हैं। इसके पानी को नियंत्रण में करके जब भी बाढ़ आये हम उस पानी को ले सकें।

इसी के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं। राजस्थान नहर परियोजना हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। जिस समय यह परियोजना बनाई गई थी, श्री कंवर सेन और दूसरे लोगों के दिमाग में जो मुख्य सवाल था वह यह था कि इसका पानी पाकिस्तान को जाता था और वे चाहते थे कि इस पानी से हमारी सूखी धरती की सिंचाई हो सके। आज ज्ञान की वृद्धि हुई है, विज्ञान ने काफी तरक्की की है उसके आधार पर इस परियोजना का और अच्छे ढंग से उपयोग करना चाहिये। मैं सुझाव देना चाहती हूं कि राजस्थान नहर के द्वितीय चरण में कुछ संशोधन करके नाचना के पास से एक नहर तिलवाड़ा तक ले जाई जाय और दूसरी नहर नाचना से शिव– बाड़मेर तक और तीसरी नहर को कंवाल से दूर घाटासर तक ले जायं तो बाड़मेर व जैसलमेर जो घनी आबादी का क्षेत्र है, वहां तीन बैल्ट तैयार की जा सकती हैं और निश्चित रूप से उस क्षेत्र को हम हमेशा के लिये सूखे से बचा सकते है जहां पशु पालन का भी बहुतायत से धन्धा होता है। मैं निवेदन करना चाहती हूं बाड़मेर जिले में जो ट्यूब वैल्स चल रहे है, उनका रिचार्जेज का सिस्टम नहीं है–वहां काफी पानी भरा हुआ है और हम केवल पानी का खनन ही खनन करते रहे तो 10-5 सालों में वह पानी भी सूख जायेगा और जो पानी आज बाड़मेर में मिल रहा है वह भी नहीं मिलेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं इसी तरह की कठिनाई उस क्षेत्र में है जहां सीमान्त जिला है, मैं यह कहने की आवश्यकता नहीं समझती हूं कि अगर पानी नहीं है तो निश्चित रूप से वह क्षेत्र उजड़ेगा और निर्जन व उजड़ा हुआ क्षेत्र दुश्मन को निमंत्रण देता है। तो मैं आपको सुझाव देना चाहती हूं पानी के सम्बन्ध में कि वित्त मंत्री जी ने अपने इस बजट में सिंचाई की दरों में बढ़ोतरी की और इसके लिये मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं। उन्होंने साहस पूर्ण कार्य किया है, बधाई इसलिये नहीं देना चाहती हूं कि राजस्थान की जनता बहुत समृद्धशाली बन गई है और बहुत कुछ राज्य कोष में देने की हिम्मत रखती है। मैं वित्त मंत्री जी को इसलिये बधाई देना चाहती हूं कि राजस्थान जैसे राज्य में जहां एक तरफ मनुष्य पीने के पानी के लिये तरसे, पानी के अभाव में पशु तरसे वहां दूसरी तरफ इतना सस्ता और इफरात से पानी दे। दुनिया के किसी देश में इतनी इफरात से पानी नहीं दिया जाता है जितना अपने यहां दिया जाता है। हमारे पास जो पानी के साधन उपलब्ध हैं उनको बहुत समझदारी से, सोच समझकर और टेक्निक के आधार पर उपयोग करना चाहिये। हमारे यहां पर पानी का इतना अभाव है कि पानी के लिये हम

(श्रीमती मदन कौर)

लड़ते हैं, बड़े बड़े खर्चे करते हैं और उसके बावजूद पानी नहीं है वहां इतनी इफरात से पानी दिया जाता है।

श्री ओंकारलाल चौहान : क्या जो रेट्स वित्त मंत्री जी ने लगाई हैं वह वाजिब हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : गंगानगर में भी वाटर लोगिंग है....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य उस क्षेत्र से आ रहे हैं जहां वाटर लोगिंग की प्राबलम है।

श्रीमती मदन कौर : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी उनके रख रखाव के लिये जो खर्चा होता है उसके लिये किसान और वहां के लोग कुछ भी न देवें तो दूसरी जगह जहां पानी नहीं है वहां आयेगा कहां से। इसके लिये मेरा सुझाव है कि प्रशासन के खर्चे को कम करना चाहिये, हमारी अर्थ व्यवस्था को कम करना चाहिये और पानी की अच्छी व्यवस्था करके प्रशासन में खर्च करके कुछ कटौती की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी गांवों में जन साधारण के सुधारने की बात आती है तो लोगों को भू-आवंटन करने का कार्यक्रम सबसे पहले किया जाता है। मैं तो यह निवेदन करना चाहती थी कि जो जमीन खेती के लिये उपयोगी थी, जो जमीन खेती के लिए उपजाऊ थी वह सारी जमीन तो बहुत पहले ही खेती के नाम में आ चुकी है। अब तो जो मार्जिनल लेण्ड है जिसका हम भूमि हीन लोगों में और साधन हीन लोगों में आवंटित करके श्रेय लेना चाहते हैं। वह जमीन ऐसी है कि बिना परिश्रम के, बिना कड़ी मेहनत के, बिना उसके कोई साधन जुटाये उपयोगी नहीं हो सकती है। मेरा सुझाव है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये केवल खेती पर दबाव नहीं डाला जाय बल्कि दूसरे काम–काज लोगों के रोजगार सुधारने के लिए दिए जाने चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा सुझाव प्रधान मंत्री ने भी दिया था।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय, बेकारी की समस्या हमारे राज्य में भयंकर रूप से है। हमारे देश में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त लोग बेकार है, शिक्षित बेकार हैं, अर्द्ध शिक्षित बेकार हैं और अनपढ़ भी बेकार हैं तो बेकारी के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री जी का बिलकुल मौन रहना निश्चित रूप से निराशाजनक है।

मैं श्वेत क्रान्ति के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहती हूं क्या श्वेत क्रान्ति का हमारा स्वप्न साकार हो रहा है केवल मात्र डेयरी खोलने से और अगर इसी से श्वेत क्रान्ति आ जाती हो तब तो वह श्वेत क्रान्ति आ चुकी है लेकिन इसकी गति को तेज बनाये रखने के लिये, इसकी गति को और जीवन देने के लिये हमें कुछ अंकुर इसमें और डालने चाहिये। बाड़मेर में अच्छी कांकरेज नस्ल की गायें हैं। पड़ौसी राज्य बार बार कर और कांकरेज नस्ल को राजस्थान से ले जाना चाहते हैं और हमारे पशु पालन अधिकारी इस चिन्ता में बैठे रहते हैं कि हम किस तरह अपना लक्ष्य पूरा करें तो

(श्रीमती मदन कौर)

मेरा निवेदन है कि हम अच्छे पशुओं को हमारे जिले से बाहर नहीं जाने दें। चार पांच साल पहले शायद इस सदन में यह घोषणा की गई थी कि बाड़मेर जैसलमेर में कांकरेज नस्ल को सुधारने के लिये प्रयत्न किया जायगा लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जब हम आज श्वेत क्रान्ति की बात करते हैं तो कांकरेज, थारपारकर और राठी की जो नस्लें है, उनकी सुरक्षा करने का पूरी तरह प्रयत्न करना चाहिये और उनको हमारे जिले से बाहर नहीं जाने देना चाहिये। मैं यहां तक निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले साल अकाल में यदि किसी की सबसे ज्यादा हालत खराब हुई है तो वह पशु पालकों की हुई है। उनके पास बैठने के लिये जगह नही है। चरागाह की इतनी कमी है। जितने भी चरागाह थे उनको लोग दबा कर बैठ गये। पशुपालकों के पशुओं को चरने की जगह नहीं। जावें तो कहां जावें। इसलिये जो पशुपालन का धन्धा करते हैं उनके लिये भी आपको व्यवस्था करनी चाहिये। वरना जब कभी अकाल पड़ेगा तो वहां से पशु बाहर चले जावेंगे या पशु मर जावेंगे और पशुपालन का धन्धा ठप्प हो जावेगा।

अन्त में मैं पीने के पानी की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। आज भी पश्चिमी क्षेत्र के कई जिलों में और खासतौर से बाड़मेर क्षेत्र में तो कई जगह ऐसी हैं कि जहां पीने का पानी है ही नहीं आठ आठ मील तक पीने का पानी नहीं आपने ग्रामीण जल प्रदाय निगम बनाने की भी बात कही है। कहीं इसको भी एक बोर्ड की तरह ही नहीं बना दिया जाय। जो भी निगम बने, इन्सान को जल उपलब्ध कराने के साथ साथ पशुओं को भी जल उपलब्ध हो उसके लिये सोचें। जन संख्या के साथ साथ पशुओं की संख्या का भी ध्यान रख कर इस ओर व्यवस्था की जाय।

इस बजट का मैं समर्थन करती हूं लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने सुझाव रखे हैं उन पर माननीय वित्त मंत्रीजी विचार करेंगे और कार्यरूप में परिणत करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री हाजी जान मोहम्मद : मुझे समय दिया जाय। मैं थोड़ा बंगले पर गया था फिर भी नाम नहीं आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश किया गया है इससे एक साधारण व्यक्ति किस प्रकार ऊपर पहुंचेगा जब कि एक समृद्ध व्यक्ति द्वारा अपने वर्ग के लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए, गरीब किसान और मजदूर का शोषण करने के लिये एक बजट रख दिया हो। यह जरूर किया गया है कि करनी और कथनी को बचाने के लिये प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम को जोरदार समर्थन किया है। न तो वित्त मंत्रीजी 20 सूत्री कार्यक्रम में आस्था रखते हैं जो कि किसान और मजदूर की भलाई के लिये हैं यह बताया गया है, अपना एक मौका समझ कर सब लोग जय बोल कर ही जिन्दा रह सकते हैं इस दृष्टि से 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करना और किसान की बात करना यह अपने जिन्दा

(श्री मूलचन्द सामरिया)

रहने के लिये तरीका अपनाया है। वास्तव में देखा जाय तो किसान का, गरीब आदमी का, मजदूर का और पिछड़े हुए लोगों का किस प्रकार से भला होगा यह कहीं नहीं दृष्टि-गोचर होता है। इस बजट से किसान को लाभ होने वाली बात है बल्कि उसके विपरीत उसका उल्टा शोषण होगा जबकि किसान के पैर लड़खड़ा रहे हैं।

राजस्थान बनावट में और प्राकृतिक दृष्टि से बड़ा समृद्ध प्रदेश है। लेकिन इसका किस प्रकार से आज तक शोषण किया गया है।

(2.55 म.प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

इसका इतिहास समझें। किसान ने गेहूं पैदा किया। 200 रुपया क्विन्टल पर अनाज मिलता था पहले उसको 105 रुपये पर बेचने के लिये बाध्य किया लेवी में। किसान पर टैक्स अलग लगाये। आज किसान की हालत इतनी बिगड़ गयी है कि 150) रु. 200) क्विन्टल से खाने के लिये उसने अनाज लिया और आज किसान का गेहूं 80 रुपया क्विन्टल पर बिक रहा है और रुपये में छः आना आमदनी भी नहीं हो रही है। आज किसान महंगाई के कारण दब गया क्योंकि उसको दूसरी चीजों के पैसे अधिक देने पड़ते हैं तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज से दबा रहेगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने सिंचायी की दरों में वृद्धि की। क्या जो छोटे काश्तकार हैं, किसान हैं उनको एक्जम्पशन दिया जावेगा? नहीं होगा इसी प्रकार से बिजली दरों में भी वृद्धि की है यह भी किसान के लिये घातक होगी। मैं नहीं समझता कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के कौन से सूत्र में यह था कि रेफ्रीजरेटर और विलासपूर्ण वस्तुओं पर टैक्स कम किया जाय? यह कौनसा नारा था कि जिसमें विलासयुक्त चीजों पर टैक्स कम किया जाय और काश्तकारों को राहत पहुंचायी जाय? यह समझने में मैं असमर्थ हूं।

आज परिस्थितियां यह है। किसी को पुराने ऋण से मुक्ति दी। लेकिन आज रूरल बैंक से उनको ऋण नहीं मिलता है। यह भी निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि जब एक किसान को ऋणदाता ऋण नहीं दे सकता है तो उस किसान के लिये सरकार की ओर से कोई व्यवस्था होनी चाहिये ताकि उस किसान को छोटे 2 ऋण मिल सकें। सबसे बड़ी समस्या किसान के सामने उनको अपने को जिन्दा रखने की है। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की चीजों में कीमतें कम हुई हैं, खास तौर से किसान के जो चीजें काम आती हैं उनके भावों में, उनकी कीमतों के अन्दर कोई कमी नहीं हुई है बल्कि कुछ अंशों में बढ़ी ही हैं। वित्त मंत्रीजी ने किस प्रकार से उनको रिलीफ दिया है? फिर भी वित्त मंत्रीजी घोषणा करते चले जाते हैं कि सुधार हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहूं कि 15 पर्सेन्ट से कम कर दिया टैक्स, रेफ्रिजरेटर्स सेठिया लोग यूज करते हैं जब कि दूसरी ओर किसान पर टैक्स लगा दिया तो किस प्रकार से यह माना जा सकता है कि किसान की माली हालत ठीक हुई है। पर-केपिटा इनकम तब ही बढ़ सकती है जब कि आम आदमी की जिसमें किसान और मज

(श्री मूलचन्द सामरिया)

भी शामिल हैं उसकी हैसियत बढ़ती है। लेकिन किसान की आमदनी में कमी हुई है। किसान ने फसल पर कितना खर्चा किया, फिर भी उसकी उपज का उसको कम दाम मिल रहा है। वह नुकसान में जा रहा है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद 20 सूत्री कार्यक्रम और नारा एक मात्र नारा रह जाता है।

माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने बेरोजगारी की समस्या के लिए तो यह मान लिया है कि यह हल हो गयी है इसलिये इस ओर बजट भाषण में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इस ओर कारगर कदम उठाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। अर्द्ध शिक्षित, बेरोजगार और किसान के लिये टैक्सों में रिलीफ की कोई बात नहीं है। मजदूरों के लिये 3 पर्सेन्ट से 4 परसेन्ट कर दिया और उसको आमदनी के साथ जोड़ कर ऐसा व्यवहार किया है उससे साफ जाहिर होता है। आप क्या कहना चाहते हैं? किसानों के साथ क्या करना चाहते हैं। आप मजदूरों की दुहाई क्यों देते हैं और मजदूरों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं? आपकी कथनी और करनी में फर्क है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब सिंचाई के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज मुझे पता नहीं इन्दिरा गांधी जी जब भरतपुर पधारी थीं तो मुख्य मंत्री जी ने एक पुस्तिका उनको भेंट की थी जिसमें राजस्थान में खर्चा कहां कहां किया गया उसका पूरा विवरण दिया गया था।

There is no regional imbalance in Rajasthan.

लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि उसमें पता नहीं क्या लिखा है। अगर वह पुस्तिका सामने होती तो उसका अध्ययन करने के बाद ही कहा जा सकता है कि उसमें कहां तक सही लिखा है। राजस्थान में राजा महाराजाओं के समय सिंचाई के बांध थे उनको भी सिंचाई की तरफ से लेकर वित्त मंत्री जी ने अपने जन स्वास्थ्य विभाग में ले लिया। जमुवा रामगढ़ का बंधा जो कि जयपुर हिज हाईनेस के समय का है उससे पहले जमवा रामगढ़, बस्सी और दौसा इन तीन तहसीलों में सिंचाई होती थी लेकिन राजस्थान की सरकार बनने के बाद, और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उस बंधे को जयपुर के पेय जल के काम में लिया गया जबकि पीने के पानी के लिए बनास योजना की बात चल रही है और माननीय सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि उस योजना का भी सारा प्लानिंग तैयार है और उसके ऊपर लाखों रुपया गवर्नमेंट आफ राजस्थान ने खर्च कर दिया है। इसके साथ ही साथ एक ढूंढ नदी जयपुर से करीब 8 मील दूरी पर है उस पर भी एक बांध बनाया जा सकता है और उस बांध का पानी जयपुर के पेयजल के लिए काम में लाया जा सकता है। यही नहीं जमवा रामगढ़ का पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है लेकिन मैं यह समझता हूं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात हमारी सरकार चरितार्थ करती है। ऐसा लगता है कि पूर्वी राजस्थान में कोई राजनैतिक नेता नहीं है और इससे यह क्षेत्र शून्य है और जितने भी यहां के कांग्रेसी नेता हैं वह भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं और येन केन प्रकारेण पश्चिमी राजस्थान के पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। इसलिए हमारी

(श्री मूलचन्द सामरिया)

पूर्वी राजस्थान की मांग को कोई वजन नहीं दिया जाता। यही नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र में लाखों करोड़ों रुपया सिंचाई के साधनों पर खर्च किया गया है, जहां हमने लाखों करोड़ों रुपयों के टैक्स दिये हैं और सरकार की आमदनी में हमारा हिस्सा है वहां पर हमारी एग्जिस्टिंग इर्रिगेशन स्कीम को छीन कर जयपुर के पेयजल के लिए लेना यह सरकार की असफलता का कारण बनता है। मैं माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या पूर्वी राजस्थान जमवा रामगढ़, बस्सी और दौसा के किसानों के लिए और वहां जनता के लिए सरकार ने अलग से कोई व्यवस्था की है? फिर क्या जो जमुआ रामगढ के बंधे से सिंचाई होती थी उसको कम्पन्सेट किया है? यही नहीं जब जयपुर नगर के पीने के पानी आवश्यकता से अधिक उसमें पानी आता है तो उस समय मीटिंग होकर यह तय होता है कि कितना पानी दिया जाये और मीटिंग बुलाने में जन स्वास्थ्य विभाग और सिंचाई में कारस्पोन्डेन्स में इतना समय लग जाता है कि जब किसान को पानी की आवश्यकता होती है उस समय उस पानी को नहीं छोड़कर महीनों पीछे छोड़ा जाता है जब कि उसको आवश्यकता नहीं होती है। इस साल अतिवृष्टि की वजह से बंध में ज्यादा पानी आया और पानी छोड़ा भी गया लेकिन, सभापति महोदय, आज तक टेल तक सिंचाई नहीं हो सकी जब कि फसल करीब करीब पक कर तैयार हो चुकी है। मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में केबिनेट में सोच विचार कर सरकार निर्णय ले कि अमुक मात्रा से अधिक पानी होने पर मान लिया जायेगा कि बढ़ा हुआ पानी सिंचाई के काम में लिया जायेगा। अगर ऐसा किया गया तो मैं समझता हूं कि जो सरकार के निर्णय में अनावश्यक देरी से नुकसान होता है किसानों को उससे बचाया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, आज सिंचाई के मामले में न केवल हमसे बदला लिया बल्कि दूसरे साधन भी नहीं जुटाये गये जिससे वहां के प्रभावित क्षेत्र को कुछ रिलीफ दिया जा सके। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार कम से कम 10 पर्सेन्ट, 20 पर्सेन्ट पानी देते हुए दस साल के अन्दर यह एश्यो-रेन्स तो दें कि इस साल 10 पर्सेन्ट, अगली साल 20 पर्सेन्ट और उससे अगली साल 30 पर्सेन्ट और इस तरह से 10 साल के बाद यह बांध पूरा सिंचाई के लिए दे दिया जायेगा यदि यह निर्णय लिया जाता है तो मैं समझूंगा कि सरकार ने कुछ किया है।

माननीय सभापति जी, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि किसान की जो खेती है वह बिल्कुल अनिश्चितता की स्थिति में होती है। आज ज्योंही फसल पककर तैयार हुई तो जयपुर जिले में रोली जैसा रोग हो गया और फसल उससे प्रभावित हो गयी। मैं समझता हूं कि अगर सरकार किसी भी कीमत पर जिस तरह से कृषि की बीमा योजना शुरू की है तो उसका प्रीमियम देने से किसान को यह गारन्टी तो होगी कि उसकी फसल से इतनी तो आमदनी उसको होगी ही। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह फसली बीमा के लिए जरूर विचार करे और फसली बीमा होने पर किसान को किसी अंश में रिलिफ दी जा सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

सभापति महोदय, बहुत कम समय मिला।

श्री सभापति : जितना समय दिया जा सकता है दिया गया। अब आप जल्दी समाप्त करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं कम से कम समय लूंगा।

यही नहीं, सभापति महोदय, एक छोटा किसान है उसके पास दो चार बीघा जमीन है सरकार सारी वाहवाही लूटने के लिए और शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को जिनको सोचने का इतना मादा नहीं है वह एक बीघा जमीन का क्या करेंगे। चरागाह को अलाटमेन्ट करने की बात सरकार ने की है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस किसान के पास एक दो बीघा जमीन खेती की है और वह गाय या भैंस रखता है तो क्या वह एक बीघा के अन्दर चरायेगा या उसे चरागाह के अभाव में वह जमीन बेचनी पड़ेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा....

श्री परसराम मदेरणा : उसका समाज में स्टेटस बढ़ा है।

श्री मूलचन्द सामरिया : किस का ?

श्री परसराम मदेरणा : भूमिहीन का जिसको भूमि अलाट की गई है।

श्री मूलचन्द सामरिया : लेकिन सारे समाज का ढांचा चकनाचूर कर दिया है। अगर किसी को छोटा टुकड़ा दे देंगे तो क्या लाभ होगा। जिस धन्धे में वह लीन है उसको कर्जा देकर सुविधा दे दें तो वह उसको और आगे बढ़ा लेगा लेकिन जिसको खेती करने का ज्ञान नहीं है उसको बीघा दो बीघा जमीन देने से कुछ नहीं होगा और लोग जानते हैं कि वह दिल्ली जायेगा अपनी अपनी मजदूरी करने और वह पाती देकर हमसे ही करवायेगा। इससे वह पक्का काश्तकार नहीं हो सकता है। क्या दो तीन बीघा में कोई व्यक्ति की हैसियत बढ़ती है। इस तरह का नारा मात्र देने से उनकी हैसियत नहीं बढ़ेगी दो तीन बीघा में हैसियत बढ़ती हो तो वह साल भर काम कर सकता और अपना गुजारा कर सकता और फिर वह मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाता क्योंकि जमीन का एक लालच है कि मुफ्त में मिलती है इसलिए गले में डाल लेते हैं और फिर मुकदमेबाजी में फंसना पड़ता है और वह बरबाद हो जाता है। मैं यह मिसाल के तौर पर पूछना चाहूंगा आपने कितने लोगों को चरागाह अलाट किया जिनमें से कितने लोगों ने वास्तव में कब्जा दिलाया और कितने लोगों ने उस चरागाह पर मिली हुई जमीन पर खेती करके अपनी हैसियत बढ़ाई और आज बाजार में कितने लोग हैं जो अपनी हैसियत का दावा कर सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

यह बात यदि आप समझाने को तैयार हों तो मैं समझने के लिए तैयार हूं आप बता दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : इसका मूल्यांकन अभी हो रहा है। अभी मैं इस स्थिति में

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं हू कि आपको उत्तर दे सकूं लेकिन आपका नजरिया और आपका दृष्टिकोण चाहे बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम हो, चाहे सरकार का और कोई कार्यक्रम हो, सभी में आपको एक ही बात दिखाई देती है वाहवाही लूटने की। कुछ खतरा तो आपको लग रहा है लेकिन क्यों लग रहा है यह मुझे मालूम नहीं।

श्री मूलचंद सामरिया : मुझे कोई खतरा नहीं लग रहा है। मैं भी उसी क्लास का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं भी उसी क्लास से हूं जिसको आप दो बीघा जमीन दे रहे हैं....

(व्यवधान–शोरगुल–अश्रव्य)

श्री सभापति : आप और कुछ कहना चाहते हैं अपना पोइन्ट ? कोई आवश्यक पोइन्ट हो तो वह आप कहिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : जिनके लिए रोज नारे लगाओ और प्रक्टिकली कुछ नहीं हो, इस बात की मुझे चिन्ता है।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री गोकुलचन्द जाटव : सभापति महोदय...

श्री सभापति : आप बोलने दीजिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : अब मैं एक दो लाईन में अपनी बातें निवेदन कर देता हूं। दौसा वाटर स्कीम सेंक्शन तो हो गई लेकिन वहां जो टैंक बनना था वह आज दिन तक भी नहीं बना है, इसलिए टैंक जल्दी बनाया जाय।

दौसा में रेवेन्यू केसेज बहुत हैं उनकी सुनवाई के लिए उसको सब डिविजन हैड क्वार्टर करके मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वहां पर ए. डी. एम. की कोर्ट स्थापित की जावे जिससे कि गरीब किसानों का जयपुर आने जाने का खर्चा कम हो सके। इसी तरह से मैं यह निवेदन करूंगा कि सोसाईटीज की शाखायें इतनी अधिक तादाद में हैं कि उनको देखते हुए कि ए. आर. का आफिस भी वहां पर कायम हो। दौसा अस्पताल के आस पास में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है इसलिए वहां के होस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल में अपग्रेड किया जाय और इसके साथ ही साथ मेटरनिटि होस्पिटल और चाईल्ड वेलफेयर सेंटर भी कायम किया जाये।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि दौसा कालेज को वहां की छात्र संख्या की लाईब्रेरी और उसकी बिल्डिंग आदि सबको देखते हुए और यातायात के साधनों को देखते हुए उसको पोस्ट ग्रेज्यूएट कालेज में क्रमोन्नत किया जाय। यही नहीं, सभापति महोदय, जब आपने सभी सामन्ती परम्पराओं को तोड़ा है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जिले के गठन में जो सामन्ती परम्परा रही है जिससे जनता को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, जिससे जनता को प्रभावी प्रशासन नहीं मिल रहा है उसको आज तक क्यों पके से लगा रखा है इसके लिए मै निवेदन करूंगा कि जयपुर जिले के आकार को, जयपुर की शिक्षा संस्थाओं, जनसंख्या, सड़क और यातायात के साधनों, पशु धन, राजस्व और इसी तरह से खेतिहर जमीनों को देखते हुए इस प्रश्न पर आप शान्तिपूर्वक और निष्पक्षता से विचार करेंगे तो आप

(श्री मूलचन्द सामरिया)

निश्चित तौर से मानेंगे कि जयपुर जिले के दो जिले होकर एक जिले का डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर दौसा होना चाहिए। दौसा की स्थिति को देखते हुए वह डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर में क्रमोन्नत करने के लिए बाध्य होना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही रीजनेबल और वाजिब मांग है। न्यायिक तरीके से देखेंगे तो आप मानेंगे कि जयपुर जिला जितना भीमकाय जिला है कि एक कोने से दूसरे कोने तक आकर के अफसरों को दरख्वास्त देना, हैड आफिसर्स को अप्रोच करना और इफेक्टिव प्रशासन पाना बहुत मुश्किल है।

अन्त में मैं एक बात निवेदन और करना चाहूंगा। मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है लेकिन भय इस बात का है माननीय सभापतिजी, आज हमारी सरकार में ऐसे मंत्री भी बैठे हैं जो 420, 464, 486, 120–बी, आई. पी. सी. के मुजरिम हैं और बड़ी शान के साथ सरकार में बैठ कर शासन चलाते हैं अगर इन्हीं से बीस सूत्री कार्यक्रम को पूरा कराना है तो अवश्य कराया जावे।

श्री सभापति : श्रीमती मदनकौर।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मदनकौरजी तो बोल कर गईं, साहब।

श्री सभापति : श्री हाजीजान मोहम्मद।

श्री भगराज चौधरी : सर, मैं काफी समय से इन्तेजार कर रहा हूं।

श्री सभापति : बिराजिये, हाजी जान मोहम्मद।

श्री चिरदाराम : सभापति महोदय, हमारा भी नम्बर आएगा।

श्री सभापति : जरूर आएगा। जैसे 2 नम्बर आ रहा है, मौका दे रहा हूं। श्री हाजी जान मोहम्मद।

श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा) : सदरे मोहतरिम, आज मुझे एक शेर याद आता है :

"कहां से लायेगा कासिद, जबां मेरी
मजा जब है, जब सुनेंगे दास्तां मेरी"

सब की आवाज एक सी है। बजट जो पेश किया गया है मुझे उस पर भी एक शेर याद आता है :

"जबां ने खलक को
नक्कारे खुदा समझो"

जितने भी एम.एल.ए. साहबान बोले हैं सब की एक ही आवाज है कि यह बजट जो बनाया है किसानों को मारने के लिए और उसकी बरबादी के लिए है। सिंचाई की दरें जो बढ़ाई हैं वह किसानों को मारने के लिए हैं। मिर्ची पर, मूंगफली पर, गन्ने पर टैक्स बढ़ाये हैं। ये सब किसानों को मारने के लिए है। अगर कोई खुशहाल काश्तकार है तो बहुत से गिरे हुए लोग भी हैं। इसलिए सारे किसानों को परेशान करने के लिये यह बिल (बजट) है। इसको वापिस भी लिया जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। बजट को वापिस लिया जाय यह हाउस की एक ही आवाज है। काश्तकार परेशान हैं इससे उसकी परेशानी दूर हो। उसका गल्ले का उगाने में कितना पैसा लगता है, आगे

(श्री हाजी जान मोहम्मद

पीने के अन्दर कितना पैसा लगता है, मजदूरी का पैसा लगता है, चार पाँच रुपया किलो बीज है, इस हालत में वह कहां जाएगा। अगर आप इसको रीढ़ की हड्डी बतलाते हैं तो मेहरबानी करके अगर काश्तकारों को जिन्दा रखना है तो उनके लिए ऐसा इन्तेजाम कीजिए। हमारे माथुर साहब ने कहा था कि हम गल्ला खरीदेंगे, उन्होंने भीलवाडा में गल्ला खरीदा होगा लेकिन दूसरे जिलों के काश्तकार इतने परेशान हैं...

श्री परसराम मदेरणा : कोटा में परचेजेज हुई हैं। तीन हजार टन गेहूं की परचेजेज अभी जो है इस वक्त कोटा में हुई हैं। लेवी की बात नहीं कह रहा हूं, श्रोपन मार्केट से प्रक्योरमेंट प्राइज जो 105) रु. क्विन्टल है, वन ग्रेड और टू ग्रेड वीट की क्वालिटी की, उसमें तीन हजार टन की परचेज हुई है मुझे ऐसी जानकारी मिली थी। कोटा में कुछ हुई है। बूंदी और झालावाड़ की बात तो नहीं कह सकता।

श्री हाजी जान मोहम्मद : सारे कागजों में है अमल इसका कुछ नहीं है काश्तकार या तो परेशान है...

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हाजी जान मोहम्मद : रोज कानून बनाए जाते हैं और रोज तरमीम की जाती है। आखिर कब तक तरमीम करते रहेंगे। किसान आज भटकता रहता है। आखिर उसको अपने बच्चे पालना है, उनकी शादी विवाह भी करना है लेकिन आपने इतना बर्बाद कर दिया है लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। और भी बहुत सी बातें हैं। जैसे आप कहते हैं कि लाखों बीघा किसानों को दे दें। एक व्यक्ति को पांच बीघा जमीन दे दी, लेकिन वह उसको आबाद कैसे करेगा। चार हजार, तीन हजार रुपये में एक बैल की जोड़ी आती है वह पैसा काश्तकार कहां से लाएगा। सारे हिन्दुस्तान में तो आपने ढिंढोरा पीट दिया कि लाखों बीघा जमीन बांटी है लेकिन जमीन कभी आबाद नहीं हो सकती है ऐसी हालत में। यही हालत मकानों की है। मकानों के लिए जमीन तो दे दी लेकिन उस पर मकान कैसे बनायेंगे, बजट में इसके लिए कोई इन्तेजाम नहीं है। बजट में इसके लिए कोई पैसा नहीं रखा है तो यह ढिंढोरा पीटने से क्या फायदा। और चीजों पर टैक्स लगा सकते हैं। शराब पर लगा सकते हैं, सिनेमा पर लगा सकते हैं। इन पर लगाइये आप। आपको टैक्स लगाना है तो शराब पर लगायें, सिनेमा पर लगायें, बड़े काश्तकारों पर लगाइये...

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री चन्दनमल बैद : सिनेमा पर टैक्स बढ़ाइये यह कह रहे हैं।

श्री हाजी जान मोहम्मद : जिला झालावाड़ में जब से देश आजाद हुआ है उसके अन्दर कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक दो ही योजनाएं थीं भीमसागर बांध और हरिश्चन्द्र बांध की। लेकिन आजादी के 27 साल बाद भी इसका इन्तेजाम नहीं हुआ है.. वहां पर अच्छी अच्छी नदियां हैं। उन पर

(श्री हाजी जान मोहम्मद)

बांध बनाये जा सकते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं। सताईस साल की आजादी के बाद भी आज तक वहां पर कोई नया काम नहीं हुआ है। राजस्थान में लाखों, बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। हजारों स्कूलें बनी हैं। मन्दिर भी बने हैं। लेकिन आज तक इनकी रिपेयर का काम नहीं किया गया है। मेरी तहसील पिड़ावा में एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है परन्तु उसकी रिपेयर का कोई इन्तेजाम नहीं है। सरकार सुनती ही नहीं है। मेरा निवेदन है कि यह लाखों रुपयों की बिल्डिंग है। इसकी आधी दिवार गिर चुकी है। और बाकी की दिवार गिर जायेगी तो 12।13 आदमी और मर जायेंगे। इसकी मरम्मत आप कब करेंगे। अगर मरम्मत नहीं कर सकते हैं तो इन आदमियों के कफन का इन्तजाम तो आप कर दें। लाखों रुपयों की बिल्डिंग है। आधी गिर चुकी है। गवर्नमेंट की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो राज्य कर रहे हैं उनको यह देखना चाहिये। अच्छी बिल्डिंग है। इस बारिश के पहले मेहरबानी करके इस पर ध्यान दीजिये। दीवार गिर गयी और आदमी मर गये तो यह आपकी जिम्मेवारी होगी।

बिजली का मसला है। इसके लिए तो हमारे जोशी जी छाती पर हाथ रख कर कहते हैं मैं जिम्मेदार हूं। परन्तु कोई काम नहीं होता है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जैसे आदमी भी ऐसी बात कहें। इसलिए पुरजोर अल्फाज में कहना चाहता हूं कि इस ओर आप ध्यान दें। सत्तर हजार में से आपने दो हजार दिये हैं। सड़कों का क्या हाल है ? हमारी बद-किस्मती है। वैद जी वहां पर आये थे, उनको बताया था····

श्री चन्दनमल वैद : आपने मेरा जोर से स्वागत किया था····

श्री हाजी जान मोहम्मद : हां स्वागत किया था। परन्तु वह कहना भूल गया। आपको भी वहां पर एक काम बताया था आपने हां भी की थी किन्तु यहां आकर इन्कार कर गये। यह बड़े अफसोस की बात है। मिनिस्टर का करेक्टर अच्छा होना चाहिये। अगर मिनिस्टर झूठ बोलेंगे तो हम क्या करेंगे ? एक काम पड़ा था, उसको भी कैन्सिल कर दिया। मिनिस्टर को सच बोलने की कोशिश करना चाहिये।

काश्तकारों पर यह जो आपने टैक्स लगाया है उसको वे बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इससे वे बर्बाद हो गये हैं। यह बात जरूर है कि गल्ला सस्ता हो गया। परन्तु उनके लिए आप क्या इन्तजाम कर रहे हैं। ठीक है आवाज सब की एक है। काश्तकार के साथ ज्यादती हुई है। उन पर लगे टैक्स को आप वापिस लें। उनको राहत दें। आप कहते हैं काश्तकार हमारी रीढ़ की हड्डी है। लड़ाई में काश्तकार ही आगे जायेगा। झूंझनूं के रंगरूट ही जायेंगे। आप नहीं जाएंगे। इसलिए मेहरबानी करके काश्तकार को जिसे आप अपनी रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसको राहत दीजिये। आज तो आप काश्तकार की हड्डियों को चूर चूर कर रहे हैं····

श्री परसराम मदेरणा : रीढ़ की हड्डी तो बरकरार है।

श्री हाजी जान मोहम्मद : आपके यहां के लिए तो करोड़ों रुपया है। आपका एक गुट है इसलिए आप मजबूत हो। मैं तो जिला झालावाड़ की बात कह रहा हूं। वहां का कोई धणी धोरी नहीं है। चुनावों के दिनों में तो आप भेज देते हो परन्तु आपने कोई इन्तजाम नहीं किया है। यहां पर आपका पक्ष-पात है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मिनिस्टरों का स्वागत करो, काम हो जायेगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हाजी जान मोहम्मद : हम तो समर्थन ही करते आये हैं। शहर के एम. एल. ए. चालाक होते हैं। वे अपना काम करा ले जाते हैं। वे हम काश्तकारों के हित की बात नहीं कर सकते। वे होशियार होते हैं काश्तकार को जिसे आप अपने रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उनका क्या हाल है? ठीक है गल्ला सस्ता हो गया, सब को राहत मिली है लेकिन काश्तकार को क्यों मारना चाहते हो। इसलिए अर्ज करूंगा मेहरबानी कर के इस पर दुबारा गौर करें। इसमें तरमीम हो सकती है वरना राजस्थान का किसान, खास कर झालावाड़ जिले का किसान आइन्दा इलेक्शन में आपको वोट नहीं देगा। हम अपने स्वयं के राज्य में दुखी हैं, हमारा काश्तकार दुखी है। शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, प्लाट्स हैं इन पर क्यों नहीं आप हाउस टैक्स बढ़ाते? हमारे गरीब किसानों के रोजगार पर ही क्यों लगाना चाहते हैं। पुरजोर अल्फाज में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे काश्तकारों के हाल पर आप मेहरबानी कर के गौर करें। गौर किया जा सकता है। इनको नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। नजर अंदाज किया तो काश्तकार नाराज हो जायेगा। शहर के लोग चालाक हैं, यहां पर बड़े कारखाने हैं। उन पर टैक्स लगा सकते हैं परन्तु काश्तकार कहां जायेगा। वह तो हल चलाता है और चोटी से पैर तक उसके पसीना आता है। किस मुश्किल से वह गल्ला पैदा करते हैं। आज काश्तकार के लिए चीजें सस्ती होनी चाहिए, दवाओं के मूल्य में गिरावट आनी चाहिए, (समय–समाप्ति–सूचक घंटी) इसलिए मेरी पुरजोर अर्ज है, पूरे मंत्री-मण्डल और खास तौर से हमारे वित्तमंत्रीजी से, वह इस पर गौर करेंगे और काश्तकारों की तकलीफों को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापति जी, माननीय वित्त मंत्रीजी ने राज्य की वित्तीय स्थिति का चित्र हमारे सामने रखा। 72–73 में हमारी वित्तीय स्थिति बहुत संकटपूर्ण थी, और उसके बाद माननीय वित्त मंत्रीजी ने बताया कि पिछले चार सालों में मैंने कोशिश करके राज्य की वित्तीय स्थिति को सक्षम बना दी है। पिछले वर्षों में यहां पर जो हमेशा राजस्थान में अकाल की स्थिति को देखते हुए बहुत पैसा उनको खर्च करना पड़ा। केन्द्रीय सरकार से धनराशि की कुछ सहायता मिली और, जैसा कि उन्होंने बताया कि कुछ नहीं मिली तो भी अपने साधनों के जरिये अकाल राहत कार्य पर्याप्त मात्रा में खोले और लोगों को रिलीफ दिया। यह तथ्य हमारे सामने रखे। बहुत से तथ्य वास्तविक हैं उनको मन्जूर करते हैं, परन्तु जो राज्य की

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
वास्तविक वित्तीय स्थिति हमारे समक्ष रखी, वह रखना भी चाहिए और एक सफल वित्त मंत्रीजी के लिए यह जरूरी भी है कि और नये टैक्सों की खोज में उनकी हर जगह पर दृष्टि रहती है कि किस जगह से टैक्स लायें और अपने बजट के घाटे की पूर्ति करें। उस घाटे की पूर्ति करने के बावजूद उनका घाटा 18 करोड़ 40 लाख के आस पास बच जाता है। उसके बारे में उन्होंने बताया है कि टैक्स के एरियर्स की वसूली, रिकवरीज में और केन्द्रीय सरकार की सहायता को लेकर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।।

माननीय सभापतिजी, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो हमारे सामने पिक्चर रखी है और प्रधान मंत्रीजी के 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए विशेष बजट प्रावधान का भी जिक्र किया है, और उसके अलावा जिला वाइज एलोकेशन्स भी किये हैं, सभापतिजी, इन एलोकेशन्स के आधार को देखते हुए जो राजस्थान में समान रूप से जैसा विकास होना चाहिए और बजट का प्रावधान होना चाहिए, यह हमें देखकर बहुत असन्तोष होता है। जिस जगह से जो मंत्री आता है, जैसा कि माननीय वित्त मंत्रीजी चूरू जिले से आते हैं तो नापासर का नाम आगया है कि वहां पर क्रमोन्नत कर दिया गया है...

श्री चन्दनमल बैद : नापासर चूरू जिले में कहां है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : चूरू जिले में नहीं तो आपके डिवीजन में तो है।

श्री चन्दन मल बैद : वैसे तो सारी स्टेट मेरी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : छंगाणीजी फलौदी से आते हैं तो वहां पर अस्पताल क्रमोन्नत होगया अस्पताल 50 बेड्स का। पिछले कई वर्षों से वहां पर कुछ नहीं हुआ तो होना भी चाहिए यह मैं नहीं कहता। वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसके लिए हम इन्कार नहीं करते हैं। यह इम्बैलेन्स, यह हार्ट-बर्निंग मंत्री मण्डल क्यों करता है, वह सीधे एम. एल. एज. पर प्रहार करता है। एक ही बात को लेकर हमारे यहां के क्षेत्रों की उपेक्षा होती है। फाइनेन्स मिनिस्टर सबसे ज्यादा मंत्रियों की हैल्प करते हैं। माननीय देवपुराजी को ही ले लें। वह उदयपुर से आते हैं। दो मीडियम इर्रिगेशन की योजनाओं की माननीय वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की है वह कहां पर हैं? उदयपुर डिविजन में है...

श्री चन्दनमल बैद : उदयपुर डिवीजन में मन्जूर की हैं इसकी घोषणा नहीं की है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दो सिंचाई योजनाओं का बजट में प्रावधान रखा गया है। वह हमने देखा है। आज मंत्री जिस इलाके से आते हैं उन्हीं में काम होता है...

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य को कोई गलतफहमी है...

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई गलतफहमी नहीं है। उदयपुर में दो सिंचाई योजनाएं हैं उनको हमने पढ़ा है और बजट में उसका प्रावधान भी है...

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : अखबार में आया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अखबारों में नहीं पढ़ा है। बजट में आगया है तो पैसा देना

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
ही पड़ेगा मन्जूर की है योजना तो उसकी बात छोड़िये।

तो इस तरह से, सभापतिजी, राज्य सरकार की ओर से बजट के प्रावधान हैं। राजस्थान हमारा एक है, और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां रिसोर्सेज ज्यादा हैं जो विकास के अन्दर ज्यादा कन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसे इलाकों के लिए माननीय वित्त मंत्री जी आपका ध्यान जाना चाहिए।

एक तो मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि पिछले चार सालों से बराबर हमारे द्वारा प्रेस करने के बावजूद थोड़ी सी बिक्री कर की जो दर एल. डी. ओ. की 25 पर्सेन्ट से 15 पर्सेन्ट की रेट घटी है ·

एक माननीय सदस्य : 20 पर्सेन्ट है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 20 पर्सेन्ट इनका है और 5 पर्सेन्ट सैन्टर का है कुल मिलाकर 25 पर्सेन्ट है तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ दिया है, मगर माननीय वित्त मंत्रीजी गुजरात की सैल्स टैक्स की रेट को देखें···

श्री चन्दनमल बैद : आधा जो हुआ है उससे भी असन्तुष्ट हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : काश्तकार जो प्रोडक्शन में लगा हुआ है उसके प्रोडक्शन की रेट्स गिरती जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि प्राइस इन्डेक्स बराबर गिरती जा रही है तो प्राइस इन्डेक्स किस की गिरती जा रही है? सीरियल्स और तिलहन की प्राइसेज दनादन गिरती जा रही है। इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका एकमात्र कारण, सभापतिजी, यह है कि बैंकों ने जो है बिजीनेस मैन को पैसा देना बन्द कर दिया नाज खरीदने के लिए, बाकी ब्लेक मनी के सोर्सेज बन्द हो गये इसलिए वह खरीदकर अनाज कैसे रखे। दूसरी तरफ प्रान्तों में नाके बन्दी कठोर हो गई इसको देखकर बिजीनेसमेन ठिठक गया। दूसरी जगहों के बारे में तो मैं क्या कहूं कहने में असमर्थ हूं लेकिन, सभापति जी, हमारे सांचोर में और जालोर जिले में नाज की सबसे नीची दरें हैं और सपोर्ट प्राइस से भी नीची हैं। मैं खाद्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो यह ट्रेन्ड आ रहा है तो आप एफ. सी. आई. की मशीनरी को प्रिपेयर करके जगह जगह पर इन्तजाम नाज खरीदने का क्यों नहीं कर रहे हैं? उनसे कहते हैं तो खाद्य मंत्रीजी कह देते हैं कि तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली जाकर बात की है। बात क्या करते हैं स्वयं जगजीवनरामजी का स्टेटमेंट आ गया है कि हम प्राइसेज को नहीं गिरने देंगे···

श्री परसराम मदेरणा : सपोर्ट प्राइस और फ्लोर प्राइस क्या हैं इसका मुझे ध्यान नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपका ध्यान नहीं है 105/- रुपये प्राइस गेहूं की है।

श्री परसराम मदेरणा : वह प्रोक्योरमेंट प्राइस है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मिनिमम सपोर्ट और फ्लोर प्राइस से कम हैं। 80 रुपया क्विन्टल है। इससे नीचे भाव जाता है तो हर जगह पर दुकानदारी की व्यवस्था तो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

आपको करना पड़ेगी। तो, माननीय सभापतिजी, इस बारे में माननीय वित्त मंत्रीजी का कोई ध्यान नहीं गया इसलिए इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। आपको याद होगा कि पहले सांचौर के अन्दर चार माना किलो बाजरे का भाव गया था। 25 रुपये क्विन्टल बाजरे का भाव 3 साल के अकाल के बाद गया है और एफ सी.आई. ने अनाज खरीदने से इन्कार कर दिया था तो फिर स्टेट एकाउन्ट पर 48 रुपये क्विन्टल वह बाजरा खरीदा गया था। उसमें सरकार को 15 लाख का घाटा हुआ था, क्योंकि एफ.सी. आई. ने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा कि नाज खराब हो जायगा इसको फौरन बेच दो, और उनके बेचने के बाद नाज का भाव 150 रुपये क्विन्टल चला गया। वास्तविक स्थिति तो यह है कि हमारी एफ.सी.आई.सबसे ज्यादा रिएक्शनरी है। काश्तकारों का माल वह किसी तरह भी 105 के भाव से नहीं लेगा वह उनको 100 रुपया ही देगा और कहेगा कि आधार में नहीं आता है। तो इतने बड़े आर्गेनाइजेशन की जो कि मुल्क में कम्पीट कर सकता है, सभापतिजी, आज तक उनकी कोई खरीदने की तैयारी नहीं है। इस तरह से काश्तकारों की चीजों के भाव अभी तो वह बाजार में नाज आने ही नहीं लगा उससे पहले ही कीमत डाउन हो गयी। तो, सभापतिजी, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से कहना चाहता हूँ कि प्राइस इन्डेक्स की पर्सेन्टेज जो हमारे सामने उन्होंने दी है वह नाज की और काश्तकारों से सम्बन्धित उत्पादन की चीजों की है जिनकी कि प्राइसेज गिर रही हैं। उसके प्रोपोर्शन में बाजार में जाकर माननीय वित्त मंत्रीजी ने कभी नहीं देखा है कि दूसरी चीजें हैं उनमें कितना पर्सेन्टेजघटा है? वो का वो ही प्राइस लेबल मौजूद है। होटल ले लीजिये, खाने का रेट ले लीजिए। एल.एम.वी. के रेट लीजिए। वही रेट हैं। वह क्यों घटएंगे? उनको पैसे दिये जायेंगे। तो माननीय मंत्री महोदय, वो इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि किसान तो खून पसीना बहाकर चीज पैदा करता है। किसान का गेहूं सस्ते भाव में बिके और होटल वाले इस भाव में देखें। पिछले दिनों किसानों से बैंक की रिकवरी कोड़े मार मार कर की गई है। आप को अकाल की स्थिति का पता होगा। जब यह होता है तो आपको रिलीफ का भी खयाल रखना चाहिए। किसान दुगने और तिगुने भाव बीज प्राप्त करके फसल करता है। फायदा कोई उठाता है। कृषि मंत्रीजी बता रहे हैं कि उन्होंने इन्स्ट्रक्शन्स दिये हैं। परगट रोग से आधी बाजरी की फसल खत्म हो गई है। गिरदावरी हो रही थी तो एफ.सी. आई. के पास नमूने भेजे उस बाजरी के उसने कहा कि हम एक पैसे का भी नहीं लेंगे। वह उसको क्या कूड़ा करकट समझते हैं। अब वह कहते हैं कि हम नहीं खरीदेंगे। बाजार में 76 रु. क्विन्टल का भाव चल रहा है। आपने उसके लिए क्या व्यवस्था की है। कुछ भी तो नहीं है। अभी रेट आपने अनाउन्स किए नहीं है। आवश्यकता ही नहीं है। गोदाम ही नहीं है। आपने कोई व्यवस्था ही नहीं की है। इसके बारे में फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने कुछ भी नहीं रखा है। माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह आशा रखता था कि माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर महो-

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

दय कोई नया अनाउन्समेंट करेंगे क्योंकि काश्तकार रीढ की हड्डी, है। आपको आवश्यक कदम लेने होंगे। आप कोआपरेटिव सेक्टर ले लीजिये, प्राइवेट सैक्टर ले लीजिए, इर्रीगेशन ले लीजिए आपने किसी को कहीं लाभ नहीं पहुंचाया है। लोन की व्यवस्था ले लीजिए। काश्तकार को कोई लाभ नहीं हुआ है। आप कोई भी रिलीफ पहुंचाने में असमर्थ हैं। मेरा यह आरोप आपको एडमिट करना चाहिए। इतना डिफरेन्स होने के बावजूद आपको काश्तकार की रिकवरीज के बारे में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। काश्तकार आपके सामने बीज प्रोड्यूस करके रखता है। वो आपको यह सेफ साइड है। यह तो आपका इनश्योर्ड है। दूसरे जो रेफ्रीजरेटर वगैरह के टैक्सेज हैं। आपने जो कुछ सोचा हो। मैं आपको बार बार कहता हूं, पड़ोसी स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे टैक्सेज लगायें जिससे कि स्टेट की रेवेन्यू भी बढ़े और लोगों पर बोझ भी कम पड़े।

(समय–समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो, सभापति महोदय, इसी प्रकार से शिक्षा की मद में, आयुर्वेद की मद में, ड्रिंकिग वाटर में पहले तो इन्होंने वाटर बोर्ड बनाने का आश्वासन दे दिया था। वाटर बोर्ड की घोषणा अब की है। परन्तु यह नहीं होना चाहिये कि चेयरमैन, गाड़ी, स्टाफ इसी में सब बजट समाप्त कर दें। क्योंकि आपने दो करोड़ ड्रिंकिग वाटर में रखा है। परन्तु यह बोर्ड और उसकी रूपरेखा क्या होगी। इस प्रकार का करके वास्तव में हमारा जो रिलीफ देने की मंशा थी, वही करके आप रिलीफ दे रहे हैं या नहीं। अन्यथा वास्तव में रिलीफ नहीं मिलेगी। इसका आप ध्यान रखेंगे। सभापति महोदय, एजूकेशन सैक्टर में आपने 200 मिडिल स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है। लेकिन प्राइमरी स्कूलों के लिए क्या होगा ?

एक माननीय सदस्य : और सैकेण्डरी स्कूलों के लिए क्या होगा ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मिडिल स्कूलों के साथ साथ प्राइमरी स्कूलों की भी हालत बिगड़ी हुई है। पिछले पांच सालों में पंचायत समितियों की क्या हालत है। कई स्कूलों में हाजरी लेने वाले टीचर भी नहीं हैं। एक तरफ आप प्राइमरी एजूकेशन को कम्पलसरी करने जा रहे हैं। तो आपकी ओर से प्राइमरी एजूकेशन के लिए घोषणा होनी चाहिये। वह नहीं हुई है। सभापति महोदय, आयुर्वेद हास्पीटल की घोषणा की है। दूसरे तो आप खोल नहीं सकते हैं इसलिए आपने आयुर्वेद को खोल कर अच्छा किया है। जहां अभी तक नहीं खुले हैं, वहां भी खोल दें। यही आशा करूंगा। तो, सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि जो आपने बजट में प्रावधान रखा है, 2 करोड़ दिया है, तो उसके बारे में पिछड़े जिलों का ध्यान रखें। बहुत सी ऐसी जगह है जिनका आप भ्रमण ही नहीं करते हैं। उन स्थानों के लिए भी आपको पैसा देना होगा। हमारे खेतों में जो लोग हैं, उन का ध्यान रखेंगे। प्राइवेट सैक्टर में आपने पैसा दिया है परन्तु हमारे जालोर जिले में बिजली की 11 के.वी. लाइन है, । 132 के. वी. लाइन है उसका खयाल रहेगा या नहीं। आपने आश्वासन तो दे दिया है परन्तु तैयारी कुछ नहीं है। इस बारे में मंत्री महो-

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
दय ध्यान रखेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मोटी मोटी मदें रखी हैं, उन पर यह कहना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय ने दिमाग तो पूरा लगाया है । आपकी दृष्टि इस चीज को लेकर चली है । जो प्रावधान आपने सोशल सर्विसेज के लिए रखा है, यह बहुत अच्छा है । तो मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जब फाइल सैंक्शन के लिए आये तो क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठ कर काम करेंगे, यही मैं आशा करूंगा ।

श्री सभापति : श्री लूणाराम ।

श्री लूणाराम : सभापति महोदय, आजका यह बजट 1976-77 का, जिस पर कि हम चर्चा कर रहे हैं, यह बजट एक ऐसा बजट है जो आज की लोकप्रिय सरकार का बजट और पहले राजा महाराजा उसके जमाने के बजट में लगने वाले करों के अन्दर कोई फर्क नहीं है। आज यही लोग गरीब लोगों पर टैक्स लगाते हैं पहिले गरीबों पर टैक्स बेगार लेकर राजा महाराजा सम्पन्न लोगों को और अधिक सम्पन्न बनाते थे । वही पोजीशन आज इस बजट में देखने को मिलती है । सभापति महोदय, कहने में तो आज हम तीन रोज से सभी सदस्यों के भाषण यही सुनते आ रहे हैं कि गरीबों पर टैक्स लग गया, मजदूरों पर टैक्स लग गया, किसानों पर टैक्स लग गया । अब जिन पर टैक्स लगाया गया है या और किसी पर हम इसकी भूल-भुलैया में हैं और जो वास्तविकता है, उस पर्दे को हम अलग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वह इसलिए कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने बहुत ही चतुराई के साथ इस बजट को पेश किया है । यह एक प्रकार से भूल भुलैया में डालकर ही इस वर्ग पर टैक्स लगाया गया है जिससे कि सम्पन्न लोगों के बारे में, जिन्हें बचाया जो है उनको सदस्य भूल जाय और चर्चा का विषय कुछ दूसरा ही हो और यह रोना-धोना शुरू कर दे कि गरीबों पर टैक्स लगा दिया, किसानों पर टैक्स लगा दिया और मजदूरों पर टैक्स लगा दिया, यह सारी भूल-भुलैया में पड़ जायं और चाहे बाद में उसको वापिस ले लें, या कुछ कम कर दें । आज प्रश्न यह है कि टैक्स किस पर लगाया जाना चाहिये, टैक्स किसी जाति विशेष पर नहीं लगाना चाहिए, जो लोग पेशे से सम्पन्न लोग हैं, जो टैक्स देने की क्षमता रखते हैं, जिनके पास तिजोरी में नोट भरे हुए हैं, जिनके आलीशान मकान हैं, जो अट्टालिकाओं में रहते हैं इतनी ऊंची जो आकाश को चूमती हैं, और भी अनेक लोग ऐसे हैं जिन पर हमको टैक्स लगाने की आवश्यकता है ताकि वह लोग भी जनता के अन्दर आकर कुछ दूरी कम कर दें एक स्तर बना सकें और उनके साथ झोंपड़ियों में रह रहे लोगों से घृणा न कर सकें । हमने आलीशान भवनों पर कर लगाये भी हैं, लेकिन आज हो क्या रहा है । हमारे वित्त मन्त्रीजी ने जो टैक्सेज लगाये हैं और जो रकम उनसे टैक्सों से वसूल हो रही है उससे कहीं अधिक प्रशासनिक खर्चे हो रहे हैं । यह परिपाटी है। और इसी प्रकार से और भी कई उदाहरण हैं जिनके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए । जिन पर टैक्स लगना चाहिए वहां तो नहीं लगाये जाते हैं । कहने को तो घरेलू बिजली पर टैक्स बढ़ाया है और साथ में कृषि का उल्लेख कर दिया कि इस पर नहीं बढ़ायेंगे । यह भी एक भूल-भुलैया है । कलकारखानों में और बड़े-बड़े उद्योगों में अनाप-शनाप बिजली रेट में छूट दी गई है, अगर उनको भी कृषि के साथ सामान्य स्तर पर लाया जाता तो इससे

(श्री लूणाराम)

आर्थिक समस्या का भी समाधान हो जाता और काफी धन भी प्राप्त होता और समानता आती। पर उनको भूल-भुलैया में रखने के लिए कृषि का नाम साथ में जोड़ दिया ताकि साथ में यह दिखाई देता रहे कि बढ़ोतरी कृषि के लिये नहीं हैं और बचाना था उद्योगपतियों को। यह मैं भी मानता हूं कि उद्योगों पर भी टैक्स कम हो, लेकिन उन उद्योगों पर कितनी रकम लगी है जिनको आप बिजली दे रहे हैं तो, सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है? कि जिन वास्तविक लोगों पर टैक्स लगाया जाना चाहिए उन पर तो टैक्स नहीं लगाया गया, इसलिए गरीबों पर इसका ज्यादा भार पड़ेगा यह हकीकत है। सभापति महोदय, आज किसानों पर और मजदूरों पर टैक्स लगाने की बात है पर अनाज के कीमत की उनकी कितनी सम्पन्नता है और टैक्स देने की कितनी क्षमता है जो हम आज देख ही रहे हैं। उनको हम दे क्या रहे हैं, टैक्स वसूल की बात तो करते हैं लेकिन उनको मिलता क्या है? उनको ट्रैक्टर कितनी बढ़ी हुई कीमत पर दे रहे हैं और दूसरी मशीनों पर कितनी कीमतें बढ़ गई हैं। अच्छे बीज और खाद कितने मंहगे हो गये हैं, इस बारे में कोई बात नहीं करता। इसी प्रकार से आज जो भी किसान के काम में खेती के औजार आते हैं वह सब उसको बढ़ी हुई कीमत पर मिलता है। दूसरी तरफ हम उनसे अधिक अन्न उपजाने की आशा करते हैं, वह अधिक अन्न पैदा करता है, वह सोचता है कि किसी पर अहसान नहीं करता, अधिक अन्न उपजाने में ही वह अपना स्वाभिमान समझता है। लेकिन यह गुंजाइश कहां है कि उनमें सम्पन्नता आती तो आज उनके घर और उनके मकान भी किसी राजा, महाराजा, व्यापारी या उद्योगपति से कम नहीं होते, वे भी झोंपड़ियों में नहीं रहते। आज उनके बच्चे दवा आदि के लिये तरसते नहीं, शिक्षा की दृष्टि से वे भी पिछड़े हुए नहीं होते, वे भी संपन्न होते, और अपने पेट को बांधकर राजस्थान को छोड़कर अकाल के समय दूसरी जगह नहीं भटकते। होता क्या है कि उन लोगों को अकाल के समय सरकार द्वारा उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाता है, और उन्हीं से हम अधिक अन्न उपजाने व टैक्स लेने की आशा करते हैं। सभापति महोदय, किसान जानता है कि पिछली खरीफ के समय जब उसने काश्त की थी उसको ढाई सौ रुपया क्विन्टल अनाज खाना पड़ा था, और आज जब फसल मार्केट में आ रही है, या बिकने को तैयार है तो पचास साठ रुपया क्विन्टल पर भी कोई लेने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई है और दूसरी तरफ हम उनसे टैक्स वसूल करने जाते हैं। उनसे हम ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाने की आशा करते हैं और दूसरी तरफ उनसे टैक्स वसूल करते हैं इसलिए कि वह बोलने वाला नहीं है, वह कर्तव्य परायण है और सरकार को अपनी सरकार ही समझता है चाहे उसको मारे या कुछ भी करे। आज किसान की वही स्थिति है जिस प्रकार से कि एक लड़का अपने पिता को पिता समझकर प्यार करता है इसी प्रकार से सरकार चाहे किसान पर टैक्स लगाये लेकिन वह सरकार को सरकार मानकर आदेश पालन करता है। आज जो भी कृषि कार्य के लिए चीजें कितनी मंहगी मिलती है, लेकिन फिर भी वह सरकार को सरकार समझता है। सभापति महोदय, आज वही स्थिति जब हम देखते हैं तो इस

(श्री लूणाराम)

बारे में किसान पर हमको तरस आता है इसलिए कि आज एक तरफ देश के अन्दर हम गरीबी मिटाने की बात करते हैं, बीस सूत्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की वात करते हैं और बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आज हम गरीबों को, मजदूरों को और पिछड़ी हुई जातियों के लोगों को और भूमिहीनों को ऊंचा उठाने की वात करते हैं। इस साल हमारी सरकार ने कृपा करके और राजस्थान नहर के पास भूमिहीनों को भूमि देने के लिए चूरू जिले में, नागौर जिले में और जोधपुर जिले में भूमियां देने की स्वीकृति प्रदान की जिसके लिए मैं मेरे निर्वाचन के क्षेत्र अधिकांश ग्रामों में एक एक गांव में इस काम के प्रचार के लिए घूमा हूं। मेरे क्षेत्र में मैंने प्रचार किया है। लोगों ने जिज्ञासा दिखायी, लोग उत्सुक थे लेकिन लोग दरख्वास्त नहीं दे सके। इसलिए नहीं दे सके क्योंकि दरख्वास्त देने के लिए उनके पास दस पन्द्रह रुपये नहीं थे। इसलिए इस काम के लिए दरख्वास्त देने से वंचित रह गये। इतने भूमिहीन होते हुए उनकी आर्थिक स्थिति की यह हालत है। उन लोगों को जमीन दे रहे हैं उस जमीन की कीमत दुगनी कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी को बीकानेर डिवीजन बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए सौंपा हुआ है। माननीय वित्त मंत्री समय समय पर वहां गंगानगर, मीटिंग में पधारे हैं। वित्त मंत्री जी ने लोगों से चर्चा की होगी, एक मुरब्बे की क्या कीमत है? हो सकता है, किसी ने बताया हो, दो लाख तीन लाख कीमत है और हमारे वित्त मंत्री ने 17 हजार से बढ़ा कर 36 हजार दुगुना कर दिया। वित्त मंत्री ने नहीं सोचा, दो लाख का मुरब्बा बना है, जिस मुरब्बे के अन्दर आज अच्छी तरह से फसल खड़ी है, जिसके अन्दर आम का बाग लगा है, उस किसान की कई पीढ़ियों ने बलिदान किया है, कुर्बान हुए हैं मेहनत करके तब जाकर मुरब्बा की यह पोजीशन हुई है। ऐसा नहीं है कि योंही उसकी कीमत बढ़ गई हो। लेकिन वित्त मंत्री जी को सीधे ही यह कीमत बढ़ाने की लगी और आ गयी बात समझ में उन्होंने उठाकर कीमत दुगुनी कर दी दूसरे, सरकार ने महरबानी करके पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों को जमीन दी है, लेकिन वह उस जमीन पर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। हिम्मत इसलिए नहीं करेंगे कि 36 हजार देने को उनके पास होंगे नहीं। नतीजा यह होगा कि सरकार तो वाहवाही लूटेगी कि हमने जमीन दी है लेकिन लोगों ने जाकर कब्जा नहीं लिया। कब्जा वह पहले विवश और मजबूर है इस कारण नहीं कर पाया।

इसी प्रकार दूसरी तरफ यह समस्या है कि इन जमीनों की छः महिनों के बाद किश्त देने की भी सरकारी नियमों में व्यवस्था है। सभापति महोदय, एक तरफ हम जब कोई कारखाना लगाते हैं और वह कारखाना जब पैदावार देना शुरू कर देता है, उसके एक साल दो साल बाद जाकर किश्त शुरू होती है। दूसरी तरफ जमीन दी नहीं, उसने जमीन सुधारी नहीं, उसमें काश्त हुई नहीं, काश्तकार तमाम तरह मजबूर है लेकिन सरकार छः महिने बाद किश्त लेना शुरू कर देती है। आज यह हालत है।

दूसरे क्षेत्र में, सिचाई मंत्री महोदय विराजमान हैं, सिचाई क्षेत्र की यह हालत है-

(श्री लूणाराम)

मेरे पड़ोसी तहसील लूणकरणसर के अन्दर किसी भी एक गांव की सौ पचास बीघा भूमि लिफ्ट सिचाई योजना के अन्तर्गत आ गई तो उठा कर लाखों एकड़ जमीन गांव की है, वह कमान्ड घोषित कर दी। सभापति महोदय, सौ वर्ष भी उन गांवों के अन्दर जमीन को पानी नहीं लग सकता इतने टीवे हैं और पांच सात बीघा में पानी लगने पर ही कमान्ड करने की नीति हो तो उन किसानों को सब सुविधाओं से वंचित कर दिया और सिचाई के सारे नियम लागू कर दिये। इसका नतीजा यह है आज वह किसान, जिसकी अपनी अनकमाण्ड भूमि है जो कभी सिंचित होने वाली नहीं है, तीन चार मुरब्बा जमीन थी, उसको काश्त करके कमाई कर रहा था, और फसल से पेट पाल रहा था, वह भूमि उसके पास न रहने देकर उससे हटा कर एक मुरब्बा ही उसे छोड़ दी गई, 25 बीघा छोड़ दी और बाकी की ले ली जब कि वहां पर पानी की कोई योजना नहीं है। किसी-किसी गांव में पांच सौ, हजार बीघा जमीन कमाण्ड हो गई तो सारे गांवों की जमीन कमाण्ड नहीं हो जायगी। सिचाई मंत्री जी यहां विराजमान हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ऐसे गांवों के रहने वाले लोगों पर रहम फर्मा कर इस योजना को वापिस करके, जहां कमाण्ड हो गई हो, जिस पर पानी लग गया हो, वहां यह बन्धन हो, लेकिन दूसरी योजना को बन्द कीजिये, बाकी जमीन को रिलीज कीजिये जिससे किसानों को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं निवेदन कर रहा था, वह इस रूप में है। हमारे सदन के बहुत से माननीय सदस्य चूरू जिले पर, जल-प्रदाय योजना को लेकर सीधा अटेक करते हैं। चूरू जिले के अन्दर इतनी योजनायें मंजूर हो गईं, इतनी योजनायें मंजूर हो गईं, यह हो गया, वह हो गया। कोई हर्ज की बात नहीं है, अगर योजनायें मंजूर होती हैं और काम होता है, तो वास्तविक जगह अगर पैसा लगता है तो लगना चाहिए। मेरी समझ में इसमें सदन के माननीय सदस्यों को ऐतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि एक तरफ पीने के पानी की समस्या है, उसका समाधान करने के लिए, हम जो सारी जगह से आये हैं, हमें राजस्थान की सारी समस्याओं को एक समान समझना चाहिए। पर आज हकीकत और है, चूरू जिला बदनाम है, इसलिए कि हमारे वित्त मंत्री, जो जन-स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इन दोनों का सम्बन्ध हमारे वित्त मंत्री महोदय से जुड़ा हुआ है। लेकिन चूरू जिले को अभावों के कारण आपके राजस्थान का काला पानी कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जहां गांवों के अन्दर पीने के पानी का सवाल ही नहीं है..

श्री रघुनाथ विश्नोई : जगह-जगह टंकियां खड़ी हुई हैं।

श्री लूणाराम : टंकी का मैं अर्ज कर दूंगा। थोड़ा सब्र रखो।

श्री चन्दनमल बैद : प्रशंसा करने वाले नहीं हैं।

श्री लूणाराम : दूसरी तरफ ऐसा पानी गांवों के अन्दर जिस पानी को पीने से आदमी मर तक जाय, दिया जाता है। गर्मी के मौसम के अन्दर समझदार औरतें सोचती हैं कि ऐसा नहीं हो

(श्री लूणाराम)

कि रात को उठ कर बच्चा पानी न पीले और जिससे वह मर न जाय, वह पूरी रात पहरा देती है। जागती रहती है ऐसी पीने के पानी की दिक्कत है। दूसरी तरफ यह कहें कि सारा का सारा पैसा चूरू जिले में लगा दिया तो पैसे को कहां लेकर डालना चाहते हैं? आप गंगा के पानी में डालना चाहते हैं तो डालो, हमें दिक्कत की बात नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण समस्या है, उस समस्या पर पैसा लगना चाहिए····

श्री रघुनाथ विश्नोई : मना कौन कर रहा है।

श्री लूणाराम : इस रूप में कह रहे हैं। इस पैसे के लगने की जितनी आपको पीड़ा है, उतनी पीड़ा हम उस जिले के रहने वाले लोगों को भी है। वह इस रूप में है कि वित्त मंत्रीजी हमारे जिले के होते हुए भी हमारे साथ न्याय नहीं करते हैं। मैं तो यह सोचता हूं कि इस प्रकार का बजट मेरे हाथ लग जाय तो चाहे आप आलोचना मेरी करें, तब भी सारा बजट ले जाकर चूरू जिले की इस जल समस्या का समाधान कर दूं। लेकिन हमारे वित्त मंत्री ने वास्तविक रूप से उपेक्षा बरती है, जो बजट ले जाते हैं तो अपने क्षेत्र के बहार सरदारशहर के बाहर पैसा नहीं ले जाना चाहते हैं, वह उस तक सीमित रखना चाहते हैं। सरदार शहर तहसील का अधिकतर देहाती क्षेत्र मेरा है, लेकिन वित्त मंत्रीजी का वह जन्म स्थान भी है। वह जल-संकट में भयानक तहसील है जिसमें पीने के पानी का नाम नहीं है। 110 गांव मेरे क्षेत्र में हैं और 50-60 वित मंत्रीजी के क्षेत्र में हैं। वहां योजनायें स्वीकार कराई हैं। मेरे क्षेत्र में सिर्फ दो गांवों में योजना स्वीकार हुई हैं। पूछिये वित्त मंत्रीजी से, अगर मेरे क्षेत्र के एक गांव में भी पीने का पानी हो तो। जिन गांवों का प्रतिनिधि मैं हूं, उनसे वित्त मंत्रीजी की नजर टेढ़ी रहती है····

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसे गांव राजस्थान में और भी हैं।

श्री लूणाराम : यहां तक स्थिति है कि मेरे क्षेत्र के मेरे खुद के गांव में जल-प्रदाय योजना दस साल से लागू है लेकिन पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी न होने से पानी की भयानक स्थिति आ जाती है। चार साल से मैंने पिटीशन कमेटी को पिटीशन दी हुई है। वित्त मंत्रीजी को न जाने कितने कागज दिये हुए हैं, लेकिन वित्त मंत्री के देखने की बात नहीं है। इतनी बात होने के बाद भी मेरे को सूचना दिये बिना कांग्रेस विरोधी लोगों को साथ लेकर मेरे गांव पधारते हैं। पिछले वर्ष वहां पधारे हैं और वहां जाकर कहते हैं कि समस्या पीने के पानी की तो है, लेकिन आज तक किसी ने मेरे को कहा नहीं कोई हर्ज की बात नहीं है यदि वित्त मंत्रीजी गांव में जाकर यह फर्माये कि मेरे को किसी ने कहा नहीं आज तक। अब हो सकता है गांव वालों ने झूठ कहा हो। वित्त मंत्री ने नहीं कहा होगा। क्योंकि वित्त मंत्री को इतनी एप्लीकेशन दी हैं और पिटीशन भी चल रही है। वित्त मंत्रीजी ने नहीं कहा होगा और गांव वालों ने झूठ कहा होगा मेरे को···.

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : डरो मत।

श्री लूणाराम : इस रूप में ये सारी बातें जब मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि जो वोटर्स हैं वे अपने

(श्री लूणाराम)

से ज्यादा सयाने हैं, ज्यादा ज्ञान रखते हैं। लूणाराम के खिलाफ चाहे लाख कोशिश करें लेकिन इस प्रकार की बातें। वे जानते हैं कि जो कुछ लूणाराम कहेंगे, पानी की बात को वह अवश्य कहेगा। क्योंकि गांव की समस्या है। इस प्रकार के भ्रम फैलाने से पानी नहीं मिलता है। काम तो काम करने से होगा। आज मेरे क्षेत्र में जो योजनायें चालु की गई हैं, 4–4, 5–5 वर्ष हो गए, फिर भी स्थिति यह है कि आज एक गांव के अंदर पानी दे दिया, दो दिन कुआं चला फिर निल। गांव के लोग रोते फिरते हैं। एक नहीं जितनी भी 3–4 योजनायें चालू की गई हैं, उन सब का हाल यही है। मेरे खुद के गांव में हुआ है, उसमें इसके विभाग के ठेकेदार मरम्मत कर रहे थे तो गांव के लोगों ने मुझसे कहा कि मिट्टी लगा रहे हैं, सरकार का पैसा जा रहा है, जो अच्छा कुआं बना हुआ है उसको नाश कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इस विभाग को नमस्कार करता हूं, मिट्टी लगे या न लगे, आने वाली पीढ़ियां देखेंगी यह पैसा तो यूं ही लगने वाला है। हर योजना का यही हाल है। यह हकीकत है। आप विभाग का कोई आदमी दे दीजिए, मेरे साथ एक-एक योजना का अवलोकन करने चले, तो उनको पता लगेगा कि पैसा कैसे बर्बाद होता है।

जिस तरह से वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की है बोर्ड बनाने की, आप बोर्ड बनायें या नहीं, कम से कम मानव जाति और पशुओं पर इतनी कृपा करें चाहे हमें बजट में अधिक पैसा रखना पड़े। एक समस्या उन जिलों की है आए साल हम उस समस्या से पीड़ित हैं। आज एक तरफ तो यह हो रहा है, कि हम मुफ्त में पानी दे रहे हैं···

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री लूणाराम : ····दूसरी तरफ हकीकत यह है कि मुफ्त में पानी शहरों और गांवों को दे रहे हैं वहां 5–5, 7–7 मील से पानी लाना पड़ता है। 100 रुपये खर्च होते हैं। कहीं दूर-दूर जाकर पानी पड़े। हम मुफ्त में पानी नहीं चाहते हैं। आप हमारे साथ न्याय नहीं करते हैं। बेशक पानी पर टैक्स लगायें कोई दिक्कत नहीं हमें मुफ्त में पानी नहीं चाहते लेकिन किसी कीमत पर पानी मिल तो जाना चाहिये दूसरी तरफ यह स्थिति है।

पश्चिमी राजस्थान की अनेक समस्याएं हैं विद्युत् विभाग के पास जाते हैं तो वह कहता है कि डेजर्ट एरिया है। सड़कों के विभाग में जाते हैं तो वे भी कहते हैं कि एरिया डेजर्ट है। कहीं भी योजना बनने वालों के पास जायं, जब भी हम जाते हैं तो यही जवाब मिलता है कि यह तो डेजर्ट एरिया है। मेहरबानी करके इस डेजर्ट एरिया को इस बजट से राजस्थान से निकाल दें जिससे हम किसी प्रकार की आस नहीं लगायें नहीं तो फिजूल ही डेजर्ट एरिया को बदनाम करते हैं सो है, उसे विकसित कीजिए।

अभी एक माननीय सदस्य पूर्वी राजस्थान की वकालत कर रहे थे, ठीक है, उन्हें अपने क्षेत्र के लिए करना भी चाहिए, लेकिन जो डेजर्ट एरिया के बारे में उन्हें दर्द हो रहा था इसलिए कि डेजर्ट एरिया के नाम से मरू बोर्ड बनाया। आज मरू बोर्ड बनाया किसलिए? नौकरों के लिए जो सरप्लस थे उनको वहां लगा दिया? कोई काम आपने

(श्री लूणाराम)

मुफ्त में नहीं किया है रेडियो पर रोज सुनते हैं कि राजस्थान के विद्युत् मंत्री ने इतने गांवों में विद्युत् का उद्घाटन किया, इतनी देहाती योजनायें मंजूर हुई। यह सुनकर एक तरफ तो खुशी होती है लेकिन ऐसा होता नहीं है। मंत्रीजी बतायें कि गत 4 वर्षों में एक भी गांव में हमारी तरफ चूरू जिले में बिजली दी है? जब तक ये विद्युत् मंत्री रहेंगे, आशा है देगें भी नहीं। दो साल पहले एक गांव में वे मेरे क्षेत्र में पधारे और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि मुझे भरोसा नहीं मंत्री पर कि वह हमें विद्युत् दे देंगे। इस प्रकार तीन बार घोषणा करवाई गई कि मैं इस गांव को विद्युत् दे दूंगा। आज उन बातों को तीन साल हो गये। मैं अगर झूठ कह रहा हूं तो विद्युत् मंत्री कह दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : संभव होगा तो दे देंगे, यह कहा होगा।

श्री लूणाराम : हम कैसे मानकर चलें कि हमारा भी ध्यान रखा जाता है। हम आशा करते हैं कि हम भी राजस्थान के उस हिस्से में रहते हैं जो पीड़ित है। थोड़ी बहुत प्रार्थना पर विद्युत् मंत्री कोशिश कर देंगे चाहे दिल से या नहीं। पर विद्युत् मण्डल में देहाती विद्युतीकरण के लिए पहले सेक्रेटरी थे, आजकल चीफ इन्जिनीयर हो गये श्री सक्सेना जी। मैंने देवपुरा जी से कहा कि वह होशियार हैं न तो अपनी कहें न दूसरे की सुनें। तो विद्युत् मण्डल का यह हाल हो रहा है।

इसी प्रकार डेजर्ट एरिया में जब डेयरी की बात करते हैं तो किसी न किसी रूप में नाम लिया जाए, अगर कोई योजना बना कर दे दें तो नहीं।

जन-स्वास्थ्य की वही बात आ जाती है, दिल में दुःख होता है। आज हकीकत यह है कि इस जन-स्वास्थ्य विभाग का हमारे जिले में काम हुआ, योजनायें बनीं। 7 तहसीलों में से 6 में ए.ई.एन. रखे। पर लूणाराम पर मेहरबानी नहीं है, इसलिए डूंगरगढ़ से A.E.N. को, इतनी पुरानी आफिस है, योजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं है, ए.ई.एन. आफिस तोड़कर डूंगरगढ़ से हटा कर रतनगढ़ कर दिया।

इसी प्रकार जुडीश्यरी का मामला है। सरदार शहर में नई जुडीश्यरी के लिए ठीक नहीं बैठता है इसलिए सब डिविजन डूंगरगढ़ कर दिया क्योंकि सरदार शहर चूरू जिले में है। यह तो अपने घर का लेखा-जोखा है। ये चीजें शोभा नहीं देतीं। वित्त मंत्रीजी चूरू जिले के हैं इसलिए इस रूप में आप भेद भाव न करें।

इसी प्रकार मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट ज्युडिशियल जो नया सरदार शहर में स्थापित किया है के साथ श्री डूंगरगढ़ तहसील को लगा दिया जब कि डूंगरगढ़ रतनगढ़ सब-डिविजन में है और सरदार शहर चूरू सब डिविजन में इसलिए डूंगरगढ़ की जनता अन्य कार्यों के लिए तो रतनगढ़ जाए और न्याय के लिए सरदार शहर यह भेद-भाव और ऐसी हरकतें वित्त मंत्री जी को शोभा नहीं देती कृपया दिल बड़ा रखकर काम करिए जिससे जनता का नुकसान न हो।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री लूणाराम)

यह बजट जो पेश किया गया है उसमें आपने टैक्सेज लगाये हैं वह आपने ऐसे लोगों पर लगाये हैं वह एक गरीब तबका है। जो गरीब लोग हैं वह तो वित्त मंत्रीजी से कुछ कहने वाले नहीं है, और न ही बोलने वाले हैं। न ही वित्त मंत्री जी को वह लोग आकर ओलंभा देने वाले हैं। लेकिन आपने तो यह सोच लिया कि यह काश्तकार वर्ग आपके इस टैक्स को बरदाश्त कर लेंगे। वित्त मंत्रीजी मैं आपसे स्पष्ट निवेदन कर देना चाहता हूं कि काश्तकार वर्ग गरीब है और उसमें क्षमता नहीं है कि आपके इन टैक्सेज के भार को सह सके। वह दब जायेगा, टूट जायेगा और बरबाद हो जायेगा। इसलिए आपको उनकी तरफ विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। मैं सदन में बार-बार यही कहता आया हूं कि काश्तकारों पर समय-समय पर इस प्रकार के टैक्स नहीं लगावें और उनको इन करों से मुक्ति दिलाने की व्यवस्था करें। बस यही मुझे निवेदन करना है। जय हिन्द!

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी देर के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दोयम मैं वित्त मंत्री को मुबारकबाद देना चाहता हूं ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका नाम तो याद आ गया आखिर यही बहुत है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद इस बात के लिए देना चाहता हूं, कि उन्होंने जो बजट पेश किया है वह कॉमनमैन के हितों से बहुत दूर है और जो हमारा 20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम है उससे परे जाकर बजट रखा है। सभापति महोदय, हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरागांधी तो यह चाहती हैं कि 20–सूत्री कार्यक्रम हमारी जनता तक पहुंचाया जावे और दूसरी तरफ आपने जो टैक्सेज बजट में रखें हैं वह कॉमनमैन पर, और हमारी क्लास पर, हमारी पीजेन्ट्री क्लास पर भारी कर भार डालते हैं। आपने जो टैक्सेज लगाये हैं वह उस गरीब तबके पर लगाया है जो किसान है, जो एक गरीब मजदूर है और वह क्लास है जो कि मेनली मिडिल क्लास है। सभापति महोदय, हमारे मिडिल क्लास में जो खासतौर से सर्विस क्लास लोग हैं उन पर इस बजट का विपरीत असर पड़ा है। काश्तकार पर विपरीत असर पड़ा। जबकि हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरागांधी यह चाहती हैं कि हमारा बजट ऐसा होना चाहिये कि जिससे मिडिल क्लास फेमिली पर किसी प्रकार का बर्डन नहीं पड़े। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कल ही अखबारों में आया है कि रेलवे मंत्री, श्री कमला पति त्रिपाठी ने जब रेल्वे बजट पेश किया था तब उन्होंने जो कहा वह मैं आपको यहां कोट कराना चाहता हूं

"Additions to the pressure on the family budget of the common man should be avoided."

जबकि आपने प्रयत्न यह किया है कि ज्यादा से ज्यादा बर्डन मिडिल क्लास पर आना चाहिये। मैं आपसे यह निवेदन करना

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

चाहता हूं कि आपने बिजली पर ड्यूटी बढ़ा दी है इससे आम जनता पर कितना भारी भार पड़ा है आखिर आप क्या चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आप समाज के उस वर्ग पर प्रेशर डाल रहे हैं जो कि गरीब हैं आपने 15 रुपये तक के कपड़े की कीमत पर जो टैक्स पहले नहीं था उस पर भी आपने टैक्स लगाया है। यह 15 रुपये तक के कीमत के कपड़े कौन पहनता है वह आपका गरीब काश्तकार, मजदूर और मिडिल क्लास के लोग पहनते हैं। लेकिन आपको वह भी नहीं भाया और वह टैक्स भी आपकी आंखों में अखरा तो आपने उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो वह फायदा आपने मालिकों को दिया। और आपने अपने फेस सेविंग डिवाईस के लिये यह कह दिया कि हमने दस परसेन्ट से टैक्स सात परसेन्ट कर दिया इसी प्रकार आपने जो स्टाम्प ड्यूटी थी एफीडेविट पर और दूसरी चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया जो कि कोमनमैन पर पड़ता है। आज लोग अदालतों में जाते कोर्ट फीस देते हैं, वह ज्यादातर कौन हैं या तो गरीब काश्तकार या लेबर क्लास हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें वहां जाकर टिकट लगाना पड़ता है तो यह आपने सारा का सारा बर्डन टैक्सेज का कोमनमैन पर डाल दिया है आपने उसकी इकोनोमी को डेस्ट्रोय करने की कोशिश की है। और सिर्फ अपना फेस सेविंग डिवाईस के लिये आपने बोन्ड्स और कम्पनीज पर भी टैक्स लगा दिया है। यह आपने बड़ी ही चतुराई से किया है। इस ढंग की प्रक्रिया से ऐसा मालूम होता है कि आप कोमनमैन को कभी भी फलता-फूलता नहीं देख सकते। आपको गवारा था कि कहीं आम गरीब आदमी सुखी न हो जाय। जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने इस सदन में कल कहा था कि आपने जो इन्टरटेनमेन्ट टैक्स लगाया है वह ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास पर भार डालेगा। आप उनके इकोनोमिक स्ट्रक्चर को डेस्ट्रोय करना चाहते हैं। आपको डर लगा बड़े-बड़े अमीर वर्ग पर आपने अंग्रेजी शराब पर पैसे जो बढ़ाये वह सिर्फ पांच प्रतिशत बढ़ाया आप उस अमीर वर्ग से डरते हैं आप उन ठेकेदारों से भी डरते हैं जिससे कि आपने कन्ट्री लीकर टैक्स नहीं बढ़ाया। उन पर टैक्स की आपकी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं जानता हूं आपमें इतनी क्षमता नहीं है कि आप उन पर टैक्स लगा सको। आप हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने जो 20–सूत्री कार्यक्रम चालू किया है उसमें भी जो 12–सूत्री कार्यक्रम हमारी प्रधान मन्त्री का है उससे आप बहुत दूर चले गये हैं आप भी मिडिल क्लास फेमिली के इकोनोमिक स्ट्रक्चर को डेस्ट्रोय करना चाहते हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर टैक्स बढ़ा कर उस क्लास पर जो लोग गरीब हैं जिनके बच्चे 50 वाट के लैम्प के नीचे बैठ कर विद्या पढ़ते हैं उनको आप बरदाश्त नहीं कर सकते। आपको मालूम होगा वित्त मन्त्रीजी कि बिजली की क्रांति होती है। जिससे लोगों के मन में, जिसमें गरीब तबके के लोगों को रोशनी मिलती है। लेकिन आपको वह सुहाया नहीं और आपने यह टैक्स बढ़ाकर कोमनमैन पर टैक्स का बर्डन डाल दिया।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो भंग और अफीम पर टैक्स बढ़ाया है उसको मैं ठीक मानता

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

हूं। आपने फेस सेविंग डिवाईस के लिये चार परसेन्ट की होजरी में कमी करदी। तो मैं वित्त मन्त्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि आपने यह फायदा किसको दिया है यह आपने फायदा दिया है मिल मालिकों को। क्या आपने मिल मालिकों से साठ-गांठ करके कोमनमैन को बरबाद करने की सोची। आपने लाईट पर डीजल पर, टैक्सेज बढ़ा दिये और आपने फेस सेविंग डिवाईस के लिये ऐसी रियायतें दी जिसका फायदा कोमनमैन को नहीं मिलता। आपको शर्म नहीं एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट्स पर और इर्रीगेशन पर टैक्स लगाते हुए। आप काश्तकार को बरबाद करना चाहते हैं। एक तरफ तो सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री मेरठ को ग्रेनरी बनाने की बात करते है यहां दूसरी तरफ हमारे राजस्थान की ग्रेनरी जो कोटा, बून्दी और गंगानगर है उसको आप किसी प्रकार की राहत देना नहीं चाहते। आप बोर्डर पर अनाज बाहर जाने के लिये रोक लगाते हैं आप उन लोगों को परेशान करना चाहते हैं। अभी आज ही कल सदन में माननीय सदस्यों ने यहां कहा कि गेहूं के भाव इतने गिर गये है कि 80 रुपये प्रति क्विंटल हो गये हैं आप उन गरीबों पर और टैक्स लगाकर उनके इकोनोमिक स्ट्रक्चर को डेस्ट्रोय कर रहे हैं। इससे मालूम होता है कि आपको उन गरीब लोगों से कोई सिम्पेथी नहीं है। सभापति महोदय, मैं वित्त मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो बजट में 8 करोड़ रुपये के प्रतिरिक्त कर लगाये हैं, जिन लोगों पर लगाये हैं वह हमारे देश की प्रधान मन्त्रीजो जो चाहती हैं उसके विपरीत नहीं है। लेकिन चूंकि आपको उनको खुशहाल रहना भाता नहीं है आपको उनकी खुशहाली फबती नहीं है आप चाहते हैं कि गरीब किसी तरह से बरबाद हो जावे यह आपने किया। आपने डीजल प्राईस बढ़ाई, मालखाने के प्राईस बढ़ाये आपकी निगाह उन लोगों पर पड़ी जो हमारे देश का उत्पादन बढ़ाते हैं आप उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहते। सभापति महोदय मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आपने बजट में जो टैक्सेज कम करने की बात की है वह 50 हजार से ज्यादा टैक्स देने वाले हलवाईयों को आपने छूट दी है तो क्या आप नटराज के मालिक से बात करके आये कि जिससे हलवाई वयं 50 हजार से ऊपर टैक्स देते हैं उन्हें राहत मिले। यह किन लोगों को आप बजट में फायदा देना चाहते हैं। इसी प्रकार से आपने नेशनलाइजेशन की बात कही, नेशनलाईजेशन करके बसों को रोड़वेज की मदद देने की आपने जो बजट में बात कही है, आप फाइनेन्स मिनिस्टर हैं इतने दिनों से आपने क्यों नहीं सोचा। आज एक तरफ यह चल रहा है कि लोगों से नेशनलाइज करने के नाम पर रूट्स लिये जा रहे हैं। मालिक मजदूर होता फिरता है और दूसरी तरफ आपने 400 बसेज का दिल्ली से इन्तजाम किया है। क्यों नेशनलाइज के नाम से आप छुरा भोंकना चाहते हैं। क्यों नहीं आपने बजट में इसको पहले रखा, क्या नेशनलाइज को खतम करने वाले, जिसका हमको विश्वास है, उसका मुंह काला करने की बात की। क्यों नहीं पहले इन्तजाम किया, आज प्राईवेट बसेज किस पर टिकी हुई है और हमको दिखाना चाहते हैं कि बसेज के लिए ऋण दिया जा

Page No 91

(91)

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

रहा है क्या यह बहुत बड़ा डिफाल्ट नहीं है ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं इसी प्रकार से आपने मिडिल स्कूल्ज के 200 झुनझुने, 200 सदस्यों को जो मेरी तरफ बैठे हुये हैं उनके हाथ में झुनझुने देकर खुश करने की बात की है लेकिन आप सोचते नहीं हैं कि राजस्थान एक प्रगतिशील प्रान्त है और हमारे नौजवान बी. ए. के बाद पोस्ट ग्रेजूएशन करना चाहते हैं और आप नौजवानों को प्राईमरी और मिडिल स्कूलों तक ही रखना चाहते हैं। आप उनके लिये किसी तरह का प्रोविजन नहीं रखना चाहते हैं लेकिन क्योंकि वह श्रीमती इन्दिरा गान्धी के कार्यक्रम में है इसलिये इसको बजट में रखना चाहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को बराये नाम रखा है क्योंकि इसके लिये भी इन्दिरा गान्धी का सूत्र कहता है वरना आप कभी नहीं सोचते। आपने इस बारे में कभी ध्यान नहीं दिया। क्या आप एक भी बात ऐसी कह सकते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कामन मेन को टच नहीं करती है और कामन मैन से कन्सर्न नहीं रखती हो। फेमिली प्लानिंग के ऊपर एक शब्द भी प्रेशर के रूप में नहीं है। आपने बड़े अच्छे आंकड़ों की जगलरी करके बजट को रखने की कोशिश की है, उसके लिये तो मैं आपको बधाई देता हूं, मैं आपको मुबारकबाद करना चाहता हूं कि आपने आयुर्वेद के लिये इसमें प्रोविजन रखा है और इलेक्ट्रिसिटी के लिये प्रोविजन रखा है किन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गान्धी जो गरीबी को हटाना चाहती हैं, जो कामन-मैन के लिये रोटी, कपड़ा और मकान की बात करती हैं मैंने निवेदन किया किस प्रकार कपड़े पर आपने टैक्स लगाया है। 15) रु. से ऊपर कपड़े वालों को डाइरेक्ट हिट किया है। मकान के अन्दर आपने रखा लेकिन जो हाऊसिंग बोर्ड की बात कही है उसमें रकम का उल्लेख नहीं किया है। हाऊसिंग सोसायटी की बात कही है वह किस प्रकार चल रही है और किस प्रकार से वह राजस्थान की सेवा कर पा रही है, यह भी नहीं बताया गया है क्योंकि वह कम्पलीटली डेड और डिफेक्ट हो चुकी है और उसको भी आपने किस तरह का नजारा रखकर दिखाया है कि हमने यह चीज रखी है।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सोर्सेज कहां से क्रियेट कर सकते हैं, मेरा यह एक आसपेक्ट है और अब मैं दूसरा आसपेक्ट अर्ज करना चाहता हूं क्या आप नेशनलाइजेशन आफ माइन्स नहीं कर सकते हैं ? खान के मंत्री महोदय इधर बैठे हुए है और मैं उनसे बार-बार निवेदन करता हूं एक ही मालिक को अधिकार देकर वही मोनोपोली करना चाहते हैं। उन्होंने मोनोपोली को आज भी कायम कर रखा है। आपसे हम बार-बार कहते हैं और इस तरह आप राष्ट्रीय प्रोडक्शन को डाइरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20-सूत्री कार्यक्रम के बाद भी आप नहीं चाहते हैं। जो मालिक जिन्दगी भर एक्स-केवेट नहीं कर सकें उन्हीं को दुबारा दे दिया। क्या आपने कोटा में हीरा लाल को दुबारा ठेका नहीं दिया और क्या इसी तरह कन्हैयालाल घाटी वाले को खनन का काम

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

दुबारा नहीं दिया गया। हमने बराबर रिप्रजेनटेशन दिये हैं और इस सम्बन्ध में हाथ से काम करने वाले मजदूर आये हैं उन्होंने कहा हमें टुकड़ा दीजिये, हम नेशनल प्रोडक्शन को बढ़ायेगें लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और बहाना करते हैं कि केबिनेट के सामने प्रपोजल रखेंगे लेकिन आज अपनी इमेज को खराब करना चाहते हैं। राजस्थान की आपको चिन्ता नहीं हैं, आपको तो दिल्ली में इमेज बनानी हैं।

झामरकोटड़ा वाली बात, राक फास्फेट की बात इस हाऊस में कितनी बार आई है, आप कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आता है what is your Programme। 20-सूत्री कार्यक्रम जिस पर हमारी प्रधान मंत्री रात-दिन लगा रही है लेकिन उस पर भी आपकी नहीं खुली है। आपने उनको इनकलकुट करने की कोशिश नहीं की है। आप तो जनता पर भार डालने की बात करते है। इसी प्रकार जो इलाके हैं, जिनको डेयरीज मिलनी चाहिए और जो इलाके डेयरी के आधार पर डवलप हो सकते हैं उनको भी दरगुजर कर रहे हैं। आज कोटा डिविजन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि आप नहरों का नाम लेकर उस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं। बहुत बड़ा धन्धा उस एरिया में जानवर पालने का धन्धा हो सकता है लेकिन उस क्षेत्र को आपने बिल्कुल छोड़ दिया दिया है।

आपने अपने बजट में शक्ल देखकर टैक्स बढ़ाये हैं। जितनी संख्या आपने बढ़ाई है मेरे ख्याल से वह शक्ल देखकर तिलक करने वाली बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इससे तो छोटी-छोटी डिस्पेन्सरीज चाहे वह फर्स्ट ग्रेड कम्पाऊन्डर की हो और चाहे डाक्टर की हो, आप गांवों में देने की कोशिश करते तो ज्यादा अच्छा होता। आप कम से कम इस बात को तो सोचते मोबाइल डिसपेन्सरी क्या परपज सर्व करेगी ? मैं नहीं कहता उनको मत खोलिये लेकिन गांवों में आज भी बहुत बड़ी जनता के लिये ऐसी जगह है जहां आज तक मेडिकल ऐड उपलब्ध नहीं है।

आज राजस्थान की बड़ी भारी जनता के लिये ड्रिन्किंग वाटर का कोई प्रबन्ध नहीं है। आप सारे रिसोंसेज को कट अप कर दीजिये लेकिन इस बात को मत कहिये कि अगले साल...

What have you done and what are your achievements ?

अब तक आपने क्या किया, इसको हम देखना चाहते है। अब तक आप क्या कर पाये हैं इसको देखने की जरूरत है। मैं इस बात से सहमत हूं कि ड्रिंकिंग वाटर की फेसिलिटी सारे राजस्थान में करना प्राईमरी कर्त्तव्य है। इसी प्रकार मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री महोदय को और सिर्फ एक बात ही निवेदन करना चाहता हूं और वह मिडिल क्लास की बात है (माननीय मंत्री महोदय का ध्यान नहीं होने से) माननीय वित्त मंत्री जी सुननेवाली बात है, जरा ध्यान दीजिये इसीलिये आपसे कह रहा हूं...

श्री चन्दनमल बेद : आपका ही पत्र पढ़ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान की इमेज प्रोजेक्ट करने की बात है जो आप दिल्ली में करते हैं, दिल्ली में करें लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप वहां कितनी ही इमेज को प्रोजेक्ट करें लेकिन दिल्ली में आपका फोर्स नहीं है। आप राजस्थान के लिये पैसा दिल्ली से नहीं ला सके इसलिये श्रोवर बर्डन की बात की है और यह कहा कि हमने बहां अच्छी तरक्की करली है और उन्होंने उसके जवाब में कहा कि ठीक है, अच्छी तरक्की करली है तो जावो अपना काम चलावो...

श्री चन्दनमल बेद : मुझे नहीं मालूम था कि आप बाथरूम में बैठे बातें सुन रहे हैं...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मिडिल क्लास, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स का इतना बड़ा आन्दोलन हुआ, मैं वकालत करना चाहता हूं उनके मंहगाई भत्ते की। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से छोटे प्रान्तों ने किश्तों का पेमेन्ट कर दिया। आप नहीं सोच रहे हैं इस ओर। आप देना चाहते थे, मुख्य मंत्रीजी देना चाहते थे लेकिन ब्यूरोक्रेसी नहीं देना चाहती है, क्योंकि 3।। हजार रुपया ब्यूरोक्रेसी को दिल्ली के पत्र पर आ जाते हैं लेकिन यू. डी. सी. और एल. डी. सी. को नहीं। उनकी वकालात नहीं करते। वहां से पत्र आ जाता है कमिश्नर को 3500 रुपये। आप समस्यायें तैयार कर रहे हैं क्योंकि मेन्शन नहीं किया है कि मंहगाई भत्ता दे रहे हैं। आपका प्रोमिस है ड्यू है, देना पड़ता है और छोट वेड्स तैयार करते हैं अगर नहीं देना चाहते हैं तो।

आखरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने किसी प्रकार के इन्सेंटिव्ज नहीं दिये हैं। जैसा युवा नेता संजय गांधी कह रहे हैं फेमिली प्लानिंग के लिये दो बच्चे वालों को इन्सेन्टिव देना चाहिये। यह सरकार क्या इन्सेन्टिव देना चाहती है ? दहेज प्रथा में भी क्या इन्सेन्टिव देने जा रहे हैं, आपको भी प्रोविजन करना चाहिये था प्रोग्रेसिव बजट की कोई झलक तो तैयार करते। इसके बाद वित्त मंत्री महोदय से कोई गलत शब्द कह दिया हो तो माफी चाहता हूं और बजट का स्वागत करता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वित्त मंत्रीजी की आंख से दब गया हमारा शेर।

श्री सभापति : श्री बिरदाराम।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंस नाले में पड़ गयी।

श्री सभापति : श्री बिरदाराम।

श्री बिरदाराम (जालौर) : बजट के ऊपर मैं भी दो शब्द कहूंगा आज किसान की हालत खराब हो रही है। एक रुपया में तीन किलो बाजरी अनाज मिल रह्यो है। यदि इतना सस्ता अनाज गरीब काश्तकार बेंचे और खाद डाले बहुत मंहगो तो कई स्थिति रहवा वाली है बाकी।

खाद का भाव गिरया नहीं। बाजरी और गेहूं में गिरावट आयी है काफी। ओला भी पड़ गया। भवानी इलाका में खूब गिरया। काफी नुकसान हुओ। इस बारिश में सबको नुकसान हुआ है। काश्तकारों से हजारों रुपयों को नुकसान हुओ है।

(श्री बिरदाराम)

बिजली का बारे में भी निवेदन करूं कि काश्तकारों को सस्ती बिजली नहीं मिलती। घरेलू बात हो गयी जैसे। काम करना और पैदा लेना। जहां जाओ वहां रिश्वत। कौन आदमी नहीं देता है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रिश्वत या नश्वत?

श्री बिरदाराम : मैं यह निवेदन करूं कि काश्तकार की कंडीशन खराब है। कोई एक दो बीघा जमीन दी। लेकिन उसके लिये गरीब को कोई सुविधा नहीं दी। उसके लिये साधन नहीं काश्त साधन बिना कैसे करे? जमीन जोतने के लिये बैल नहीं। बीज नहीं। खाने के लिये हो नहीं बीज कहां से आवे। मजदूरी मिलती नहीं सरकार के द्वारा ऐसे लोगों के लिये व्यवस्था करनी चाहिये। बीज के लिये सरकार व्यवस्था करे। जहां पानी है मौजूद, नदी है, बांध है तो उससे पानी दें तो सही जिससे काश्तकार सिंचाई करके अनाज पैदा करे। इससे उत्पादन भी ज्यादा हो सकता है और किसान को भी फायदा हो सकता है।

अनाज के भाव गिर गये हैं। काश्तकार की पैदावार की चीजें सस्ती मिल रही हैं लेकिन ट्रैक्टर, मशीन के भाव नहीं गिरे हैं। 875 रुपये का एक टन खाद। जब कि बाजरी 40) रु. क्विन्टल। कहां से लावेगा? मोबिल आइल 170 रु.। काश्तकार यह कह रहे हैं कि ऐसी खेती करके बरबाद नहीं होना है। जितना खाने को चाहिये उतना ही बोवेंगे। मजदूर को मजदूरी पांच रुपया दो। पड़ता नहीं खाता है। अनाज जितनी जरूरत है उतना पैदा करो। सरकार ने इस पर विचार नहीं किया, सरकार विचार करे। सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया कि सरकार खरीदेगी। काश्तकार मंडी में लाता है लेकिन खरीदती नहीं, हर दृष्टि से काश्तकार को फायदा पहुंचाना जरूरी है। काश्तकार के लिये ऐसी कोई जरूर व्यवस्था करें। अनाज जरूर पैदा करेगा।

जिला जालोर की बात करता हूं। पिछड़ा जिला है। दूसरे जिलों में आपने जैसी सहायता बढ़ायी वैसी यहां पर नहीं बढ़ायी। पाकिस्तान की सरहद माथे है। भरतपुर में बाढ़ आयी, जालोर में भी बाढ़ आयी थी। जैसा भरतपुर में इन्तजाम किया वैसा हमारे यहां नहीं किया। कितना नुक्सान हुआ है। सरकार को पैसा लगाना चाहिये।

श्री सभापति : (कुछ माननीय सदस्यों के आपस में बात करने पर) आर्डर प्लीज। कृपया आपस में बात न करें।

श्री बिरदाराम : गांव के गांव नष्ट हो गये। कुए नष्ट हो गये। लाख लाख रुपये की जमीनें बरबाद हो गयी। सरकार को सोचना चाहिये। हमारा जिला पिछड़ा हुआ जिला है।

जालोर जिले में पहाड़ी जमीन है। रेतीली भी है। सिंचाई की नहर भी है। मीठा पानी भी है, खारा पानी भी है। इस जमीन पर सरकार ध्यान देकर हमारी तरफ महरबानी कर दे तो जालोर जिला काफी तरक्की कर सकता है।

(श्री बिरदाराम)

अब सड़कों के बारे में कहूंगा। जालोर की जैसी टूटी फूटी सड़कें कहीं भी नहीं हैं राजस्थान भर में। हमारे यहां आकोट नदी है, हमारे यहां जवाई नदी है। आकोट नदी है इसके लिए हर साल कितना पैसा खर्च होता है फिर भी सड़क टूट जाती है। मैं मंत्री महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि आप कम से कम यह तो जांच करें कि जालोर में इस नदी के ऊपर कितना खर्चा किया और हर साल फिर भी सड़क टूट जाती है। आप इस नदी के ऊपर पुल बनवाओ और अगर पुल नहीं बनवा सकते तो कम से कम कच्चा रपट तो वहां बनवा दो। बारिश के दिनों में जालोर आने के लिए रेलगाड़ी के और दूसरा कोई साधन नहीं है। सरकार को भी अपने कामों से वहां आना जाना पड़ता है और जनता को भी। बारिश के दिनों में अगर इन नदियों के ऊपर पुल बन जाते हैं तो आने जाने की सुविधा हो जायेगी। इसी तरह से जवाई नदी के ऊपर भी रपट बनवा दो। हमारा जिला सभापति महोदय, सरहद पर पड़ता है तो वहां के आने जाने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए।

सरकार को मैं यह भी निवेदन करूंगा कि नर्मदा नदी के लिए सरकार ने सर्वे भी कराई है। बाकी नर्मदा का पानी कब आयेगा इसका पता नहीं। हमारी सरकार कोशिश करे और पैरवी करे तो यह काम जल्दी से हो सकता है। अभी इस नमदा का पानी सिरोही जिले में ही आयेगा और जालोर जिले में तो फिर भी नहीं आयेगा। लेकिन सिरोही से जालोर और आधी भीनमाल और सांचोर तहसील आयेगी और फिर यह पानी कच्छ की खाड़ी में आयेगा। इस लिए सरकार को जल्दी ही इसके लिए कोशिश करनी चाहिए।

हमारी सरकार इतनी मेहनत करती है तो सिंचाई के लिए वह कुछ तो काम करे। इतनी जमीन हमारी डूब में आयेगी और फायदा दूसरी स्टेट वाले उठाते हैं। तो नर्मदा का पानी आयेगा तो वह गुजरात से आयेगा और इससे उसी को फायदा पहुंचेगा! राजस्थान में तो सांचोर तहसील के अलावा किसी को फायदा नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए और राजस्थान में सर्वे करानी चाहिए और यहां के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। जहां खारा पानी है वहां मीठा पानी देना चाहिए। यह मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जालोर जिले में हमारे खारा पानी है और वहां एक गांव है उसका पानी पीने से आदमी कुबड़ा हो जाता है और रीढ़ की हड्डी बाहर निकल जाती है। तो इसके लिए मैंने पहले भी कहा था और अब भी निवेदन करता हूं कि इसके बारे में सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने इसके लिए क्या कार्यवाही की? जहां जहां खारा पानी है वहां मीठे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री भगराज चौधरी। सभापति महोदय, हमको भी तो टाइम मिलना चाहिए।

श्री बिरदाराम : सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 28 परसेन्ट का रिजर्वेशन है लेकिन यह कोटा पूरा नहीं किया जाता है। बिजली

(श्री बिरदाराम)
विभाग में अभी 109 लोगों को लिया है जिसमें से शिड्यूल्ड कास्ट का एक भी आदमी नहीं है। इसके बारे में सरकार को न्याय करना चाहिए। हमारी समाजवादी सरकार है और समाजवादी सरकार से हम न्याय चाहते हैं। न्याय होना चाहिए बाकी अन्याय नहीं होना चाहिए।

सरकार को हमारे जालोर और सांचौर जिले में ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए कि मवेशियों के लिए जरूर जमीन रहनी चाहिए। हमको दूध चाहिए, घी चाहिए, मवेशियों के लिए जमीन नहीं रहेगी तो हमको दूध, दही कहां से आयेगा ?

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मवेशियों के लिए जरूर जमीन मिलनी चाहिए। भेड़ बकरी वाले हर साल इधर उधर घूमते फिरते हैं इसलिए मवेशियों के लिए हमारे यहां जरूर जमीन दी जाये चाहे पहाड़ी में दी जाये या फिर बन्जर जमीन दी जाये। कहीं न कहीं तो जमीन दी जानी चाहिए। मवेशियों के लिए जमीन नहीं होगी तो कहां से दूध मिलेगा ? तो मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि हमारी समाजवादी सरकार है...

श्री सभापति : (घण्टी) एक मिनट आसन ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जावे।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ाया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समय तो बढ़ा दिया जाये लेकिन इस घड़ी के मुताबिक, उस घड़ी के मुताबिक नहीं।

श्री सभापति : सेक्रेटेरियट दोनों घड़ियों को ठीक कर ले।

श्री बिरदाराम : इसके अलावा सभापति महोदय, अपाहिजों को और अन्धों को भी पैसा मिलना चाहिए। आज गरीबों को कर्जा मिलता है वह चाहे कोआपरेटिव बैंक से मिले या किसी से भी मिले लेकिन बीच में दलाल नहीं आने चाहिए।

(3.58 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

दलालों के बीच में आने से गरीबों को कर्जा नहीं मिल सकता है। अगर दलाल होगा तो उसके पास गरीबों का पैसा रहेगा।

श्री रामसिंह कुडी : मंत्री महोदय, इनकी बातें तो सुनो। यह बातें आपको कह रहे हैं।

श्री बिरदाराम : मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि समाजवाद आये तो सही। हमारी नेता प्रधान मंत्री इन्दिराजी जरूर समाजवाद लायेंगी। मैं कहता हूं कि पुलिस भी हमारी थोड़ी सुधरे।

(श्री बिरदा राम)

शराब बन्दी के बारे में मैं कहता हूं जो हमारी रक्षा करने वाले हैं वही शराब पीते हैं तो फिर शराबबन्दी कैसे होगी? इसकी तरफ भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जब तक पुलिस की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तब तक कल्याण नहीं होगा पुलिस के सम्बन्ध में मैं पुलिस की तारीफ भी करता हूं और जो इमरजेंसी लगाई है इन्दरा गांधी हमारी नेता देश की ने, अगर यह इमरजेंसी आज लागू नहीं हुई होती तो यह देश में जितने भी अमीर लोग हैं, जितने अमीर आदमी हैं इनको लूट कर खा जाते और आज इतनी गड़बड़ फैलती और हजारों आदमी इसमें मर जाते। इमरजेंसी ऐन मौके पर लगाई हमारी नेता ने और हमारी मांग है कि यह इमरजेंसी लागू रहे लेकिन इस इमरजेंसी से जितने परिवर्तन होने चाहिए थे वह नहीं हुए। आज भी जब गावों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इमरजेंसी में क्या हुआ। वही अनाज के भाव हैं, जो गिर गए हैं, हमारी बिजली का यह हाल है। हमारी सिंचाई का यह हाल है और उसमें हम लोग क्या करें। हम लोगों को क्या जबाव देंगे। अब हम गांवों में जाते हैं और लोगों का कोई काम होता है तो जिलाधीश को कह देते हैं, यहां आकर मंत्री महोदय को कह देते हैं लेकिन कोई काम नहीं होता तो दुबारा जब गांव में जावेंगे तब क्या कहेंगे। तुम बेकार हो। अब मैं आखिर में यही निवेदन करूंगा कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। हम आपके पास आवें और हमारी बात कोई सुने नहीं तो कहां जावें। यह ठीक है कि हमारा विश्वास है; मंत्री महोदय में विश्वास है लेकिन जब हमारी बात को नहीं मानते हैं, जब रिश्वत खोरी हो, बेईमानी हो तो कैसे चलेगा। कुछ बात तो आपको माननी चाहिए। अगर पांच दस आदमियों को अन्दर दे दें तो दूसरों को भी समझ आएगी। जिले में भी आप ईमानदार आदमियों की कमेटी बनाओ। जिला कमेटी में हम भी दौड़ेंगे। एम एल एज की कमेटी बनाओ तो साधन बन जावेगा जिले में और लोगों की सुनवाई होगी। कुछ तो सुधार होना चाहिए। इसलिए मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि मैंने इस बजट के बारे में जो कुछ बोलना था वह तो बोल दिया, बजट है हमारी समाजवादी कांग्रेस का उसके लिए तो धन्यवाद देंगे ही लेकिन कुछ बातें हैं जिनको देखना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुरभुज चौधरी।

श्री चतुरभुज चौधरी (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है उसके बारे में मैं भी कुछ विचार रखूंगा। पहले तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त में और जहां कहीं देश में यह इमरजेंसी लगी है वह बहुत ही सुन्दर काम हुआ है और आम जनता चाहती है कि इमरजेंसी लागू रहनी चाहिए। क्योंकि इस क्षेत्र में तब्दीली आई है और गलत जो काम हर स्थान पर हो रहे थे वह रुक गये हैं। इससे काफी प्रभाव पड़ा है लेकिन इसके साथ साथ कोई नहीं नाजायज काम करें, दूसरे काम करें इसलिए सरकार को सतर्क रहना जरूरी है।

इसके बाद में मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि बजट जो बना है और बिना टैक्स के

(श्री चतुरभुज चौधरी)

सरकार कोई भी चल नहीं सकती है, यह बात जरूर है। लेकिन उनका काम बजट का और घाटे का है उसमें भी घाटे का अलग अलग स्थान है। मेरा सुझाव है कि जो बजट में घाटा दिखा कर आपने जो घाटे को पूरा करने के लिए कर लगाये हैं, उसके लिए राज्य सरकार को और वित्त मंत्री महोदय को कुछ उन स्थानों पर कर लगाना चाहिए जिस से गरीबों पर असर कम हो। जितने कामों के लिए बजट में कर लगाये हैं वह थोड़ा सा किसानों और गरीबों पर ज्यादा है। इस बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं इसके विषय में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा आज जो बीस सूत्री कार्यक्रम है जो इसके बारे में कार्य चल रहा है उसमें सीलिंग और शहरी सम्पत्ति इसमें हमारी ढिलाई हर स्थान पर मुझे दिखाई देती है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हर एक गांव और हर एक किसान और मजदूर और हर तहसील में दो दो चार चार चालान हुए हैं। जिनको कोई सुनने वाला नहीं था उनके चालान किए गए हैं लेकिन जहां पर हजारों बीघा जमीन पर नाजायज कब्जे कर रखे हैं उनका कुछ भी नहीं बिगड़ सकते हैं और वह उन्हीं स्थानों पर कब्जा किये बैठे हैं, ज्यों के त्यों वहीं पर बैठे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय और राज्य सरकार के विभागों को देखना चाहिए कि क्यों ये नाजायज कब्जा किये लाखों एकड़ जमीन पर बैठे हैं। सरकार उनसे जमीन क्यों नहीं ले सकती। इसके साथ में सीलिंग में और खातेदारी में राज्य सरकार कार्यवाही करे। आज संसार में जो मौजूद नहीं है उनके भी खाते मौजूद हैं, जो पैदा नहीं हुए संसार में उनके नाम पर खातेदारी मौजूद है। इसके अलावा जो परिवार की परिभाषा घोषित कर रखी है उस परिवार की परिभाषा भी क्या है। एक परिवार जो पांच आदमियों का परिवार घोषित है लेकिन पांच आदमियों की अलग अलग खातेदारी है। एक परिवार की खातेदारी 54 एकड़ की होती है उसके बजाय पांच अलग अलग खाते बना रखे हैं। और पांच गुना फायदा उठा रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार को इस पर भी सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए। जो इस तरह से नाजायज फायदा ले रहे हैं, जो कानून से बचे रहे हैं उनके खिलाफ जरूर सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए और इससे लाखों एकड़ जमीन सरकार को मिलेगी और उस पर दलित वर्ग आबाद हो सकेगा। इसके ऊपर यह भी है कि सीलिंग के जमीन कुछ तो अभी मिली ही नहीं है, हमारे इलाके में अभी मिलने वाली है लेकिन अभी से इतना बोझ बढ़ गया है कि जिन गरीब आदमियों को हम जमीन देना चाहते हैं उनको दे नहीं सकते। ढाई सौ रुपया, तीन सौ रुपया, साढ़े तीन सौ रुपया बीघा तक वह कमी दे नहीं सकता। जिस गरीब आदमी के पास अपना कुछ भी नहीं है जो भूमिहीन है, वह भूमिहीन कभी इतनी रकम देकर जमीन ले नहीं सकता। जिसके पास बीस रुपया भी नहीं है वह ढाई सौ तीन सौ रुपये देकर कैसे जमीन लेगा ? हां उसके बदले में दूसरे लोग उसके नाम पर जमीन ले लेंगे और उसको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसमें आधी करे और इसके घाटे को कहीं और से पूरा करें और इन गरीब भूमिहीनों को इस तरह से जमीन

(श्री चतुरभुज चौधरी)

दी जावे तो उनको लाभ मिल सकता है और उनको मदद मिल सकती है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आज हमारे···

(म. प. 5.8 बजे)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

यहां पर···

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सभापतिजी, सदन में कोरम ही नहीं है।

श्री चतुरभुज चौधरी : एक ओर तो फसल खराब हो गई···

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सभापति महोदय, कोरम ही नहीं है सदन में।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया आसन ग्रहण करें। घण्टी बजायें।

(गण-पूरक-सूचक-घण्टी)

(गण पूर्ति के पश्चात्)

श्री चतुरभुज चौधरी : मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर आज मेडिकल का पैसा नाजायज तरीके से उठाया जा रहा है। क्या तो सरकारी कर्मचारी और क्या गैर सरकारी, सभी मैडिकल का पैसा नाजायज रूप से उठा रहे है और इससे सरकार को घाटा हो रहा है। इस नाजायज मैडिकल पर रोक लगायी जानी चाहिये। इससे ढाई करोड़ की, सरकार को बचत होगी।

इसके साथ ही टी. ए. और डी. ए. में भी करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। यह भी नाजायज है। यह जो नाजायज करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है वह सरकारी काम पर नहीं हो रहा है। अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी तफरी के लिए, सैर करने के लिए, कोई भी सरकारी काम निकाल कर सरकारी गाड़ियों में जाते हैं। गाड़ियों में पैट्रोल पानी की तरह बहाया जा रहा है। आज पैट्रोल चार रुपये लीटर है। यह भी कम से कम ढाई करोड़ का खर्चा है और उल्टा आप काश्तकार पर टैक्स लगा रहे हैं। राज्य कोष का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। इस पर रोक लगना मैं अति आवश्यक समझता हूं। नाजायज टी. ए. डी. ए. को रोका जाये तो कम से कम एक करोड़ रुपया बचेगा और मेडिकल पर रोक लगने से ढाई करोड़ रुपया बच जायेगा। इसलिए इस पर पाबंदी लगायी जानी चाहिये। वरना आम जनता यह समझेगी कि उनका पैसा नाजायज तरीके से खर्च किया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है। इस पर पाबंदी लगाई जाये और इस घाटे को पूरा किया जाये।

हमने जो बजट बनाया है, उसका पालन भी अनुशासन से करना चाहिये। सभी को जो साल भर का दायरा है उस में चलना चाहिये। इसलिए हमारे नेता महोदय को चाहिए कि वे हर मंत्री को कहें कि वे अपने अपने विभाग इसी बजट के दायरे में चलावें ताकि इस बजट का घाटा और न बढ़े। इसलिए हमारे मंत्रियों को भी अनुशासन में चलना चाहिए और इस नीति पर चलना चाहिये। नाजायज मेडिकल को बंद कर दें तो करीब एक करोड़ का घाटा पूरा हो जाता है। मेरी मान्यता है कि एक करोड़ का नहीं तो कम से कम 50 लाख का तो दुरुपयोग होता ही है। इसी तरह से नाजायज तरह से

(श्री चतुरभुज चौधरी)

पैट्रोल चलाया जा रहा है। आये दिन की यह हालत है। अगर इमरजेंसी में भी इसको रोका गया तो यह बंद नहीं होगा। अगर यह रोका जाए तो हमारा बजट सन्तुलित हो जाएगा। और विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए हमें अधिक धनराशि मिल जाएगी। आज गल्ले की क्या दुर्दशा हो रही है। किसान भारी दुखी है। किसान को एक एकड़ में करीब 400 रुपये का खर्चा आता है। उसे करीब 40 किलो तो बीज चाहिये। पिलायी और निंदाई आदि के लिए भी मजदूरी उसको चुकानी पड़ती है। यह सब खर्चा मिल कर 400 रुपये एक एकड़ पर होता है। और उससे उसको आमद क्या होती है? 900 रुपये का धान वह पैदा करता है। कुल चालीस मन अनाज पैदा होता है। इससे ज्यादा पैदावार नहीं होती है। दस फसल में से साढ़े तीन फसल ही पूरी उतरती है। यह तो हालत है। खर्चा काटने पर उसके पास 500 रुपये ही बचते हैं। अब आप बताओ इन पांच सौ रुपयों में वह बैलगाड़ी भी रखे, अपना और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण भी करे। यह सब कैसे सम्भव हो सकता है? पचास पर्सेन्ट किसान आज भूखे हैं। तीस साल की आजादी के बाद भी आज वह उसी पुरानी झोंपड़ी में रह रहा है। उसकी हालत नहीं सुधरी है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान पर आप ज्यादा अन्याय नहीं करें। वह दर पीढ़ी दर आपके साथ चला आ रहा है। नेहरूजी के नाम को वह ईश्वर के नाम के समान मानता है। इसलिए उनको सन्तोष दिलावें, ऐसा काम करें। उसमें असन्तोष पैदा न करें।

इसके साथ साथ मैं अपने क्षेत्र की दो-तीन मांगों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे मंत्री महोदय को यह काम करना चाहिये। हरिजन बस्ती में बिजली की व्यवस्था होनी चाहिये। जो दो–तीन सड़कें हैं उनको ठीक से बनाया जाना चाहिये। थोड़ा बहुत काम हो जावे हर क्षेत्र में, सरकार को ऐसी बात सोचनी चाहिये।

इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और जो बजट पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं और यह चाहूंगा कि किसानों को सन्तोष दिलाया जावे।

श्री विशम्भरनाथ जोशी (बांदी कुई): सभापति महोदय, मैं वित्तीय आय-व्ययक 1976-77 पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी मेरे बहुत पुराने फ्रेंड हैं उनके बारे में मेरी बड़ी अच्छी राय है लेकिन इस बजट को देखने के उपरान्त उन्हें मुबारकबाद देने का मेरा मानस नहीं बन पाता है इसका मुझे खेद है।

सबसे पहले मुझे यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने आज भारत की और राजस्थान की जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं उसमें जो एक घाटे का वह भी मार्जीनल नहीं बल्कि 27 करोड़ 70 लाख कुल मिलाकर घाटे का बजट पेश किया है। ऐसा करके उन्होंने एक प्रकार से देश के वित्तीय अनुशासन को वायलेट किया है...

श्री सभापति: कृपया उन्हें डिस्टर्ब न करें पास में बैठकर।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : हमारे आर्थिक तन्त्र को अभी एक जबरदस्त धक्का लगा था और उसको पूरी तरह से झंझोड़ दिया गया था जिसके फलस्वरूप एक लम्बे अर्से तक हमारे यहां पर एक ऐसा दौर चला कि कीमतें आसमान को छूने लगीं। सामान्य जन के लिए जीवन-यापन करना दुर्लभ हो गया था और जीवन की वस्तुएं मिलना दुश्वार हो गया। लोग बड़े परेशान होने लगे। इसके कारण हमारे प्रजातन्त्र को एक प्रकार से चुनौती आ गई। उस स्थिति में हमारे देश की सरकार ने क्रेडिट स्क्वीज के जरिये और अन्य फिस्कल मेजर्स के जरिये इन्फ्लेशन का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई और उसी प्रकार का वातावरण तैयार किया। रिजर्व बैंक ने क्रेडिट स्क्वीज किया। उसी दिशा में यह भी एक कदम होता है कि सरकारें, चाहे केन्द्रीय सरकार हो, चाहे वह राज्य सरकारें हों, अपने बजटों को सन्तुलित करें तथा ओवरस्पेन्डिंग न हो। ओवरस्पेन्डिंग अगर होने लगा और राज्य सरकारें बड़े पैमाने पर एक के बाद एक घाटे का बजट बनाती गई तो नतीजा यह होगा कि उस घाटे को पूरा करना पड़ेगा और वह केन्द्रीय सरकार के मत्थे पड़ेगा और उसको पूरा करना पड़ेगा केन्द्रीय सरकार को सारी सरकारों के घाटे को पूरा करना पड़ेगा तो अन्ततोगत्वा कोई विकल्प केन्द्रीय सरकार के पास नहीं रहेगा तो उसको यह मेथड एडाप्ट करना पड़ेगा कि डेफिसिट फाइनेन्सिंग में बड़ी मात्रा में नोट उसको बनाने पड़ेंगे। वह नोट सर्क्युलेशन में आयेंगे। उससे क्रय शक्ति लोगों की बढ़ेगी और समाज का उत्पादन उतना ही रहता है तो फिर वह इन्फ्लेशन का शिकंजा जिसको बड़ी मुश्किल से हम दूर कर पा रहे हैं उसमें जकड़ जायेंगे। अभी हाल ही में भारत सरकार के वित्त मन्त्री ने अपने एक भाषण में कहा था कि हमारी पालिसी क्रेडिट स्क्वीज की लागू रहेगी और सारे एन्टी इन्फ्लेशनरी मेजर्स लागू रहेंगे, और उसके बाद में राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों और राज्य सरकारों से कहा है कि अपने बजटों को सतुलित बनाने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता था कि हमारे अनुभवी वित्त मंत्रीजी इस दिशा में अपना योगदान जरूर देंगे और इस वर्तमान स्थिति पर नियंत्रण करेंगे। लेकिन मुझे खेद हुआ कि उन्होंने भी एक घाटे का बजट बनाकर एक प्रकार से एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत की जो कि अच्छी नहीं कही जा सकती। कुछ सरकारों ने अच्छे उदाहरण पेश किये हैं, उनका हम अनुकरण नहीं कर सके हैं और हमने अपना बजट घाटे का बनाया। वित्तीय अनुशासन की जो आवश्यकता है और आर्थिक तन्त्र में जिसकी जरूरत है, उस आवश्यकता को एक प्रकार से ध्यान में नहीं रखते हुए और उस स्थिति की कोई परवाह नहीं करते हुए किन्हीं अपने कारणों से उन्होंने यह बनाया है और समाज की आवश्यकता की हमने एक प्रकार से उपेक्षा की है।

मुझे खेद है, सभापति महोदय, कि असलियत से हमारे बजट के जो अनुमान होते हैं वह अन्डर एस्टीमेटेड होते हैं। आप पिछले तीन सालों के तीनों बजट उठाकर देख लें तो आपको यह पता लगेगा कि हम हमारी रेवेन्यू रिसीट्स को अन्डर एस्टीमेट करते हैं, और इसी वजह से अन्य करों से आने वाली आमदनी हमारे आंकड़ों से ज्यादा बनती है, रेवेन्यू

(श्री बिश्वम्भरनाथ जोशी)

रिसीट्स ज्यादा निकलती हैं। इसी प्रकार से एक्सपेन्डीचर को हम पिछले वर्षों से अन्डर एस्टीमेट करते चले आ रहे हैं, और इसलिए होता यह है कि हमारे बजट के जो आंकड़े हैं वह रियेलिस्टिक हो नहीं पाते हैं। पिछले वर्ष 74-75 में 12 लाख के एक मार्जीनल सरप्लस का ख्याल करके चलते हैं वह 12 लाख का सरप्लस पता नहीं किधर गया और बजट में 9 करोड़ 44 लाख का घाटा रहा। पिछले वर्ष भी वह घाटा जो है बढ़ा हुआ निकला है। इस साल जो 27.70 करोड़ के घाटे का अनुमान है तो जिस वक्त आप रिवाइज्ड बजट पेश करेंगे तो 76-77 का यह घाटा बढ़कर कम से कम 45 करोड़ का जरूर आयेगा। इस दृष्टि से मैं निवेदन करता हूं कि यह इतने बड़े घाटे का बजट रखना आज की स्थिति और परिस्थितियों में वित्तीय अनुशासन के तकाजे के बिल्कुल खिलाफ है।

इसके साथ ही वित्त मंत्रीजी ने कीमतों के गिरने के बारे में और उत्पादन के बढ़ने के बारे में और जीवन की आवश्यकताओं की एक अच्छी स्थिति होने के बारे में एक प्रकार से क्रेडिट लेने की कोशिश की है यह कह कर कि वितरण व्यवस्था में सुधार हुआ है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसका क्रेडिट आपको नहीं जाता है। जो भी स्थिति हमारे देश की है और राजस्थान उसका एक अविभाज्य अंग के रूप में है उसमें भी कीमतें घटी हैं। यह बात सही है कि कीमतें आसमान को छूती हुई उठी थी और पैदावार भी हमारे यहां पर बढ़ी है, केवल कृषि की पैदावार। मगर इन दोनों के लिए क्रेडिट केवल उसको जाता है एक एजेन्सी को, भारत सरकार को जिन्होंने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की और उसके बाद में फालो अप एक्शन में क्रेडिट स्क्वीज किया और एन्टी इन्फ्लेशनरी मेजर्स लिए और उसका ही यह फल हुआ कि आज यह स्थिति देश में हुई। उन बढ़ती हुई प्राइसेज पर ब्रेक लगा और प्राइस हाइक रुका ही नहीं कम हुआ है। यह सारे भारत का कामन फिनामेना है और उससे राजस्थान अछूता नहीं रह सकता था। पैदावार बढ़ने का जहां तक सवाल है उसका सेहरा तो भगवान को है, उसकी क्रेडिट सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा को है कि उसने अच्छा मानसून दिया और पिछले सारे वर्ष मौसम अच्छा रहा। लोग यह कहते हैं कि शायद 50 सालों में इतनी अच्छी और बढ़िया बारिश नहीं हुई....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : साथ ही साथ काश्तकारों को धन्यवाद दें कि उन्होंने मेहनत की....

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : वह तो हमेशा ही करते हैं उसके बावजूद परिणाम अच्छा तब निकलता है जब कि इन्द्र भगवान की कृपा होती है। इन्डियन एग्रीकल्चर इज ए गेम्बलिंग इन मानसून्स। वह बात अभी भी चल रही है। हमारे यहां पर यह कहा जाता है कि खेती की जो उपज है, खाने की वस्तुयें हैं, सीरियल्स नाज, तिलहन वगैरह, इनकी कीमतों पर ही दूसरी वस्तुओं की कीमतें मुनस्सर करती हैं और इन चीजों की कीमतों का जो रुख है कि तेजी की तरफ जाने वाला है या मन्दी की तरफ जाने वाला है इस पर अन्य सब चीजों की प्राइसेज डिटरमिन होती हैं। मानसून अच्छा हो गया तो फेवरेबल दरें होंगी।

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

वितरण व्यवस्था का जहां तक सवाल है, तो माननीय वित्त मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज ही सुबह जब मैं घूमने जा रहा था तो अखबार वाला एक अखबार डाल गया था वह शायद था राजस्थान पत्रिका और उस अखबार के लिए हम नहीं कह सकते हैं कि गैर जरूरी तौर पर सरकार की खिलाफत करता है। वह अच्छे ढंग से बात करता है। उस अखबार के प्रथम पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि राशन की चीनी की हजारों बोरियां गायब आज के अखबारों में लिखा हुआ है। वितरण व्यवस्था जो आपकी है वह इस प्रकार की है। जिसके बारे में आप कहते हैं उसकी व्यवस्था यह है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसके बजाय बाजारों में अनाज सस्ता है। वितरण व्यवस्था को कोई पूछता ही नहीं है।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : इसलिए यह श्रेय इन परिस्थितियों को जाता है। इसका श्रेय हमको नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि धन्यवाद उनको देना चाहिए जिनके कार्यों के फलस्वरूप यह स्थिति आई है। उसका आभार प्रदर्शन नहीं करें तो गलती होगी। कोआपरेटिव सैक्टर के बारे में अभी मन्त्री महोदय ने फरमाया था और इस बात पर कि शार्ट टर्म, मीडियम टर्म और लांग टर्म लोन उन्होंने सहकारी क्षेत्र में रखे हैं। वह तो अच्छा किया है। लेकिन केवल आप वित्तीय प्रावधान करके सन्तोष कर लें, जिस पर हमारे सारे आर्थिक प्रावधान निर्भर करते हैं तो बहुत ठीक नहीं है। यह किसी से छुपा नहीं है कि कोआपरेटिव सैक्टर में कितने घोटाले हैं। कोआपरेटिव सैक्टर हर प्रकार के घोटालों का घर है। अच्छे अच्छे लोगों की इस बारे में यही राय है। वह एक प्रकार से लाइलाज हो गया है। यह कहा नहीं जा सकता है कि इसका हम इलाज कर सकेंगे या उनके बारे में कोई कारगर कदम उठायेंगे।

(व्यवधान)

कोआपरेटिव में कितने घोटाले हुए हैं। कितनी इर्रेग्युलरिटीज पकड़ी गई हैं। कितने रिलीज किये हैं। कितने बैंक घाटे की स्थिति में चल रहे थे, उनमें से कितनों को ठीक किया है। यह आप देते तो अच्छा होता। कितने डिफाल्टर्स को सजा दी है। ये बातें देते तो ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि भविष्य में जो क्रेडिट फ्लो होगा वह कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा होगा। किसानों के हर सैक्टर को, इण्डस्ट्रीज को अब भारत सरकार की ओर से भी सारा लोनिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा होने वाला है। इसलिए जो बैंक वगैरह कर रहे हैं, वह कोआपरेटिव सोसायटीज के द्वारा है। इसलिए यह अहमियत है कि आप कोआपरेटिव सोसाइटीज को सुधारें रूरल बैंकों के बारे में आपने कहा है। हमने जो यह कदम उठाये हैं, वह बहुत ही कम भूमि वाले जो विलेज आर्टिजन्स हैं, उनके लिए मांग की है। वास्तव में यह कदम सराहनीय है। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ है कि जो लोग पहले ऋण देते थे। वस्तुतः उन्होंने देना बन्द कर दिया। और, जो कर्जा देते हैं तो वह सोना, चांदी गिरवी रख कर देते हैं। जितना कर्जा देते हैं, उससे ज्यादा

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

का सोना, चांदी गिरवी रखते हैं। ऐसे ऊंचे रेट पर कर्जा लेने के लिए गांव वालों को मजबूर होना पड़ा है। आप उनको आल्टरनेटिव लोनिंग एजेन्सी प्रोवाइड नहीं कर पाये हैं। वह व्यवस्था हम नहीं कर सके हैं। तैंतीस हजार गांवों के लिए केवल 8 हजार शाखाएं खुली हैं। अभी यही हुआ है। ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहावत हुई है। तो वह उसी प्रकार की बात हो जाएगी, ड्राप इन दी ओसन। समुद्र में बूंद हो जाएगी।

इरिगेशन के बारे में मुझे यही कहना है कि आपने अधिकांश धनराशि केवल दो बड़ी योजनाओं पर खर्च कर दी। यह ठीक है कि राजस्थान केनाल एक बड़ी योजना है। दूसरे इलाकों में भी उसको विकेन्द्रित किया जाना चाहिए। किन्तु हमारा सारा जो बजट है, उसकी मद कहीं ज्यादा दो योजनाओं पर खर्च कर दी। इतना बड़ा राज्य है राजस्थान, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा राज्य है। यहां आपको मध्यम सिंचाई की योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जो काम आज से चार-पांच साल पहले शुरू हो गये थे, वह अधूरे पड़े हैं। पिछले सालों में एक भी माइनर इरिगेशन योजना में काम नहीं हुआ है। जिनमें से एक का शिलान्यास भूतपूर्व मुख्य मन्त्री सुखाड़िया जी ने किया था। आज से 6 साल पहले किया था। जो पिछले चार साल से स्टेगर्ड कर दिया गया है। वह मेरे क्षेत्र बांदीकुई में है। आखिर तीसरा, चौथा, पांचवा साल हो गया है। कितना इन्तजार करना पड़ेगा इस क्षेत्र के लोगों को जब आपने माही का जो प्रावधान किया है, वह 6 करोड़ का है। उसकी राशि को दुगना कर दिया गया। डबल कर दिया है। आप उसको डेढ़ गुना ही करते। और, जो पिछले काम स्टेगर्ड हैं, उनके लिए खर्च करते तो खेती के लिए ज्यादा काम हो सकता था। प्लानिंग कमीशन में यह इनवेस्टमेण्ट की सुविधा है जो हर एक को दी जानी चाहिए। जयपुर, अजमेर और ऐसे कई इलाके हैं जहां की सोइल बहुत अच्छी है। कुछ साधन आप कर देते तो मेग्जिमम खेती की पैदावार हो सकती थी। हरियाणा की तरफ भी पैदावार हो सकती थी। दूसरे राज्यों से हमे मंगाने की आवश्यकता नहीं रहती। डेफिसिट स्टेट से हम सरप्लस स्टेट बन सकते हैं। वह आपने तरीका अपनाया नहीं है। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा, आज इस प्रकार से एक जबरदस्त क्षेत्रीय असन्तुलन व्याप्त है। इस सरकारी खजाने को जयपुर डिवीजन वस्तुतः 50 प्रतिशत देता है। इसकी उपेक्षा की गई है और घोर उपेक्षा की गई है। राजस्थान जब से बना है, एक भी इरिगेशन प्रोजेक्ट सारे जयपुर डिविजन में आपने नहीं दिया है। और न ही उसके अन्दर एक भी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट दिया गया है। राजस्थान कैनाल के लिए अरबों रुपये की धनराशि खर्च की जा रही है। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट की आधा बूंद पानी भी जयपुर डिवीजन में आने की संभावना नहीं है। ठीक है कि यहां पर बड़ी बड़ी नदियों का अभाव है, लेकिन यहां की सॉइल फर्टाइल है और वाटर लेवल ऊंचा है। आप जयपुर डिविजन की हर पंचायत समिति में नलकूपों का जाल बिछा सकते हैं, और यह आपके लिये बहुत आसान भी होगा इससे अच्छे नतीजे आपके सामने आवेंगे,

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

पैदावार भी अधिक बढ़ेगी और इसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिल सकेगा। यह ट्यूब वेल बनाने का अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड का काम था लेकिन उसने इस दिशा में कोई भी काम नहीं किया और हमेशा का रवैया दिखाया है राजस्थान के इस सबसे बड़े डिवीजन के प्रति। इरींगेशन के मामले में देख लीजिये या सड़कों में या और किसी मामले को ले लीजिये, हर क्षेत्र में राज्य सरकार इस डिवि-जन के लिये उपेक्षापूर्ण रवैया दिखा रही है बावजूद आपका बार बार ध्यान दिलाये जाने पर। मैं आपको तारीख तो नहीं बता सकता, लेकिन सदन के माननीय नेता ने, श्री जोशीजी ने बहुत बहस के बाद, मुझे तारीख तो याद नहीं है, राज्यपाल महोदय के भाषण पर बहस के समय या बजट भाषण के समय जब वे जवाब दे रहे थे तो उन्होंने फरमाया था, क्षेत्रीय असन्तुलन की बात आई तो उन्होंने फरमाया था कि अगर ऐसा है तो इसके कारणों का मैं इन्वेस्टीगेशन करना चाहूंगा और अगर ऐसा पाया गया तो यह सरकार की और मेरी जिम्मेदारी है, और जो भी कार्यवाही उचित होगी, वह की जायगी। और प्लान उस समय तक फाइनल नहीं किया गया था उसके बारे में यह आश्वासन दिया था कि यदि उसमें फेर बदल की आवश्यकता हुई तो वह भी किया जायगा। लेकिन मुझे दुःख है कि जोशी जी के आश्वासन के बावजूद भी ऐसा नहीं किया गया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आश्वासन दिया था। सदन के अन्दर सदन के नेता द्वारा दिये हुए आश्वासन के ऊपर आपने कौन कौन से कदम उठाये और वह असन्तुलन किस हद तक दूर हुआ, उसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं है। मैं बहुत ही नम्र शब्दों में कहूंगा कि बहस का उत्तर देते समय मुख्य मंत्रीजी या वित्त मंत्रीजी इसका उत्तर देने की कृपा करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि श्री जोशी जी जैसे नेता आश्वासन देते हैं तो उसको गम्भीरता से लेना चाहिए और उस पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए थी। जब वे आश्वासन देते हैं और कार्यवाही नहीं होती है तो फिर एक निराशा की भावना जाग्रत होती है और उनके वचन पर, उनके आश्वासनों पर उनके कथन पर से जनता का विश्वास उठ जाता है, इसलिए इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। It is never two late to mend.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जोशी जी के आश्वासन को तो वित्त मंत्रीजी को भी बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : बजट की रूप-रेखा बनाते समय सदन में दिये गये आश्वासनों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा पावर जनरेशन के बारे में मुझे यह कहना है कि नई विद्युत योजनाओं को आपने चालू किया है और आपका कहना है कि हम पावर को ठीक से वितरण करने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि दूसरे राज्यों में गलतियां हो रही हैं वह हम भी कर रहे हैं। यह एक तथ्य है कि एट-मिक पावर जनरेशन विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही ऊंची चीज है, यू. एस. ए. में भी है, ग्रेट ब्रिटेन भी इसका प्रयोग कर रहा है और दूसरे देशों में भी इस विषय में अनु-संधान जारी है, लेकिन वहां भी बहुत

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

सन्तोषजनक तरीकों से काम नहीं हो रहा है। अमेरिका में भी यह हालत है कि दो महीने काम किया और फिर बन्द हो गया फिर चार महीने तक चालू रहा, फिर खराब हो गया। जिस तरह से आपका राणा प्रताप सागर चलता है कुछ महीने चलेगा और फिर बन्द हो जाता है फिर आप नहीं कह सकते कि कितने दिनों में वापिस चालू होगा। जब वह बन्द हो जाता है जो कि दो सौ मेगावाट का उत्पादन करता है तो फिर आप दूसरी बिजली को रेस्ट्रिक्ट करने लगते हैं, इसके अलावा और चारा ही क्या है आपके पास। असलियत में हम लोग नावल्टी की तरफ दौड़ते हैं न्यूक्लियर टेक्नालाजी फार पावर जनरेशन क्रेज फार नावल्टी। इस प्रवृत्ति को हमको छोड़ना चाहिए और हमको इसके लोभ को संवरण करना पड़ेगा, असलियत में दूसरे देशों में भी अभी इस पर प्रयोग हो रहे हैं और हमारे यहां तो यह टेकनालोजी शैशवावस्था में है। और ऐसी हालत में भारत जैसे गरीब देश के पास जहां सीमित साधन हैं, उसका भी अगर एक बहुत बड़ा भाग उसमें लगा दिया तो हम उचित न्याय नहीं कर पायेंगे। राणा प्रताप सागर पर आपने लगा दिया, एक और रिएक्टर वहां लगा रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक और लगा रहे हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह आप सैंकड़ों और अरबों रुपयों का खर्चा करने जा रहे हैं और हम इसमें ज्यादा समझते भी नहीं। हाइली और मोस्ट हाइली टेक्निकली एडवान्स्ड कन्ट्रीज के भी यह काबू में नहीं आ रहा है। दूसरे साधनों को हम इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा है हाइडल पावर, इसमें हमको रेनफॉल पर निर्भर रहना पड़ता है। मानसून की मर्जी पर है। वर्षा कम होती है तो अकाल पड़ जाता है और पावर जनरेशन घटानी पड़ती है, लोगों के घरों में भी बिजली की कटौती करनी पड़ती है। किसानों को सिंचाई के साधन भी देने में हमको बाधा होती है और नतीजा यह होता है कि हमारे पर दुतरफा मार पड़ती है। अभी नरौरा में थर्मल जनरेशन के लिए भी निर्णय लिया गया। उसके बारे में हमको इस बजट में कहीं पढ़ने को नहीं मिला है, नमालूम इसका क्या कारण है जिसको कि दूसरे प्रदेशों में तो अपनाया जा रहा है और इस पर स्ट्रेस किया जा रहा है, इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इस विषय में अगर आप कोताही नहीं करते तो मानसून की मेहरबानी पर और राणा प्रतापसागर पर जो हमको निर्भर रहना पड़ता है वह नहीं रहना पड़ता और किसान और मजदूरों का भविष्य भी एक अनसर्टेन फेक्टर पर निर्भर नहीं रहता। इस दिशा में भी निवेदन करूंगा कि हमको कुछ भविष्य के लिए सोचना चाहिए और इसके बारे में कुछ करना चाहिए।

एक आपने कहा कि शायद खुद अपने अनुमान सही निकल गये, जिस प्रकार आप सोचते हैं उस प्रकार योजना के लक्ष्य प्राप्त कर लिये ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में तथा आशा करके चलते हैं कि आठ हजार एक सौ प्लान के एण्ड तक आप · · ·

श्री चन्दनमल वैद : अगली साल के एण्ड तक।

श्री बिश्वम्भर नाथ जोशी : 1976–77 के एण्ड तक दे पायेंगे। मैं निवेदन करूंगा तेंतीस हजार में से आठ हजार गांव को बिजली देने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वह लक्ष्य पूरा भी हो जाता है, उसके बाद भी कुछ देहाती क्षेत्र हैं उनका एक चौथाई भी इलेक्ट्रिफाई नहीं कर पायेंगे। जब तुलना करते हैं, हमारे पड़ोस में बहुत छोटा सा राज्य है, हरियाणा, राजस्थान से उसकी, तो मुझे तुलना को देख कर अफसोस होता है कि हमारा राज्य, जिसके इतने उत्साही मंत्री महोदय हैं, पुराना राज्य बना हुआ है और हरियाणा अभी कुछ साल पहले बना है, उस हरियाणा के मुकाबले में राजस्थान कितना पिछड़ा हुआ है। इस बात को देख कर हैरत होती है, दुःख होता है, राजस्थान के पिछड़ेपन पर बड़ा दुःख और क्षोभ भी होता है...

श्री रघुनाथ विश्नोई : छोटा भी है हरियाणा।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा, आर.एस.ई.बी., जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत चलता है, उसके आर्टिकल 52–53 में प्रावधान है, आर. एस. ई. बी., कोई भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में नहीं चलेगा, न ही चलने दिया जायगा। घाटे में चलने का सवाल हो उनके कारण जो दूसरी पावर इंडस्ट्री हैं, दूसरे पावर हाउस चल रहे हैं तो उनको एक्वायर करने के पावर्स दिये हैं, कर भी लिये हैं। पावर जनरेशन है उसमें परिपूर्ण मोनोपोली है। उसके बाद भी घाटे में चल रही है। इसका कारण क्या है। हमारी लापरवाही है, या हमने शायद बहुत अयोग्य लोगों को बैठा रखा है–यह समझ में नहीं आता है। एक्ट का मैण्डेटरी प्राविजन है, उसके अनुसार आर.एस.ई.बी. चलना चाहिए। हम देखते हैं लाखों रुपये माहवारी पावर की चोरी होती है बिजली की क्योंकि हम मीटर सप्लाई नहीं कर पाते हैं। मीटर एक साधारण और सिम्पल इन्स्ट्रूमेंट है। इसके अलावा दूसरे उपकरण हैं, कभी ट्रान्सफार्मर नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। हम मांगते हैं तो समय पर मिल नहीं पाते हैं। इसमें डिपार्टमेंट का खुद का रुख जस्ट नहीं होता। आर. एस. ई. बी. जिस एक्ट के तहत बना है, उसके आर्टिकल आफ एसोसियेशन में यह है, वह बहुत विस्तृत है कि वह हर प्रकार के उपकरण मैन्युफेक्चर कर सकता है। यह इन्डस्ट्री सेट अप है, इस पर दो सौ करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया है। यह पहले का है, अब मैं समझता हूं कि ढाई सौ करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया है, इतनी राशि का सरकारी खजाने से एक्सपेंडिचर हुआ है, दो सौ करोड़ पहले वक्त का है जब मैं पी. यू.सी. का चेयरमैन था। इस वक्त ढाई सौ करोड़ हो गया होगा, ढाई सौ करोड़ से ऊपर चला गया होगा। मैं समझता हूं, इसके बाद और लोन ले सकते हैं, एल. आई. सी. से और फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं, आर. एस. ई. बी. के बिजली के मैटिरियल की। इससे बिजली सप्लाई रोकनी नहीं पड़ेगी, उपकरणों की कीमत ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी और काम नहीं रुकेगा। आज आर. एस. ई. बी. में बहुत बदइन्तजामी है। मैं बदइन्तजामी का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि खरीद में कितना घोटाला है, प्रबन्ध में कितनी बदइन्तजामी है, इसका नमूना यह

(श्री विश्वम्भर नाथ जोशी)

है एक घोटाला था जेवरा कन्डक्टर का। इसमें ढाई करोड़ का नुकसान हुआ है, 2.5 का। इसमें इन्ट्रेस्ट लाखों का पड़ रहा है। कई साल तक 2.5 करोड़ का इन्ट्रेस्ट लगाया जाय कि ढाई करोड़ पर कितना होता है यह घोटाला जेवरा कन्डक्टर का है, उसको गम्भीरता से लेना चाहिए, दोषी लोगों को सजा देनी चाहिए। लेकिन रेस्पान्सिबिलिटी जिस लेवल पर फिक्स की जानी चाहिये वह नहीं की गई है। इसका नतीजा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जितना टाइट और व्यवस्थित होना चाहिए वह नहीं कर सके हैं। यह मुझे पावर जनरेशन के बारे में निवेदन करना था।

अब आपने खुद भाषण के दौरान जिक्र किया है रूरल वाटर सप्लाई कोर्पोरेशन भी आप खोलने जा रहे हैं। आप रूरल वाटर सप्लाई कोर्पोरेशन खोल रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। कई कोर्पोरेशन और बोर्ड बहुत पहले बना दिये हैं। कोर्पोरेशन, बोर्ड, कमीशन बनाने और सेट अप करने का जहां तक सवाल है, उसमें राजस्थान सरकार, मैं समझता हूं, देश की समस्त सरकारों से आगे होगी। सबसे आगे है, इस बात को स्वीकार करने में एतराज नहीं है। यह बना रहे हैं, इसके पीछे इसके इम्प्लीकेशन को आप रियलाइज कीजिये। आपने बनाया है, मान लीजिये, ट्राइबल डवलपमेंट के बारे में कमीशन, बोर्ड भी, कमीशन भी...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : डेजर्ट का पता नहीं है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : तो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके अलावा ट्राइबल डवलपमेंट कमीशन को एडवाइजरी फंक्शन एन्ट्रस्ट करने जा रहे हैं। जितने कोर्पोरेशन और बोर्ड बने हैं यह तमाम भी अधिकांश थ्योरली एडवाइजरी हैं केवल सलाह देने का काम है। आप एक्जीक्यूटिव फंक्शन एन्ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं वह काम करेगा विभाग। आपका जो विभाग है, वह करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। यह केवल एडवाइजरी है, तो मैं निवेदन करूंगा कि इनको सेट अप करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। यह मैं जानना चाहूंगा। आपके अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं जिनकी जिम्मेवारी है उन विभिन्न योजनाओं को पूरा करना है, उन विभिन्न कामों को सम्पादित करने की। मेरे पास कई मिसालें हैं, एक मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करूंगा, आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जिसके पास प्रावधान है, और अधिकार हैं, प्रोग्राम है, एरिया के डवलपमेंट का, यह काम उसके पास है, कुछ हद तक पंचायत और डवलपमेंट विभाग के पास है, फारेस्ट डिपार्टमेंट के पास भी है। यह विभिन्न डिपार्टमेंट क्या असफल रहे हैं, असमर्थ रहे हैं, गुड्स डिलीवर नहीं कर सके हैं फेल हुए हैं...

श्री रघुनाथ विश्नोई : उनमें विश्वास नहीं है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : उनमें विश्वास नहीं है कार्य संचालन का, इसलिए मजबूर होकर अलग पैरेलल एजेन्सी सेट अप करनी पड़ी है। नार्मल एजेन्सी, डिपार्टमेंट के ऊपर से हट गया, इसलिए यह सेट अप करना पड़ा....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जी नहीं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इसलिए यह करना पड़ा कि कोई व्यवस्था स्वस्थ व विश्वास की व्यवस्था होने से काम अच्छा चल जायेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन बोर्ड, कोर्पोरेशन, कमीशन का एक्जीक्यूटिव फंक्शनिंग नहीं है, केवल सलाह इनको देनी है। सलाह अन्ततोगत्वा मिनिस्टर, हैड्स आफ डिपार्टमेंट के पास जाती है, और सरकारी मशीनरी के लोग उसे एक्जामिन करके उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उनके द्वारा आप किस प्रकार से और कार्य में गति ला सकते हैं, किस प्रकार से लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं — यह किस प्रकार विश्वास होता है ?...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इलाकों के विकास की दृष्टि से प्रायोरिटी देते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जी नहीं, आप जैसे बोलने वालों को चुप करके वहां बैठाने का प्रबन्ध किया गया है।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, क्या यह अलाउड है कि दो मेम्बर एक स्पीच दें।

श्री सभापति : मैं समझता हूं, सभी सम्माननीय सदस्य समझदार हैं, इसलिए मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गौरी शंकर मुनीम : सभापति महोदय, छः बज गये हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : हमने हमारे प्रशासन में एक बहुत बड़ी खराबी इन्ट्रोड्यूज कर दी है। इस प्रकार हमने अपने प्रशासन के अन्दर एक डोइरेशन का प्रवेश करा दिया है। क्यों इन्ट्रोड्यूज किये हैं, बोर्ड, कोर्पोरेशन और कमीशन ? बोर्ड, कोर्पोरेशन और कमीशन स्थापित करके जनता के पैसे को बरबाद कर रहे हैं। यह एजेंसी काम कर सकेंगी—इसमें मुझे डाउट है···

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : व्यक्ति और बोलने वाले हैं इसलिये समय बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। (विराम) एक प्रस्ताव कभी कभी रखते हैं उसको मंजूर नहीं करते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! आसन ग्रहण करें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं निवेदन करूंगा कि अभी तो भाषण आधा भी नहीं कर पाया हूं।

कई माननीय सदस्य : कल के लिए रख लें।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 12 मार्च, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.00 बजे शुक्रवार दिनांक 12 मार्च, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

(110)

परिशिष्ट – 1

(तारांकित प्रश्न सं. 37 की सूची)

सूची 'अ'

हनुमानगढ़ आर.ई.सी. योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु

	प्रस्तावित	उपलब्धि जनवरी 76	उपलब्धि का प्रतिशत
1. विद्युतिकरण किये जाने वाले गांवों की संख्या	34	34	100
2. 33 के.वी. लाइन्स (किलो मीटर्स)	47	26	55.43
3. 11 के. वी. लाइन्स (किलो मीटर्स)	172	173	100.00
4. एल. टी. लाइन्स (किलो मीटर्स)	178	104	58.79
5. कुओं की संख्या	574	328	57.14
6. अन्य कनेक्शन्स	2573	1828	71.04
7. कुल कनेक्शन्स	3147	2156	68.57

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 40 के आदेश की प्रति)

Certified copy of stay order dated 29-7-75 in S. B. Civil Misc. Stay Petition No. 1113 of 1975, in S. B. Civil Writ Petition No. 1228 of 1975.

PETITIONER

Gujar Mal son of Shri Ganga Sahai by caste Brahmin, resident of village Chandpuri Tehsil Thanagazi, District Alwar.

Versus

RESPONDENTS

1. The State of Rajasthan.
2. Shri Ram Narain Chaudhary, Minister for Community Development and Panchayat, Government of Rajasthan, Jaipur.
3. The Additional Secretary to the Govt. (Inquiry) Community Development and Panchayat, Government of Rajasthan, Jaipur.
4. Shri Chiranji Lal son of Shri Sheoji Ram, Mahajan by caste, resident of village Ajabpura, Tehsil Thanagazi, Distt. Alwar.
5. Shri Bhanwar Singh son of Shri Moolsingh Rajput by caste, resident of village Ajabpura, Tehsil Thanagazi, Distt. Alwar (Raj.).
6. In the High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur.

Date of order 29-7-75.

Hon'ble Joshi J.

Mr. P. N. Dutt for the petitioner.

Issue notice of the stay application. Meanwhile the operation of the impugned order dated 19th July, 1975 (Annexure 10) removing the petitioner from the office of Sarpanch is stayed till further orders. The notices shall be given 'Dasti" to the learned counsel for the petitioner. The rule is made returnable within three weeks.

Sd/- M. L. JOSHI J.

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

भेड़ व ऊन जिला अधिकारी का कार्यालय

42. श्री शंकरलाल (पाली)–क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पाली, सिरोही और जालोर जिलों का जिला अधिकारी कार्यालय केवल एक जालोर में कार्यरत है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(2) क्या यह सही है कि इन तीनों जिलों में पाली जिला सबसे बड़ा जिला है और भेड़ व ऊन विभाग की दृष्टि से भी सबसे अधिक कार्य पाली जिले में रहता है?

(3) क्या सरकार जिला अधिकारी कार्यालय पाली में रखने का विचार करेगी?

उत्तर

(1) जी हां, सन् 1967 से पहिले पाली एवं सिरोही के लिये जिला भेड़ व ऊन कार्यालय अलग था। सन् 67 में हुई राज्य व्यय में आर्थिक कटौती के कारण राज्य सरकार को पाली के जिला अधिकारी कार्यालय को बन्द करना पड़ा।

(2) यह सही है कि इन तीनों जिलों में से पाली जिला सबसे बड़ा है, परन्तु सभी बातों को ध्यान में रखते हुये कार्य वितरण एवं सुविधा की दृष्टि से फिलहाल जालोर जिले में ही जिला अधिकारी कार्यालय स्थित है।

(3) जी नहीं।

पंचायत समिति, शाहबाद में ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थान

43. श्री रामगोपाल (किशनगञ्ज)–क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि पंचायत समिति, शाहबाद जिला कोटा में सीताबाड़ी, कपिलधारा, कन्यादह और रामगढ़ आदि ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनका पर्यटन विभाग की ओर से विकसित किया जाना अत्यावश्यक है? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

जी हां, सामान्यतया ऐसे सामान्य स्थान को भी विकसित किया जाना उचित ही है। किन्तु समुचित धनाभाव के कारण व इन स्थानों के रेल मार्ग से सम्बन्धित न होने व जिले का मुख्यालय न होने से इनको विकसित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये हैं।

विजयनगर क्षेत्र के हरिजन भूमिहीनों को भूमि का आवंटन

44. श्री बेगाराम चोहान (रायसिंहनगर)–क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि उपनिवेशन क्षेत्र विजयनगर के हरिजन भूमिहीनों ने दिनांक

(श्री बेगाराम चौहान)

30 दिसम्बर, 1975 तक करीब 1175 प्रार्थना-पत्र भूमि आवंटन के लिये दिये थे जिनमें से करीब 76 व्यक्तियों को लाटरी निकाल कर भूमि का आवंटन किया गया? यदि हां, तो शेष व्यक्तियों को भूमि का आवंटन कहां किया जावेगा?

उत्तर

जी नहीं। उपनिवेशन क्षेत्र, बिजयनगर, में दिसम्बर, 75 तक 1790 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के भूमिहीनों के 'एफ' प्राथमिकता के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 616 प्रार्थियों के आवेदन-पत्र अपात्र पाये जाने से अस्वीकृत हुए तथा 79 को आवंटन किया गया। शेष 1095 भूमिहीनों को तहसील में भूमि उपलब्ध न होने से आवंटन नहीं हुआ। आवंटन नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है तथा इन शेष पात्र व्यक्तियों को बाकी बची भूमि का आवंटन इस कैटेगरी के पत्र सवर्ण घोषित होने उन दोनों को मिलाकर उनकी सम्मिलित लाटरी निकाली जायगी।

बीकानेर जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां

45. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर को दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समितियों के गठन एवं अन्य कार्यों के निमित्त परियोजना अधिकारी एवं अन्य आवश्यक कर्मचारी दिये गये हैं? अगर हां, तो उन्होंने अब तक कुल कितनी समितियां बना कर पंजीयन हेतु, सहायक पंजीयक, बीकानेर के कार्यालय में प्रस्तुत कीं तथा उनमें से अब तक कुल कितनी समितियां पंजीकृत की गईं?

(2) क्या यह सही है कि एक ही गांव में एक ही दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का गठन एवं पंजीयन होना उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ सहकारी भावना को बढ़ावा देने के लिये उचित समझता है? अगर हां, तो ग्राम शेखसर के बास खोडाला में पूर्व में एक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के कार्यशील होते हुए क्या दूसरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का गठन किया गया तथा क्या इस गठन में परियोजना अधिकारी के माध्यम से समिति-गठन की कार्यवाही की गई? अगर नहीं, तो सहायक पंजीयक, बीकानेर द्वारा यह अनुचित एवं गैर कानूनी कार्यवाही कैसे की गई?

(स्थगित किया गया)

भू. पू. नरेशों से अवाप्त की गई भूमि

46. श्री ओंकार लाल चौहान (उग): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत कितनी भूमि भूतपूर्व राजाओं (नरेशों) से अवाप्त की गई है? कितनी-कितनी भूमि किस किस भूतपूर्व नरेश से अवाप्त की गई है, दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री ओंकार लाल चौहान)

(2) इस अवाप्त भूमि को क्या भूमिहीन लोगों में वितरण किया गया है? यदि हां, तो इसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर :

(1) राजस्थान में राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत भूतपूर्व नरेशों से कुल 52,764 (बावन हजार सात सौ चौसठ) एकड़ भूमि अवाप्त की गई है। प्रत्येक भूतपूर्व नरेश से अवाप्त की गई भूमि का विवरण सूची में अंकित कर दिया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अवाप्त की गई भूमि में से 567-74 एकड़ भूमि को 128 भूमिहीनों को सिरोही जिले में आवंटित किया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पूर्व में उच्च न्यायालयों के स्थगन आदेश के कारण भूतपूर्व नरेशों से भूमि अवाप्ति का कार्य सम्पन्न नहीं हो सका था। उपरोक्त भूमि की अवाप्ति अभी हाल ही हुई है। अतः भूमिहीनों को आवंटन करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

भूतपूर्व राजाओं से अधिग्रहीत भूमि का वितरण (सूची–1)

क्र.सं.	नाम	क्षेत्रफल अधिग्रहीत राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत (एकड़ों में)
1	2	3
1.	अलवर	105
2.	किशनगढ़	5849
3.	बीकानेर	6441
4.	बूंदी	1224
5.	भरतपुर	– नोटिस जारी किया जा चुका है। सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित कर दी है।
6.	धौलपुर	– नोटिस जारी किया जा चुका है। सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित कर दी है।
7.	बांसवाड़ा	2501
8.	कुशलगढ़	1014
9.	शाहपुरा	– कार्यवाही की जा रही है।
10.	डूंगरपुर	17592
11.	जयपुर	नोटिस दिया जा चुका है। सुनवाई चल रही है।
12.	जैसलमेर	1788 एकड़ भूमि धारा 6(1) व 6(2) के अधीन खातेदारी अधिकारी माने जाने से वास्तविक कब्जा किसी क्षेत्रफल का नहीं लिया गया है।
13.	जोधपुर	16661
14.	झालावाड़	– राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम, 1975 के अंतर्गत कोई भी भूमि अधिग्रहण योग्य होना नहीं बतलाया गया है।

(116)

1	2		3
15.	कोटा	–	उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कार्यवाही रुकी हुई है।
16.	प्रतापगढ़	–	कार्यवाही की जा रही है।
17.	सिरोही	574	
18.	करौली	–	
19.	टोंक	447	राजस्थान भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी भूमि अधिग्रहण किये जाने योग्य नहीं बतलाया गया है।
20.	लावा		
21.	उदयपुर	356	
	योग	52764	

राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत सिरोही जिले में आवंटित भूमि की सूचना। (सूची–2)

क्र.सं.	नाम जिला		संख्या व्यक्तियों की जिन्हें भूमि का आवंटन किया गया है।	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	सिरोही	(1) अनुसूचित जाति	69	232–40
		(2) अनुसूचित जन-जाति	22	82–00
		(3) सैनिक	1	4–00
		(4) अन्य व्यक्ति	36	249–34
		योग–	128	567–74

जेलपुरा-बड़गांव नदियों की सिंचाई योजना

47. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में जेलपुरा-बड़गांव नदियों की एक सिंचाई योजना बनी हुई है ? अगर हां, तो यह योजना क्या है ?

(2) क्या यह सत्य है कि अभी दोनों नदियों का पानी टेप किया जाकर उनका पानी सिंचाई हेतु अब तक काम में नहीं लिया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ? दोनों नदियों का पानी टेप किया जाकर सिंचाई हेतु कब तक काम में ले लिया जाने की संभावना है ?

(3) क्या यह सत्य है कि अभी इन नदियों का पानी गुजरात में जा रहा है ? अगर हां, तो इस पानी को गुजरात बोर्डर पर बंधे बांधे जाकर सांचोर की तरफ कब तक डाइवर्ट कर दिया जावेगा ? उक्त योजना से कितने क्षेत्र में सिंचाई होने की संभावना है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला जालोर में जेलपुरा बड़गांव नदियों की सिंचाई योजनायें बनी हैं।

जेलपुरा की सिंचाई योजना को नये डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।

बड़गांव योजना का काम ही अभी तक डी.पी.ए.पी. के अन्तगत स्वीकृत हुआ है। इसमें नदी पर पिक अप वियर जानकर नहर बनाई गई हैं। इस योजना से 1787 एकड़ भूमि को प्लावन मिलेगा। कार्य पूरी प्रगति पर है और इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा हो जावेगा। इस योजना से अगले वर्ष जल प्लावन सम्भव होगा।

(2) जी नहीं। अभी भी इन क्षेत्रों के काश्तकारों द्वारा इन नदियों का पानी नालियां बना कर खेतों को प्लावित करने के काम में लिया जा रहा है। उपरोक्त योजनाएं पूर्ण होने पर व्यापक रूप से जल प्लावन किया जा सकेगा।

(3) जी हां। वर्षा ऋतु में तो पानी गुजरात में ही जाता है। परन्तु रबी काल में काश्तकारों द्वारा अभी भी नालियां बना कर खेतों को प्लावित किया जा रहा है।

बड़गांव योजना से अगले वर्ष 1787 एकड़ भूमि को जल प्लावन सुविधा प्राप्त हो जावेगी व जैतपुरा योजना लगभग 12000 एकड़ भूमि को यह सुविधा प्राप्त होगी। इस योजना को वित्तीय अभाव के कारण अभी प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के पास विचाराधीन अपीलें

48. श्री रामसिंह कुड़ी (बायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के पास पेंडिंग अपीलों आदि के 1200 मामलों में से लग-

(118)

(श्री रामसिंह कुड़ी)

भग 900 मामले नागौर जिले के हैं ? यदि हां, तो पेंडिंग मामलों की जिलेवार 1-1-76 तक की संख्या दर्शाते हुये सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर को जिला मुख्यालयों पर कैम्प रख कर ऐसे विचाराधीन मामलों को निपटाने का आदेश दिये जाने में कोई आपत्ति है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर को जिला मुख्यालयों पर कैम्प रख कर पेंडिंग मामलों को शीघ्र निपटाने का आदेश देगी ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि नागौर जिले के लगभग 900 मामले राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के यहां विचाराधीन हैं ।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

लालसोट व बामनवास कस्बों में नगरपालिका बनाने का निर्णय

49. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.–

क्या राज्य सरकार ने जयपुर जिले के लालसोट व सवाई माधोपुर जिले के बामनवास कस्बों में नगरपालिकायें बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो कब से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

घोसुण्डा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. द्वारा दिया गया ऋण

50. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि घोसुण्डा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., घोसुण्डा जिला चित्तौड़गढ से श्री भूमटमल खटवानी ने 31-8-73 को रोकड़ पाना व बौण्ड नं. 19 पर अवैधानिक रूप से 6960) रु. का ऋण लिया है जो कि अभी तक जमा नहीं कराया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त श्री भूमटमल खटवानी के विरुद्ध उक्त सेवा सहकारी समिति के 2000) रु. आडिट में बकाया निकले हैं जो भी उसने आज जमा नहीं कराये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम सेवा सहकारी समिति की कार्यकारिणी ने दिनांक 12-7-75 को श्री भूमटमल खटवानी की कुर्की करके वसूली करने के लिए प्रस्ताव पास करके उच्चाधिकारियों को भेजा है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त श्री भूमटमल खटवानी से अभी तक यह रकम वसूल नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री भूमटमल खटवानी, घोसुण्डा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. द्

(सहकारिता मंत्री)

दिनांक 31-8-73 को समिति से 960 रु. स्वीकृत ऋण के रूप में तथा 6090 रुपये अनियमित रूप से बिना किसी स्वीकृति के ले लिए। यह रकम अभी तक जमा नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। श्री झूमटमल खटवानी के विरुद्ध पोसूण्डा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के 2000 रु. किसी भी आडिट वर्ष में बकाया नहीं निकलते हैं।

(3) विभाग को ऐसे प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं है।

(4) श्री झूमटमल खटवानी से प्रश्न सं. 1 में सबंधित रकम की वसूली नहीं हुई है। उसके बारे में उसके विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1955 की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है।

झालावाड़ जिले में जलाऊ लकड़ी की टालें

51. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में केवल झालरापाटन व झालावाड़ में बिक्री के लिए जलाऊ लकड़ी की टालें है?

(2) क्या यह भी सही है कि झालावाड़ में टाल शहर से दूर होने के कारण लकड़ी लाने में परेशानी व खर्चा अधिक होता है?

(3) क्या यह सही है कि इन दोनों टालों पर समय पर लकड़ी कोयला आदि उपलब्ध नहीं हो पाता है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त क्षेत्र के बड़े कस्बों जैसे खानपुर, भवानी मंडी, अकलेरा व बकानी, असनावर आदि में जलाऊ लकड़ी की टालें कब तक खोली जा रही हैं?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। झालावाड़ जिले में झालरापाटन के अतिरिक्त झालावाड़ एवं भवानी मण्डी में भी विभागीय टालें हैं।

(2) जी हां। नगरपालिका द्वारा चयनित स्थान शहर से एक तरफ पड़ता है।

(3) जी नहीं, इन टालों पर पर्याप्त मात्रा में लकड़ी व कोयला उपलब्ध है।

(4) भवानी मण्डी में पहले से सरकारी टाल स्थापित है। अन्य स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में लकड़ी, कोयला उपलब्ध न होने के कारण अभी सरकारी टाल खोलना संभव नहीं है।

अजमेर जिले की गृह निर्माण सहकारी समितियां

52. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में गृह निर्माण सहकारी समितियों का गठन हुआ? यदि हां, तो कितनी सहकारी समितियां बनाई गईं?

(श्री शंकरसिंह रावत)

(2) क्या यह भी सही है कि इन्हें ऋण की व्यवस्था करानी थी ? यदि हां, तो अब तक कितनी सहकारी समितियों को ऋण प्राप्त हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर जिले में गृह निर्माण सहकारी समितियों का गठन हुआ है। इस समय अजमेर जिले में 75 गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं।

(2) जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण की आवश्यकता थी उनके ऋण प्रार्थना बनाकर राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि., जयपुर को भिजवाये गये? अजमेर जिले की 18 गृह निर्माण सहकारी समितियों को 40.51 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है जिनमें से 9 समितियों को 13.16 लाख रुपये का ऋण वितरण किया जा चुका है।

तहसील दौसा में जयपुर के भू. पू. महाराजा की जमीन

53. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–**

(1) क्या यह सही है कि ख. नं. 519, 486, 482 रानी का बाड़ कस्बा दौसा एवं ख. नं. 484 बीड़ भण्डाना तहसील दौसा, जयपुर के भूतपूर्व महाराजा की निजी सम्पत्ति थी ?

(2) क्या कावेनेन्ट के अनुसार भूतपूर्व महाराजा को अपनी उक्त जमीन बेचने, बट पर वतलाने आदि के समस्त अधिकार प्राप्त थे ? यदि हां, तो क्या इस समझौते के अनुसार कागजात सरकारी में दुरुस्ती की गई ?

(3) क्या टिनेन्सी एक्ट की धारा 6 के अनुसार उक्त भूतपूर्व महाराजा के बाटेदार खातेदार हैं ?

(4) क्या राजस्थान लैण्ड एक्वीजीशन आफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट एक्ट की धारा 6 (1) के अनुसार भूस्वामी के खातेदारों को खातेदार माना गया है ?

(5) क्या राज्य सरकार ने भूतपूर्व महाराजा की उक्त भूमि पर काबिज खातेदारों को ही खातेदार मानने की नीति अपनाई है जो दिनांक 21–12–75 को अखबारों में प्रकाशित हुई है ?

(6) क्या उक्त बीड़ व बाड़ में काश्तकारों ने उक्त भूमि पर गेहूँ पैदा कर लेवी भी जमा कराई है ?

(7) क्या काबिजों को खातेदार मान कर तत्संबंधी दुरुस्ती कागजात में की जावेगी ?

उत्तर

भूतपूर्व महाराजा जयपुर की भू-सम्पदा को अवाप्त करने सम्बन्धी मामला जिलाधीश, जयपुर के सम्मुख विचाराधीन है। हाल ही में सम्बन्धित पक्षकारों से बहस ली गई है, क्योंकि मामला सब-ज्यूडिस है अतः निर्णय से पूर्व प्रश्न का उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है।

राजसमन्द नगरपालिका थ्री ह्वीलर स्कूटर

54. श्री नाना लाल (राजसमन्द) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज समन्द जिला उदयपुर नगरपालिका को समाज कल्याण विभाग द्वारा थ्री व्हीलर स्कूटर भंगी कष्ट निवारण हेतु अनुदान के रूप में दिया गया ?

यदि हां, तो क्या जिस हेतु स्कूटर दिया गया उसको उसी काम में लिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्कूटर खराब हालत में नगरपालिका नाके के बाहर पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो इसको किसने खराब किया और यह किस कार्य में खराब हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की सम्पत्ति स्कूटर का नाजायज उपयोग कर क्षति पहुंचाई गई है ? यदि हां, तो क्या उस अधिकारी से द्वारा जुर्माना वसूल करने का राज्य सरकार इरादा रखती है जिसने कि उक्त स्कूटर को क्षति पहुंचाई है ?

उत्तर

(1) जी हां, स्कूटर के उपयोग के बारे में अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा चूंकि इसी प्रश्न को लेकर एस. डी. ओ. के यहां जांच चल रही है।

(2) यह स्कूटर नाके नं. 2 के बाहर खराब हालत में पड़ा है। शेष प्रश्नों की जांच भी एस. डी. ओ. के यहां चल रही है। जांच का निर्णय आने तक निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है।

(3) इस मामले की जांच एस. डी. ओ. के द्वारा कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

लाडनूं तहसील की लघु सिंचाई योजना

55. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं तहसील जिला नागौर के लिये एक लघु सिंचाई योजना बनाई गई थी ? अगर हां, तो यह योजना लम्बे समय से सरकार के पास किस कारण पड़ी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना राष्ट्रीय बचत बैंकों के कृषि हेतु ऋण देने के लिये विशेष तौर से बनाये गये निगम द्वारा बनाई गई थी और इसको शीघ्र प्रारम्भ करने की सिफारिश राज्य सरकार को की गई थी ? अगर हां, तो इसकी क्रियान्विति में क्या बाधा है ?

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर के लिए कृषि वित निगम द्वारा एक लघु सिंचाई योजना तैयार की गई थी।

(कृषि मंत्री)

इस योजना को कृषि पुनर्वित्त निगम से पुनर्वितीयन करवाने के लिये कृषि वित्त निगम ने स्वीकृति चाही थी जो कृषि पुनर्वित्त निगम ने नहीं दी। अतः राज्य सरकार के पास पड़ी रहने का प्रश्न ही नहीं है।

(2) जी हां। उक्त योजना कृषि वित्त निगम द्वारा तैयार करके कृषि पुनर्वित्त निगम को स्वीकृति के लिए भेजी गई थी जिसको कृषि पुनर्वित्त निगम ने स्वीकृति नहीं दी है।

शुद्धि-पत्र

दिनांक 11 मार्च, 1976

क्र.सं.	स्तंभ संख्या	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5
1.	43	ऊपर से 8	अर	आप
2.	53	नीचे से 10	देखनें	देखने
3.	59	ऊपर से 1	वेता	देता
4.	61	नीचे से 6	अपने	आपने
5.	64	,, 9	ब्योरोक्रेसी	ब्यूरोक्रेसी
6.	66	,, 12	कुलनक	कुलक
7.	69	,, 16	स	इस
8.	75	ऊपर से 10	ſs	is
9.	76	,, 1	हुण्डा	हाण्डा
10.	76	नीचे से 11	अन्य	जन्य
11.	79	ऊपर से 7	छाहते	चाहते
12.	83	नीचे से 11	को	कोई
13.	93	ऊपर से 9	कर	का
14.	105	नीचे से 11	पस	यस
15.	109	ऊपर से 3	बड़ा	बढ़ा
16.	113	,, 7	तब	जब
17.	116	नीचे से 17	में में	में
18.	136	,, 1	मज	मजदूर
19.	169	,, 9	बहार	बाहर
20.	179	ऊपर से 12	नही	नहीं आई
21.	184	,, 15	अप	आफ
22.	193	,, 9	मे	नेता
23.	199	,, 8	रोका	न ही रोका